LOK SABHA DEBATES

(Part I -- Proceedings with Questions and Answers)

Friday, November 29, 2019 / Agrahayana 8, 1941 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, November 29, 2019 / Agrahayana 8, 1941 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

….	1
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 161-168, 171 & 173)	1A-30
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 169-170, 172 & 174-180)	31-50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 1841-2070)	51-280

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Friday, November 29, 2019 / Agrahayana 8, 1941 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, November 29, 2019 / Agrahayana 8, 1941 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURMENT MOTION	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281-86**
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	**287**
LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE	**287**
STANDING COMMITTEE ON LABOUR **1st to 3rd Reports**	**288**
BUSINESS OF THE HOUSE	**288-90**
ELECTION TO COMMITTEE **Indian Council of Medical Research**	**291**
BILL INTRODUCED **Arms (Amendment) Bill**	**292**
QUESTION OF PRIVILEGE & PERSONAL EXPLANATION	**293-97 & 300-08 & 316**
OBSERVATION BY HON'BLE SPEAKER	**310**
SPECIAL MENTIONS	**298-99 & 309-15 & 317-350**

RESOLUTION RE: CONSTRUCTION OF CANALS THROUGH KEN-BETWA RIVER LINKING PROJECT TO OVERCOME THE PROBLEM OF WATER SCARCITY AND STRAY COWS IN THE BUNDELKHAND – (Contd.- Inconclusive) **351-74**

Shri Dushyant Singh **351-54**

Shri P.P. Chaudhary **355-57**

Shri Bhagirath Chaudhary **358-61**

Shri Guman Singh Damor **362-65**

Shri Janardhan Mishra **366-69**

Shri Ritesh Pandey **370-72**

Shri Hanuman Beniwal (Speech unfinished) **373-74**

xxx

(1100/CS/AK)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, कल विपक्ष के सारे एमपीज ने आपसे यह माँग की थी कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी के खिलाफ जिस तरीके से घटिया बयान सदन के अंदर पेश किया गया है, इसने हम सबकी मर्यादा को ठेस पहुँचायी है और खासकर आपको भी, क्योंकि आप सदन के, हमारे कस्टोडियन हैं। सदन के अंदर जो कुछ भी होता है, उसका असर इस कुर्सी पर जरूर पड़ेगा, इसलिए हम लोगों का आपसे निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को कहूँगा कि वे प्रश्न काल के बाद 12 बजे सदन में आएं।

…(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ओले पड़े हैं और उससे फसलों को बहुत नुकसान पहुँचा है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए। मैंने आपको बोल दिया है। आप बैठ जाइए।

क्वेश्चन नम्बर, 161, श्री सुनील कुमार पिन्टू।

(प्रश्न 161)

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब प्राप्त हुआ है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के बारे में उन्होंने अपने उत्तर में रेडियो, टीवी चैनल्स आदि का जिक्र किया है।

महोदय, आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं और मुझे लगता है कि पूरा सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी का या माननीय नरेन्द्र मोदी जी का सपना है कि दिल्ली से जो योजना चल रही है, वह योजना गाँव के सबसे निचले तबके के व्यक्ति तक पहुँचे। 'आयुष्मान भारत' जो माननीय प्रधान मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके प्रचार-प्रसार में कहीं न कहीं सरकार के स्तर पर कमी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 'आयुष्मान योजना' के अंदर आधार कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड में किसी के नाम में थोड़ा सा भी अंतर होने के कारण वे सेवा से वंचित हो जाते हैं। उनको यह कह दिया जाता है कि आधार कार्ड में आपका नाम कुमार की जगह प्रसाद है या अन्य कुछ है और उन्हें सेवा से वंचित कर दिया जाता है। क्या सरकार इसका प्रचार-प्रसार करेगी कि कैसे वे अपने नाम में सुधार कर सकते हैं, ताकि वे उस योजना का लाभ ले सकें या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।

इसके साथ ही साथ क्या नीचे के स्तर पर सांसद निधि से गाँवों तक प्रचार-प्रसार करने के लिए सरकार विचार रखती है, ताकि उसके माध्यम से गाँव के निचले तबके के व्यक्तियों तक सरकार की योजनाओं की विस्तार से चर्चा हो सके।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : सरकारी योजनाएं जो जनकल्याण की हैं, उनकी पहुँच सही लाभार्थियों तक हो और सबको उसकी जानकारी हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार से कार्यक्रम भी होते हैं और सभी प्रकार के इश्तिहार दिए जाते हैं। उसमें मूल मुद्दा लोक शिक्षण होता है। आपका जो सुझाव है, उसके दो हिस्से हैं। मैं हेल्थ मिनिस्ट्री से यह जरूर कहूँगा कि इस तरह से सुझाव आया है कि जिनको किसी छोटे कारण से 'आयुष्मान योजना' में कार्ड नहीं मिला है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, वे उसका इश्तिहार दे दें। विभिन्न मंत्रालय जो इश्तिहार देते हैं, हम उसे छापते हैं। हमारा काम वह है और इसलिए उस संबंधित मंत्रालय को मैं आपका सुझाव जरूर दूँगा।

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): महोदय, मेरा एक दूसरा भी सवाल था। माननीय मंत्री जी, आपने कहा था कि दो पहलू आए हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दो प्रश्न एक साथ पूछ लेते हो।

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): महोदय, मंत्री जी ने हमारे एक ही प्रश्न का जवाब दिया है।

माननीय अध्यक्ष : एक ही जवाब दिया है। वे एक जवाब और दे देंगे।

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि क्या नीचे के स्तर तक सांसद निधि के थ्रू प्रचार-प्रसार करने का सरकार का कोई विचार है, ताकि गाँव के नीचे के तबके तक इसकी खबर पहुँच सके।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : महोदय, आज एमपीलैड में प्रसिद्धि के लिए या योजना पहुँचाने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एमपीलैड के बारे में नियम ग्रामीण विकास मंत्रालय संचालित करता है, प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन करता है। मैं उनको भी यह बताऊँगा कि इस तरह से सुझाव है और क्या एमपीलैड का भी इसमें उपयोग हो सकता है। मैं आपकी यह भावना उन तक पहुँचा दूँगा।

(1105/CS/SPR)

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि दिसम्बर, 2018 तक जो एनडीए/भाजपा की सरकार है, उसने 5,245.73 करोड़ रुपया इश्तिहारों पर खर्चा था, चाहे वे अखबारों के इश्तिहार हों, चाहे चलचित्र के इश्तिहार हों या सोशल मीडिया के इश्तिहार हों। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता कि आपने कितना पैसा खर्चा था और उससे पहले हमने कितना पैसा खर्चा था। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या आपने ऐसा कोई कॉस्ट बेनीफिट एनालॉसिस करवाया है कि सरकार जो पैसा इश्तिहारों पर खर्च करती है, जो पैसा अखबारों को देती है, टेलीविजन चैनल्स को देती है, सोशल मीडिया को देती है, उसका सरकारी नीतियों के प्रचार-प्रसार में कितना असर पड़ता है? यह मेरा आपसे सवाल है।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : आपने यह बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पहले 5 साल में कितना खर्चा हुआ, अभी कितना हुआ, माननीय सदस्य वह नहीं पूछ रहे हैं। अभी हमने समाचार पत्रों के रेट्स भी बढ़ा दिए थे, तो सेंटीमीटर वाइज भी आंकड़े मौजूद हैं और वे दिए गए हैं। आपका जो सुझाव है, वह सही है कि एडवरटीजमेंट, यह कॉस्ट बेनीफिट एनालॉसिस हम करते हैं या नहीं, तो हमने तीन बदलाव किए हैं। आपने देखा होगा कि अभी हम थीमैटिक एडवरटीजमेंट्स दे रहे हैं। आप इस तरह से समझिए कि योगा डे के एडवरटीजमेंट में प्रीवेंटिव हेल्थ के जितने कार्यक्रम हैं, चार-पाँच मंत्रालयों के, आयुष मंत्रालय से लेकर बाकी मंत्रालयों के जो हेल्थ के कार्यक्रम होंगे, उन सबको भी एडवरटाइज करते हैं। एक-आधा पेज इश्तिहार का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो और ढंग से लोगों तक जानकारी पहुँचे, यह एक नया प्रयास है। माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है कि इसका भी कॉस्ट बेनीफिट एनालॉसिस लोगों तक कितना पहुँचता है और कितना परिणाम करता है, यह अच्छा सुझाव है।

(इति)

(प्रश्न 162)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आज पहली बार जवाब दे रही हैं, तो इनको धन्यवाद देना चाहिए।

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से पूर्ण संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरा एक पूरक प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, मुझे यह स्पष्ट करें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूरे देश में काम करती हैं और इनसे बहुत अधिक काम लिया जाता है। क्या इनका कोई जॉब चार्ट बना है? इसके साथ ही साथ इनके मान-सम्मान की स्थिति भी देश में बहुत गंभीर है। राजस्थान में तो ये परिस्थितियाँ हैं कि वहाँ के अधिकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को केवल अपना गुलाम समझते हैं। तरह-तरह के लगभग 7 डिपार्टमेंट्स का काम इनसे लिया जाता है। क्या भारत सरकार उनकी इज्जत, सम्मान और उनके जॉब चार्ट की बात करेगी?

सुश्री देबाश्री चौधरी : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी को अवगत कराना चाहती हूँ कि आंगनवाड़ी सर्विस में ऐसे जॉब चार्ट का प्रावधान है। जॉब चार्ट में कई सारे कार्य, जैसे परिवार कल्याण संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी और सेंसस संबंधी कुछ काम शामिल हैं। प्रत्येक बच्चे का वेट करना, मंथली रिकॉर्ड रखना, माताओं को हेल्थ और न्यूट्रिशन एजुकेशन देना, स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर पीएचई स्टॉफ की मदद करना, नॉन-फॉर्मल प्रीस्कूल एजुकेशन आयोजित करना, शिफ्टों में माताओं-बच्चों और परिवारों का सेंसस करना, इस तरह के बहुत सारे काम इनकी सर्विस में शामिल हैं।

(इति)

(1110/CP/SNT) (Page Nos. 5-6)

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नंबर 171 और 173 को भी इसके साथ लेते हैं।

क्वैश्चन नंबर 171 – श्री दीपक बैज।

(प्रश्न 171)

श्री दीपक बैज (बस्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न कुपोषण से संबंधित है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार 5 वर्ष की आयु वाले 35.7 प्रतिशत बच्चे कम वजन के और 38.4 प्रतिशत ठिगने तथा 58.5 प्रतिशत बच्चे खून की कमी से ग्रसित हो रहे हैं। वास्तव में कुपोषण देश के लिए बहुत गम्भीर समस्या है।

मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र से आता हूं। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर, ये कुछ ऐसे जिले हैं, जहां कुपोषण का बहुत ज्यादा प्रभाव है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि देश में कुपोषण से संबंधित सबसे ज्यादा प्रभावित टॉप 10 कौन-कौन से राज्य हैं, उन राज्यों में कुपोषण को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं तथा उन राज्यों में कब तक कुपोषण पर नियंत्रण होगा? जो आदिवासी और पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनके लिए केन्द्र सरकार की क्या विशेष कार्य योजना है? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं।

महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी): अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम अपनी सहयोगी मंत्री का अभिनंदन करना चाहूंगी कि आप सबके आशीर्वाद से उन्होंने अपना पहला जवाब सभा पटल पर प्रस्तुत किया।

सदस्य का विषय तीन भागों में आपके सामने प्रेषित हुआ है। एक, देश में टॉप 10 कौन से राज्य हैं, जो कुपोषित हैं? मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि सभी राज्यों में कुपोषण की चुनौती है। जिलेवार यह जानकारी राज्यों के सम्मुख प्रस्तुत होती है, लेकिन यह जानकारी ऐसी है, जो डायनेमिक है। मतलब कि कई बच्चे जो अति कुपोषित होते हैं, उन्हें 15 दिन के हस्तक्षेप में, जिनमें स्वास्थ्य संबंधी सेवायें, पोषण संबंधित सेवाओं के साथ-साथ जिलाधिकारी, आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर मिल कर महिला और बच्चे के स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं। इसलिए उनका जो मानक है या बेंचमार्क है, वह बेहतर होते हुए दिखता है। इसलिए उस डायनेमिक प्रोसेस को देखते हुए हमने एक एसएमएस सर्विस बनाई है जिसके अंतर्गत अगर बच्चा वेट में स्टैटिक रहता है अथवा अंडर वेट होता है, तो तुरंत माता पिता के लिए और फील्ड फंक्शनरी के लिए एसएमएस जेनरेट हो जाता है। महोदय, आपको जानकर खुशी होगी कि अक्टूबर माह में लगभग 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा ऐसे मैसेजेज़ देश भर में ऐसे माता-पिताओं को, फील्ड फंक्शनरीज को दिये गये हैं।

जहां तक ट्राइबल इलाके में विशेष चुनौती का इन्होंने उल्लेख किया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि कुपोषण की इस समस्या, इस चुनौती के साथ जूझने के लिए मात्र महिला, बाल कल्याण विकास मंत्रालय काम नहीं कर रहा है, बल्कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, वाटर सैनिटेशन का डिपार्टमेंट, भारत सरकार के 15 मंत्रालय, लेकिन साथ ही प्रदेश में ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कनवर्जन्स प्लान भी प्रस्तुत होता है। आपके प्रदेश से भी यह अपेक्षित रहता है। 27 प्रदेश अब तक ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक अपना कनवर्जन्स प्लान भारत सरकार को प्रस्तुत कर चुके हैं।

(इति)

(प्रश्न 173)

SHRI ACHYUTANANDA SAMANTA (KANDHAMAL): Hon. Speaker, Sir, I humbly thank the hon. Minister, Madam, for mentioning very clearly in Question no.173, schemes like, Anganwadi Poshan Abhiyan, Scheme for Adolescent Girls, Creche scheme, Child Protection Scheme, Mid-Day Meal Scheme, Ujjawala Scheme, and the POCSO Act.

Still, I am interested to know, through you, hon. Speaker, Sir, from the hon. Minister, the special initiatives taken by the Government for tribal children to mitigate problems like child marriage, malnutrition, trafficking, and dropouts, which are rampant in the tribal communities. I would also like to know from the hon. Minister the steps taken for the welfare of children with disabilities.

(1115/NK/GM)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Hon. Speaker, Sir, as the hon. Member has enunciated a variety of challenges, I would like to highlight that we, in conjunction with the Ministry of Social Justice, Ministry of Tribal Affairs, and Ministry of Human Resource Development, are trying to serve the interest of the children of our country. When it comes to trafficking, I am happy to share with the House that in conjunction with the Ministry of Home Affairs, we have recently sanctioned anti-trafficking units to help protect our children and women in all districts across the nation. One of the first such initiatives is under the Nirbhaya fund. Similarly, when it comes to education, given my past experience within the Department, I can highlight that the Ministry of Human Resource Development ensures that the drop-out rates or learning solutions which are needed for these children irrespective of whether they are tribals or children from other localities are monitored at the school level. In fact, in NCERT, we have ensured that learning outcomes are defined and we encourage parents to ensure that their children meet those learning outcomes. It is something in which parents can also be involved. …(*Interruptions*) *Divyang* is an issue that a senior Member has right now highlighted. I would like to highlight that efforts through the Ministry of Social Justice are under way to help serve our children better in that particular segment. But I can also share with the hon. Member that the ICDS scheme is going to be under review with the NITI Aayog. One of the issues that I hope to engage upon is special nutritional needs or special vocational needs and early childhood learning needs of those who are in the *divyang* category.

SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): Hon. Speaker, Sir, lakhs and lakhs of anganwadi workers and helpers are working throughout the country for a meagre honorarium. The scheme is under the Integrated Child Development Scheme introduced by the Government of India. The workers and helpers are working in anganwadi from 9 am to 5 p.m. They are working with dedication. I would like to ask the hon. Minister whether the Government of India has enhanced the honorarium for workers and helpers and if there is any proposal before the Government of India to make these helpers and workers permanent.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I would like to highlight to the hon. Member that the issue of permanency and job description of anganwadi workers was brought to the notice of the hon. Supreme Court. In a judgement given in the year 2006, it was settled by the hon. Supreme Court that this is not a permanent job. In fact, an honorarium is well deserved by the anganwadi workers. But, to ensure that we help protect their interest, there are certain additional facilities. While money has been enhanced to Rs. 4500, we encourage States to top- up. We also additionally give a 180-day paid absence/maternity leave for those who are undergoing pregnancy. We encourage and give them cover under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Jeevan Jyoti Bima Yojana, and the latest Pension Yojana that has been started by the hon. Prime Minister with regard to a pension fund for those who seek economic benefits once they retire. Those elements are also being taken care of with regard to anganwadi workers.

(ends)

(प्रश्न 163)

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): अध्यक्ष महोदय, मैं बिना किसी भूमिका के आदरणीय मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहती हूं। देश में होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा और प्राकृतिक चिकित्सा में प्रैक्टिस करने वाले आयुष चिकित्सकों की मध्य प्रदेश सहित राज्य व संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या की क्या स्थिति है? क्या आदरणीय मंत्री जी इसे बताने की कृपा करेंगे?

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ऑल इंडिया लेवल पर और मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या के बारे में पूछा है। प्रश्न के आंसर में एक एनेक्चर लगा हुआ था। आयुष पैथी के जरिए जो आयुर्वेद किए हैं। मध्य प्रदेश में 46, 981 डॉक्टर्स आयुर्वेद के हैं, 1,783 डॉक्टर्स यूनानी के हैं और नेचुरोपेथी के 15 डॉक्टर्स हैं।

(1120/SK/RSG)

होम्योपैथी के 18,284 डॉक्टर्स हैं, कुल मिलाकर 67,060 डॉक्टर मध्य प्रदेश में सभी पैथी के हैं। देश में संख्या आठ लाख के आसपास है। मैं डिटेल में कह सकता हूं कि 7,99,879 डॉक्टर पांच पैथी में हैं। मेरे ख्याल से यह इन्फार्मेशन यहां दी हुई है।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से लिखित में उत्तर दिया है और सदन में भी उत्तर दिया है। प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की स्थापना राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत की जाती है। यह सवाल राज्य से जुड़ा हुआ है, परंतु फिर भी मैं आपकी अनुमति से पूछना चाहती हूं कि क्या आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की स्थापना करने का कोई विचार है?

श्री श्रीपाद येसो नाईक :माननीय अध्यक्ष जी, हैल्थ राज्य का सब्जैक्ट है। आयुष मंत्रालय में आयुष नेशनल मिशन के जरिए सैंट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स के तहत हम फाइनेंशियल मदद करते हैं। मध्य प्रदेश के लिए 50 बैड अस्पताल की स्कीम है, इसके तहत हमने चार 50 बैड के अस्पताल दिए हैं। अस्पताल कौन सी कैटेगिरी में चाहिए, आयुर्वेद, होम्योपैथी, युनानी या नेचुरोपैथी में चाहिए, यह राज्य सरकार तय करती है। जब राज्य का प्रपोजल आता है तो हम उसी तरह से सहायता देते हैं।

मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं, यदि वहां नेचुरोपैथी अस्पताल चाहिए, तो राज्य सरकार को प्रपोजल देना होगा। इसका कम्पोनेंट है कि हम 60 परसेंट फंडिंग राज्य को देते हैं और राज्य सरकार 40 परसेंट देती है और जमीन का बंदोबस्त भी करती है। राज्य सरकार से प्रपोजल आने के बाद हम तुरंत एप्रूव करते हैं।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you, Mr. Speaker.

As we all know, the big challenge faced by Ayurveda in our country today and by AYUSH generally, but particularly Ayurveda, is the lack of adequate research and documentation. In the western world, AYUSH tends to get discredited on the argument that it is not based on scientific principles, that there is not enough case studies documented, and enough conclusions are not drawn.

In this House, previously we have agreed that the nation needs a serious research university in Ayurveda. There are some Ayurvedic treatments that are actually getting extinct. Ottamooli in Kerala, a miraculous on-time medication, is recorded as having cured many illnesses but there is no one left to research it.

You may remember, Mr. Minister, when you came to my constituency and we opened together the new wing of an Ayurveda building, I had requested you publicly and you had publicly responded, that you would upgrade the Ayurveda college and the institute to a national research university for Ayurveda in Thiruvananthapuram. This was in 2018, Sir, during your last visit to my constituency. The Government has done nothing about it. It is not in the Budget this year.

We all understand Ayurveda is our nation's pride. It is not just a constituency matter; it is something that the whole country needs, to establish the credibility of Ayurveda on the global stage. Can I please request you, Sir, to take steps to upgrade the Ayurveda Medical College into a national research university in order to get Ayurveda back on the footing we need?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की रिक्वेस्ट बिल्कुल सही है, वर्ष 2018 में हमने इस पर चर्चा की थी। आयुष मंत्रालय रिसर्च में आगे जा रहा है। हमने आयुष के अलग-अलग विंग्स के लिए अलग-अलग रिसर्च सैंटर्स बनाए हैं। आपने कहा है कि यहां अस्पताल है और यहां आयुष रिसर्च युनिवर्सिटी होनी चाहिए। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि आयुष मंत्रालय की ओर से इस प्रपोजल पर निश्चित तौर पर विचार किया जाएगा। इसके लिए जो सहयोग राज्य सरकार से चाहिए, वह सहयोग मैं आपसे मांगता हूं, आप राज्य सरकार से कहें कि वह सहयोग करे ताकि तुरंत हम आगे बढ़ सकें।

(1125/RK/RPS)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, AYUSH means *Ayurveda*, Yoga, Unani and Siddha and Homeopathy. The National Institute of Homeopathy is situated in Kolkata. One Unani medical college along with the hospital is there in my constituency. Health is a State subject and I would say that AYUSH systems of healthcare have not been given much importance by the State Governments. It is always considered as a side medical care and not as a primary medical care system. I would like to know whether the Central Government can directly send assistance to the AYUSH hospitals in the States. I used to be the Minister of this Department and at that time there was a move to consider AYUSH in a different way. Can the Central Government consider

taking up the modern medicine and AYUSH together to make this system of healthcare more viable for the welfare of the patients?

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, आप जानते हैं कि आयुष मंत्रालय पांच साल पहले ही बना है। पहले आयुष मंत्रालय हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ था। इन पांच सालों में हमने जिस तरह से प्रयास किए हैं, आप सभी जानते हैं, यह सब करते-करते सेंट्रली स्पाँसर्ड स्कीम्स के जरिए, हमने को-लोकेशन स्कीम डायरेक्ट शुरू की है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनमें को-लोकेशन में हमारे डाक्टर बैठते हैं, वहां वे पेशेंट्स का चेक-अप करते हैं, उनका इलाज करते हैं और हम उसके लिए बहुत सा फण्ड देते हैं। उसके बाद, हमारे डाक्टर्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी हमारे डाक्टर्स बैठते हैं, लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने बलबूते पर खड़ा रहे। मैं सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से विनती करता हूं, हम जिस तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं, वह भी करते हैं, जैसे हमने अभी डिक्लेयर किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक 50 बेडेड हॉस्पिटल आपको दे देंगे। आज मुझे यह बताने में खुशी नहीं है कि पूरे देश में से 91 प्रपोजल्स आए हैं। इसके लिए हम स्टेट्स को ही 60 प्रतिशत फण्ड देते हैं, यदि हर जिले में हॉस्पिटल हुआ तो आहिस्ता-आहिस्ता लोगों की रुचि आयुष के प्रति बढ़ेगी और इलाज भी चलेगा।

माननीय अध्यक्ष: बहुत बढ़िया है।

श्री श्रीपाद येसो नाईक: मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसको ऐसी जगह तक पहुंचने में कुछ और साल लगेंगे, जब तक हम डायरेक्ट गांव-गांव तक नहीं जाएंगे, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, हम इसमें थोड़ा बहुत पीछे रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष: आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

श्री श्रीपाद येसो नाईक: धन्यवाद।

(इति)

(Q.164)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, this Question relates to the Central Government hospitals in general and I had asked for a specific hospital in Delhi. The Minister has given a very elaborate answer. I would like to go to the broader picture that is there in this country.

It is a well-known fact that doctors and nurses do their courses from Indian medical institutions. Many of the doctors and nurses go abroad due to lucrative pay packages and better health infrastructure. Through you, Sir, I would like to know from the hon. Minister the steps being taken to encourage such talented doctors and nurses to stay and work in our country.

DR. HARSH VARDHAN: Sir, in response to the Question, in the answer itself I have mentioned a number of points about how the concern for this particular issue has been taken care of by the Government. I would like to inform the hon. Member, through you, Sir, that we are encouraging doctors in every form. As we have mentioned in the answer also, the UPSC takes a lot of time to select the doctors and other medical staff.

(1130/PS/IND)

The contractual appointments for doctors as well as nurses, to fill up the vacant positions, is taken care of well in time. Even for doctors who are not happy with the emoluments that they would normally get in the State Government Medical Services, through the National Health Mission, we have authorised the State Governments to pay salaries as quoted by the doctors. The Government of India supports the State Governments to ensure that every position of doctors and other staff is filled up in the whole country. In the reply itself, I have told you that in all the situations -- whether it is for fellowships, whether it is for leaves, whether it is for various types of facilities, or whether it is for their emoluments -- the Government of India has been very liberally supporting and helping the doctors as well as the nurses. I would say that virtually there is no significant shortage of any of them in the country.

As such, there is no doubt about the fact that many doctors and nurses definitely prefer to go outside the country and there is no mechanism by which we can forcefully stop them from leaving the country. But we have created enough significant mechanisms for them to have jobs in the country, where their needs are taken care of in the best possible manner.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप संक्षेप में प्रश्न पूछेंगे, तो मंत्री जी संक्षेप में उत्तर देंगे।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The hon. Minister, of course, has said that adequate steps are being taken to retain medical doctors and nurses in our country. But being a doctor himself, I am sure that he is aware of the World Health Organisation's report relating to the doctor-patient ratio. The WHO, with regard to the doctor-patient ratio, recommends a ratio of one doctor for 1000 patients, while India has one doctor for 10,189 patients. This is the gap which we have to bridge. Therefore, I would say that it is not adequate. Maybe the sanctioned strength is being filled up to a great extent, but the gap that the WHO has stated, is very glaring before us.

My question to you is this. A large number of incidents are happening where fear has creeped into the doctors and also among other medical staff. What are the steps that the Government is taking to give adequate protection to the professionals who are working in the medical units?

DR. HARSH VARDHAN: There are two parts of the question that he has asked.

First of all, I think, I have elaborated it on a number of occasions, when we passed the National Medical Commission Bill also, that the Government has very dynamic plans to improve the number of doctors that are produced in the country in the next couple of years. As you have seen that in the last five years, over 29,000 MBBS seats and over 17,000 P.G. seats have been increased. Right now, we are in the dynamic process of establishing 82 plus 75 medical colleges -- 82 was proposed five years back and 75 have been proposed now. It is a dynamic list of 175 medical colleges, where the district hospitals are being converted into medical colleges. For the PG also, we have relaxed the norms. For the creation of a new medical college also, we have relaxed the norms. We are hopeful that in the next five to seven years, we would be able to ensure that the number of doctors in the country is as per the WHO's standards.

Now, I come to the second part of your question. You have said that there are a lot of such cases. There is no doubt about the fact that there is a lot of violence against the doctors and also against other staff working in the hospitals.

(1135/RU/ASA)

In fact, through the Clinical Establishment Act and other laws, some States have made some laws to give protection to doctors and other related health professionals. Similarly, right now, we are in the process of discussion on whether a Central Act in this direction could be feasible which could really help the doctors apart from the laws being enacted by the State Governments.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, there is a huge supply and demand gap in our medical sector, specially as regards the issue that has been raised by Shri Bhartruhari Mahtab also. Do you have any perspective plan to address this supply and demand gap? How many doctors are we producing in our country per year? What is our target vis-a-vis the production of doctors in our country?

Secondly, what is the cost being borne out by the tax payers of our country who help to produce doctors in terms of subsidy and other amenities, that is, the cost per doctor being meted out by the tax payers?

In page No. 3 of the reply given by the hon. Minister, it is stated as:

"(i) The superannuation age of CGHS doctors and dental doctors working under the Ministry of Health and Family Welfare has been enhanced to 65 years.

(ii) Enhancement of age limit for appointment/extension/re-employment against posts of teachers/Dean/Principal/Directors in Medical Colleges up to 70 years."

Sir, why is there this kind of a dichotomy? You know that old horse is best to ride, old wood is best to burn, old wine is best to drink and old doctor is best to be treated. So, what is your expectation?

DR. HARSH VARDHAN: Sir, the hon. Member has raised many issues through a single supplementary. We know that there are about 80,000 MBBS seats in the country right now. So, roughly, you can say that that is the real number of doctors who will be coming out of the Medical Colleges, be they from Private Medical Colleges or Government Medical Colleges. Similarly, I also mentioned, in response to the supplementary put by Shri Bhartruhari Mahtab, that we are in a very dynamic process. I feel proud in saying that under the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, the expansionist programme that has been

executed and planned for prospective future is historical. At a particular time, there has been development of 157 Medical Colleges and 22 All India Institutes of Medical Sciences in the country. Then, of course, there are other developments happening on the cancer front and other fronts. So, we have very actively and very dynamically diagnosed the problem and as I said, in the next five to seven years, we are sure that we will not have any shortage of any nature whether they are undergraduate or postgraduate doctors. This is one part of it.

As regards the second part of the supplementary on whether any calculation has been made or not, I do not think there has been any calculation about it because a huge amount of money has been spent on the All India Institutes of Medical Sciences and the Medical Colleges. In comparison to that amount, the fees that is charged from an MBBS student in a Government Medical College is almost negligible.

(1140/KKD/VB)

So, the Government spends a lot of money on producing these doctors, and that is why, we always appeal to the doctors that they have to return back support of the Government to the society.

So, as such, I do not think, there is any calculation about how much money is spent. But it is a huge amount of money that the Government spends. The Government is always liberal in supporting the medical education. The very fact that it has formed the National Medical Commission now, with exhaustive plans to improve the standards of medical education in MBBS as well as in Post-Graduate Courses is itself an indication; and it speaks volumes about the commitment of this particular Government.

Sir, he asked one more thing …(*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): यह आपके जवाब में पेज नम्बर तीन पर लिखा है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, इस तरह से फिर 30 मिनट लग जाएंगे।

…(व्यवधान)

DR. HARSH VARDHAN: Yes, yes. When this age was revised from 60 to 65; and for the Head of the Institution from 65 to 70, I think, it was because of the very fact, which the hon. Member himself said that as the doctors grow older, they are more experienced, they have more information, they are more knowledgeable and they can deliver better. That is why, the age limit has been

increased from 60 to 65; and for some of the higher positions like Head of the Departments, to 70.

Sir, we will keep his suggestion in mind. In future, if there is a need and if it has to be improved further, we can think about that.

(ends)

(Page Nos. 17-18)

(प्रश्न 165)

माननीय अध्यक्ष: आप सभी सदस्यों को इंक्वायरी करनी हो, तो आप मंत्री जी के पास जाकर तसल्ली से इंक्वायरी करें। आप पूरा समय दें, मंत्री जी भी आपको पूरा समय देंगे।

अभी प्रश्नकाल में हमें आगे के प्रश्नों को लेना है।

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग 'ख' और 'ग' के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि मोरारजी देसाई योग संस्थान की तर्ज पर बिहार में क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जब सरकार यह स्वीकार करती है कि आरामपरस्त जीवनशैली से लोग रोगग्रस्त हो रहे हैं, तो ऐसे में योग केन्द्र खोलने का औचित्य सिद्ध होता है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार योग को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार में योग केन्द्र की स्थापना का विचार करेगी?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि बिहार में मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग है और बिहार में ही एक योग केन्द्र स्थापित करने की माँग आई थी। हम डायरेक्टली इस तरह के इंस्टीट्यूट की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा है कि अभी तक हमारी इतनी ताकत नहीं हुई है, आयुष मंत्रालय की जो सेन्ट्रली स्पांसर्ड स्कीम है, जैसा कि मैंने कहा कि उसके तहत हम 50 बेडेड हॉस्पिटल देते हैं। योगा के सेन्टर के लिए भी इसी 50 बेडेड हॉस्पिटल में एड करके प्रपोजल राज्य सरकार से आ सकता है। हम जो बजट राज्य को देते हैं, आयुष मंत्रालय से जो बजट जाता है, उसके लिए जो 20 परसेंट फ्लैक्सिबल फण्ड रहता है, उसी फण्ड से सरकार वहाँ योग सेन्टर बना सकती है।

मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूँ कि इस तरह के जो प्रपोजल्स हैं, उसे आप भिजवा दीजिए, हम वह देने के लिए तैयार हैं।

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): योग भारत के ऋषियों, मनीषियों की देन हैं। आज पूरे विश्व ने इसे स्वीकार किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी की पहल पर पूरे विश्व ने इसे मंजूर किया है, इसे स्वीकार किया है।

पूरा विश्व अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। केवल अनुशंसा से काम नहीं चलेगा। इसके प्रचार-प्रसार के लिए यह आवश्यक है कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के पाठयक्रम में योग को व्यापक रूप से पढ़ाया जाए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पाठयक्रम में इसे पढ़ाने के लिए क्या सरकार कोई विस्तृत योजना लाएगी?

(1145/KDS/RCP)

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक प्रश्न पूछा है। हमारे प्रयास अभी थोड़े सफल हुए हैं और स्कूल एजुकेशन में योग को प्राथमिकता देने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फिजिकल एजुकेशन में योग का समावेश किया गया है। फर्स्ट क्लास से दसवीं क्लास तक फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट कम्पल्सरी है, जिसमें योग का समावेश किया गया है। साथ ही योग को 5वीं कक्षा से न करके 6ठी कक्षा से पढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

(इति)

(प्रश्न 166)

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न नैशनल कोस्टल मिशन के बारे में है। पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट तटीय क्षेत्र में क्या होते हैं, जिसके कारण वहां के लोगों के रिहैबिलिटेशन के संबंध में यह प्रश्न था। मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में बताया कि इंटीग्रल कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में 1400 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन इनके उत्तर में यह लिखा गया है कि तीन राज्यों पर यह एसेसमेंट स्टडी किया गया है और रिहैबिलिटेशन का कार्यक्रम तीन राज्यों में किया गया है। इस क्षेत्र में 9 राज्य और कुछ यूनियन टेरिटरीज आती हैं, जिनमें 6100 किमी का लंबा तटीय क्षेत्र है। माननीय मंत्री जी कृपया यह बताने की कृपा करें कि बाकी राज्यों में कब प्रावधान करेंगे और इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: माननीय अध्यक्ष जी, श्री मनोज कोटक मुंबई से आते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सी लेवल राइज़ की क्या स्थिति है। मुंबई के बारे में सवा सौ साल का अध्ययन किया गया है। इसमें हर साल .74 मिली मीटर सी लेवल राइज़ होता है, इसलिए एकदम से अनावश्यक डर पैदा करने की जरूरत नहीं है। फिर भी, वहां जो कम्युनिटी रहती है, उसका resilience तैयार करने की जरूरत है। जैसा कि आपने अभी पूछा- ग्रीन क्लाइमेट फंड के द्वारा 800 करोड़ रुपये की एक नई योजना हम महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में शुरू कर रहे हैं। It is to build climate resilience among the coastal communities. हम यह काम कर रहे हैं।

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न सप्लिमेंट्री प्रश्न भी है।

माननीय अध्यक्ष: आपके प्रश्न का उत्तर मंत्री जी ने दे दिया है। श्रीमती कनिमोझी जी।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, the Minister has said that they have launched the Integrated Coastal Zone Management Project in Gujarat, Odisha and West Bengal. I am happy to know about that but what I would like to ask him is this. Tamil Nadu has a very large coastal area and we are suffering to a great extent because of erosions, salt water intrusion into the ground water and the flooding of coastal habitats. We are losing villages overnight despite having small groins to protect villages and they really do not help.

What long-term projects do you have? Have you done an impact study in Tamil Nadu?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: We have the National Institute of Coastal Zonal Management, which has a very good lab, in Chennai itself. I will request the Members also to sometimes visit that Institute to see how we have mapped 7500 kilometres of coastline including islands' coastline with nine-centimetre resolution through aerial photography of all the coasts with satellite and manually

confirming. That is a wonderful centre; it is situated in the University. Everybody should visit because it is a great help.

In Tamil Nadu, for each State, there are programmes. So, we are helping out all the States concerned. Regarding green infrastructure, the good point is what we are creating. In Lakshadweep, we have been able to create coral garden. In Tamil Nadu also, mangroves have grown by 500 kilometres. New plantation has happened in 1600 hectares. There is coral transplantation of 1200 square metres; there is shelterbelt plantation of 900 hectares.

(1150/SMN/SJN)

I will give all the information and about all the schemes relating to Tamil Nadu. Let me also clarify that there is no such report and that it is not a fact that villages are sinking into the sea.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I have seen in my Constituency. …(*Interruptions*)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: You give me the details. I will send a special team there. In Kerala, there was an issue pertaining to Munroe island where I sent a team and it was found that it was not related to sea level rise. It was related to some other issue and not related to sea level rise. But you send me the information and I will send a team.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, this is a very important question regarding the Coastal Zone Protection and the Coastal Zone Management. The hon. Minister has rightly said that a National Coastal Mission has been constituted and a National Action Plan on Climate Change is there.

The very important fact that is to be noted is the coastal erosion. As Kanimozhi Ji has just rightly stated, I can very well cite you in my Kollam Constituency which is a coastal area - 2-3 kilometres of the coastal area has already been eroded. We can see it with our naked eyes. There is no need for any scientific evaluation. We can very well experience with our own eyes that 2-3 kilometres have been eroded in Eravipuram, in Alappad, in Chavara and in most of the parts of my Constituency.

My specific question to the hon. Minister is this. There is a National Coastal Mission Plan. Unfortunately, there are no special measures to avoid this coastal erosion. There are only groins. I know that groins are not scientifically good. If you put some groins in a particular area, then, the coastal

erosion will take place on the other side. We have been experiencing this thing also. So, some research and some new device has to come. Till then, coastal zone protection is done by constructing groins and sea-walls. But there are no funds.

Mr. Speaker, Sir, you may kindly see. There are no funds. Till 12th Finance Commission, there was no earmarked funds to award for the coastal protection and for the construction of a sea-wall. I want to know whether the Government will earmark a special allocation because it is the boundary of the country. Our sea is the boundary of our country. Just like we are protecting our boundaries in the hilly areas, whether the Government will consider the sea as boundary and a particular amount or a specific amount will be awarded so as to address this problem?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: He has asked a good question. We have an Integrated Coastal Zone Project for all the 13 coastal states. Now, we are launching phase-II which will have a budget of Rs. 5,600 crore. In that, all those measures which were mentioned by you will be included.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका यह सवाल अच्छा है। आप इस पर लिखकर दे दीजिए, मैं उस पर विचार करूंगा।

(ends)

(Q.167)

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): This is an issue pertaining to the entire country and I am sure that every Member can relate to it. I see the answer. It says the ban on toxic materials or ganesh idol immersion during *Ganesh Chaturthi* has been put in place in 2010. It has been nine years. I am very sure that every Member here can vouch with me that there is not a single year that goes by without the immersion of toxic idols into various waterbodies.

I would like to have an answer from the Minister when it comes to environment, somehow we seem to be taking it very lightly. When it comes to national security, we do not do guidelines or awareness activities or when it comes to drugs, we do not do awareness activities or guidelines but when it comes to environment, somehow the ban is not seriously implemented and I do not know how long we can go on with this. I would like the Minister to state if there is a ban or if they are strictly going to implement this, I hope at least from next year onwards, none of us is going to see the immersion of toxic idol in any of the waterbodies.

(1155/MMN/GG)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: You see, the Ministry has issued guidelines. The States are acting, and more importantly, public is responding. Now, people create many special tanks where they immerse it, and they do not immerse it in the river or sea. Second, a good thing that is happening is that now people are not using plaster of Paris but mud and soil, and they create natural idols.

As far as paint is concerned, now there is more demand for green paints, and, therefore, we are moving in the right direction. Every year we make campaign for creating awareness among people and we are appealing to them well in advance of the festivals.

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): In India, we are proud of the fact that we can send a rocket to the Moon but I do not understand why our technical institutions cannot come up with a biodegradable solution, which can be implemented and regulated, so that everybody can use a biodegradable idol which is made from local materials. You know it is very simple but there does not seem to be a seriousness with regard to this issue in the nation.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Actually, that is what I said that if you create idols out of mud, it is biodegradable. So, people are now using more and more soil and mud for creating idols and many centres have converted to using that. A very few people are now using plaster of Paris. If you have some report of a place where more and more plaster of Paris is being used, please inform me. We will definitely direct the State Government concerned.

SHRIMATI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Mr. Minister, Sir, I would like to continue on the question of the ban on toxic materials. My colleague had spoken on the issue of Ganesh Chaturthi. I would like to expand the scope of that to all the idols because we come from a rural area where obviously, we have a lot of religious festivals. India is a land of festivals. It is not just Ganesh Chaturthi festival but there are various festivals. This idol making is actually a cottage industry and a part of small and medium enterprises and it creates a lot of employment. So, it is not something that we would like to clamp down on.

Having said that, there seems to be absolutely no widespread awareness among people who make it, among people who celebrate the festival, on not just the idols but the accompanying ornaments, the decorative materials with all of the plastics, nylon, Styrofoam that goes with it, paints and dyes which are put in usually in the ponds. The issue is, if it is put in a river, there is no problem but if it is put in a pond, which is the source of drinking water, which is used for washing and all of those things, it not only creates environmental problem but also it creates sometimes a very high level of toxicity. So, I would request your goodself to see if we could issue some very stringent guidelines which can be implemented at the Panchayat levels.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: It is a suggestion for action and we have taken note of it. The issue is very real that now we are doing away with single-use plastic. So, thermocol cannot be recycled or cannot be processed. So, it remains there and it is a hazard. It is used even in decoration. Now there will be Christmas also. …(*Interruptions*) Everything is related to Tamil Nadu! Everything is concerning all-India. So, we have already taken measures. But I take note of this suggestion and we will definitely communicate it to the States.

(ends)

(pp. 24-30)

(Q. 168)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): अध्यक्ष महोदय, जिस दिन बाघों की संख्या, अगर बाघ खत्म हो जाएंगे, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, गहन अध्ययन से इस बात की जानकारी मिली है। महोदय, आज बाघों की संख्या पूरे भारतवर्ष में 2900 है। इसके लिए हम सरकार को बधाई देना चाहेंगे। बांदीपुर, जिसकी चर्चा की गई है, वहां 382 बाघ हैं, जो दुनिया के दूसरे नंबर पर हैं। आज से ढाई सौ वर्ष पहले भारत में अंग्रेज एक पौधा लाए थे, जिसका नाम लैंटेना है। महोदय, कोटा से ले कर, रणथंभौर से ले कर बांदीपुर तक हर जंगल में लैंटेना आ चुका है, जो सभी घासों को नष्ट कर रहा है। उसका परिणाम यह हो रहा है कि बाकी छोटे जानवर उस इलाके में नहीं आ पाते हैं, चर नहीं पाते हैं, घास मरती जा रही है। लैंटेना के कारण जब घास मरती है तो छोटे पशु-पक्षी नहीं आते हैं। इस कारण से बाघों की खाने की व्यवस्था कम हो रही है। यह पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ी चिंता का विषय है।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि यह जो लैंटेना है, जिसको अंग्रेजों ने ढाई सौ वर्ष पहले भारत में अपने फूल के रूप में उपयोग किया था, उसको मारने का या उसका निवारण करने का, क्योंकि सबसे बड़ा अभिशाप अगर जंगलों में आज कुछ है तो लैंटेना है। लैंटेना को समाप्त करने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए, बाघों को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है?

(1200/RV/SAN)

श्री प्रकाश जावड़ेकर: महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। राजीव प्रताप रूडी जी सदन की तरफ से नेशनल टाइगर ऑथोरिटी के भी सदस्य हैं।

बंदीपुर में बहुत अच्छी व्यवस्था है, जहां चार फॉरेस्ट्स - सत्यमंगलम, बी.आर.टी., मुदुमलाई और वायनाड हैं। चारों एक ही वेस्टर्न घाट के कंटीग्युअस एरिया में हैं। वहां 126 टाइगर्स हैं। लेकिन, माननीय सदस्य ने लेंटाना के बारे में जो सवाल पूछा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। लेंटाना के कारण सभी जगह प्रॉब्लम्स हैं कि अगर उसके कारण बैम्बू निकल गया तो वहां लेंटाना आ गया। इसलिए अभी परसो ही, 30 तारीख को, देश के सभी वन मंत्रियों की दिन भर की बैठक हमने रखी है, जिसमें कैम्पा के 40,000 करोड़ रुपये, जो सभी राज्यों को वितरित किए गए हैं, उसके द्वारा इस लेंटाना को कैसे खत्म करें, वहां पानी के स्रोतों को सुदृढ़ और मजबूत कैसे करें, water and fodder augmentation in jungles because that is about human-animal conflict, इन विषयों पर उसमें विस्तार से चर्चा होगी, इस पर निर्णय होंगे और आपको हम इससे अवगत कराएंगे।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन-प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने किसी भी स्थगन-प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, इसमें हमारा एक विषय है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका विषय लेंगे। मैंने सदन में जो कमिटमेंट कर दी, उसे लेंगे। आप विराजें।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नं. 2 - श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी जी।

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, I rise to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(1) Review by the Government of the working of the Cotton Corporation of India Limited, Navi Mumbai, for the year 2018-2019.

(2) Annual Report of the Cotton Corporation of India Limited, Navi Mumbai, for the year 2018-2019 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Life Sciences, Bhubaneswar, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Life Sciences, Bhubaneswar, for the year 2018-2019.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Plant Genome Research, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Plant Genome Research, New Delhi, for the year 2018-2019.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Bioresources and Sustainable Development, Imphal, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Bioresources and Sustainable Development, Imphal, for the year 2018-2019.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology, Thiruvananthapuram, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology, Thiruvananthapuram, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology, Thiruvananthapuram, for the year 2018-2019.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Translational Health Science and Technology Institute, Faridabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Translational Health Science and Technology Institute, Faridabad, for the year 2018-2019.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Centre for Cell Science, Pune, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Centre for Cell Science, Pune, for the year 2018-2019.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Agri-Food Biotechnology Institute, Mohali, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Agri-Food Biotechnology Institute, Mohali, for the year 2018-2019.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre of Innovative and Applied Bioprocessing, Mohali, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre of Innovative and Applied Bioprocessing, Mohali, for the year 2018-2019.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Brain Research Centre, Manesar, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Brain Research Centre, Manesar, for the year 2018-2019.

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Animal Biotechnology, Hyderabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Animal Biotechnology, Hyderabad, for the year 2018-2019.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics, Hyderabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics, Hyderabad, for the year 2018-2019.

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Biomedical Genomics, Kalyani, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Biomedical Genomics, Kalyani, for the year 2018-2019.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Stem Cell Science and Regenerative Medicine, Bangalore, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Stem Cell Science and Regenerative Medicine, Bangalore, for the year 2018-2019.

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Immunology, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Immunology, New Delhi, for the year 2018-2019.

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Biotechnology Industry Research Assistance Council, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Biotechnology Industry Research Assistance Council, New Delhi, for the year 2018-2019.

(16) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Indian Vaccines Corporation Limited, Gurugram, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Indian Vaccines Corporation Limited, Gurugram, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Siddha, Chennai, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Siddha, Chennai, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Siddha, Chennai, for the year 2018-2019.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Ayurveda, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Ayurveda, New Delhi, for the year 2017-2018.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) A copy of the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) Second Amendment Regulations, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. 12-11/2010-CCH(Pt.-II)(1) in weekly Gazette of India dated 2nd August, 2019 under sub-section (2) of Section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, on behalf of Shri Ashwini Kumar Choubey, who has now come to the House, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pharmacy Council of India, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pharmacy Council of India, New Delhi, for the year 2018-2019.

(2) A copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) for the year 2018-2019 alongwith Audited Accounts in respect of the following centres:-

1. Population Research Centre (Department of Statistics, Maharaja Syajirao University of Baroda), Vadodara.
2. Population Research Centre (Centre for Research in Rural and Industrial Development), Chandigarh.
3. Population Research Centre (JSS Institute of Economic Research), Dharwad.
4. Population Research Centre (Gauhati University), Guwahati.
5. Population Research Centre (Department of Statistics, Patna University), Patna.
6. Population Research Centre, (Gokhale Institute of Politics and Economics), Pune.
7. Population Research Centre (Himachal Pradesh University), Shimla.
8. Population Research Centre (University of Kashmir), Srinagar
9. Population Research Centre (University of Kerala), Thiruvananthapuram.
10. Population Research Centre (Andhra University), Visakhapatnam.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

1203 hours

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 28th November, 2019 agreed without any amendment to the Chit Funds (Amendment) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th November, 2019."

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

1203 बजे

माननीय अध्यक्ष: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 28 नवम्बर, 2019 को सभा में प्रस्तुत अपने पहले प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने उल्लिखित अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति देने की अनुशंसा की है –

1.	श्रीमती हिमाद्री सिंह	17.06.2019 से 26.07.2019
2.	श्री दीपक (देव) अधिकारी	20.06.2019 से 13.07.2019
3.	श्री अतुल कुमार उर्फ अतुल राय सिंह	17.06.2019 से 06.08.2019
		एवं
		18.11.2019 से 25.11.2019
4.	श्री जयंत सिन्हा	22.11.2019 से 13.12.2019
5.	श्री बिद्युत बरन महतो	25.11.2019 से 13.12.2019

क्या सभा की यह इच्छा है कि समिति द्वारा अनुशंसित अनुमति प्रदान की जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी, हाँ।

माननीय अध्यक्ष: अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

श्रम संबंधी स्थायी समिति
पहला से तीसरा प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं: -

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

BUSINESS OF THE HOUSE

1204 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 2nd of December, 2019 will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's Order Paper:- [it contains discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019 (No. 15 of 2019) and consideration and passing of the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2019 – to replace an Ordinance]
2. Consideration and passing of the following Bills:-

1. The International Financial Services Centers Authority Bill, 2019.
2. The Recycling of Ships Bill, 2019.

3. Consideration and passing of the following Bills, after their introduction:-

1. The Arms (Amendment) Bill, 2019.
2. The Anti Maritime Piracy Bill, 2019.

3. Discussion and Voting on the first batch of Supplementary Demands for Grants (including Railways) for the year 2019-20 and consideration and passing of the related Appropriation Bill after its introduction.

(1205/RBN/MY)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The following items may be included for discussion in the next week's agenda:-

1. The alleged illegal action by Railways to evict the families residing in the land adjacent to the railway lines, particularly in Thenmala, Aryankavu, Kazhuthuruthy, Punalur in Kollam Constituency.
2. The denial of Super Speciality Treatment to the insured person on the basis of their attendance causing difficulty to the insured persons and their dependents.

SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): The following items may be included for discussion in the next week's agenda:-

1. To declare the 'Keeladi' excavation site in Tamil Nadu as a 'Protected Monument' and also to set up an experimental museum there.
2. To pay monthly rent to the farmers whose lands were acquired for laying of high-power tension electricity line in Tamil Nadu.

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो विषयों को सम्मिलित करने की कृपा करें:-

1. वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए पूरे देश में पेट्रोल/डीजल से चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की आवश्यकता है।
2. मुम्बई के विकरोली और विद्याविहार के नए रेल ओवर ब्रिज को चौड़ा किए जाने के कार्य को गति प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): The following item may be included for discussion in the next week's agenda:-

1. Need to take up the matter of Bangladeshi nationals residing in Detention Camp of Assam with the Government of Bangladesh.

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): The following items may be included for discussion in the next week's agenda:-

1. Need to take steps to curb pepper import and increase the MIP rate to Rs. 700.
2. Need to establish India's High Altitude Training Centre in Munnar and to develop it into a sports university.

माननीय अध्यक्ष: श्री दुष्यंत सिंह - उपस्थित नहीं।

सुश्री एस. जोतिमणि – उपस्थित नहीं।

श्री राहुल कस्वां (चुरू): महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो विषयों को सम्मिलित करने की कृपा करे:-

1. बेमौसम बरसात की वजह से फसलों को हुए नुकसान के संबंध में।
2. नोहर तहसील के गाँव मोटेर, धान्धूसर में एयर टू ग्राउंड फायरिंग रेंज के संबंध में।

डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं): महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित करने की कृपा करे:-

1. बदायूं, जो विकास से कोसों दूर है, जहां युवा रोजगार से वंचित है तथा पलायन से ग्रसित है, वहां उद्योग, कल-करखाने लगाए जाने की आवश्यकता है जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त हो तथा युवाओं के पलायन को रोका जा सके।

SHRI SHYAM SINGH YADAV (JAUNPUR): The following item may be included for discussion in the next week's agenda:-

1. Regarding opening of a Central School in Jaunpur Parliamentary Constituency.

(1210/SM/CP)

ELECTION TO COMMITTEE
Indian Council of Medical Research

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): I beg to move:

> "That in pursuance of rules 1(xxiv) and 15(ii) of the Rules and Regulations of the Indian Council of Medical Research, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves, to serve as members of the Governing Council of Indian Council of Medical Research, subject to the other provisions of the said Rules and Regulations."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के नियमों के नियम 1 (चौबीस) और 15(दो) तथा विनियमों के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की शासी परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

ARMS (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): श्री अमित शाह जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयुध अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि आयुध अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. किशन रेड्डी: अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): पाइंट ऑफ आर्डर बोलने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : सबको मौका देंगे।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, चर्चा में हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पद्धति, नियमों का थोड़ा पालन करें। यही हमारी गुजारिश है कि नियमों का पालन करें। …(व्यवधान) यह आपका अधिकार है।

माननीय अध्यक्ष : मैं नियम की बात नहीं करता। सदन नियमों से ही नहीं, सदन सबकी सहमति से भी चलता है। मेरा आपसे आग्रह है कि जब कोई ऐसा गम्भीर विषय होता है, जब लेबर का विषय था, मैंने खुद ही कहा कि इसे आज नहीं, यह विषय छोटा है, इस पर डिबेट करने के समय आपको अवसर दिया जाएगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आप मंडे को डिबेट करने जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : मंडे, ट्यूसडे जब भी आप डिसाइड करेंगे, उसमें आपको पर्याप्त समय देंगे।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आज बीएसी की मीटिंग हुई, उस समय भी पता नहीं था।

माननीय अध्यक्ष : कोई बात नहीं। मैंने स्पेशल इसको लिया है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, बीएसी की मीटिंग हुई थी।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप शून्य काल वाला विषय उठा रहे थे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा एक मिनट।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हम सब विपक्ष के सारे नेताओं ने, मेंबर्स ने आपसे दरख्वास्त की थी कि सदन के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का पूजन हो रहा है। नाथूराम गोडसे का जब पूजन हो रहा है, तो सदन की गरिमा को यह हानि पहुंचाता है और साथ-साथ हमारे देश का अपमान होता है।…(व्यवधान) महात्मा गांधी सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के पिता हैं। सारी दुनिया उनसे प्रेरणा लेती है। सारी दुनिया के पीड़ित लोगों के वे प्रेरणास्रोत हैं। उन्हीं के हत्यारे का जब पूजन किया जाता है, उन्हीं के हत्यारे की जब यहां सराहना की जाती है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : साध्वी प्रज्ञा जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात रखें।

विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में
एवं
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): महोदय, नियम 222 कहता है – " कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से, कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगा/सकेगी जिसमें या तो किसी सदस्य के या सभा के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का भंग अन्तर्ग्रस्त हो।"

मैं इसके अंतर्गत अपनी बात कहना चाहती हूं।

महोदय, बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूं। …(व्यवधान) परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूं, सुनिए…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप डिबेट मत करिए।

…(व्यवधान)

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): परन्तु मैं यह भी कहना चाहती हूं कि संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़-मरोड़कर गलत ढंग से पेश किया गया है। मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था जिसे गलत ढंग से इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया।…(व्यवधान) जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड़ा-मरोड़ा गया है, वह निंदनीय है।…(व्यवधान) महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूं।

मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया।…(व्यवधान) मेरे साथ तत्कालीन सरकार द्वारा रचे गए षडयन्त्रों के बावजूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है।…(व्यवधान)

(1215/NK/AK)

मुझे बिना दोषी सिद्ध हुए आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है। कोई आरोप सिद्ध हुए बिना मुझे आतंकवादी बताना, एक महिला के नाते, एक संन्यासी के नाते, एक सांसद के नाते, मेरे सम्मान पर हमला करके मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया है। …(व्यवधान) एक महिला होते हुए तत्कालीन सरकार द्वारा षडयंत्र रचकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। …(व्यवधान)।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मुझे आपके द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को दी गई विशेषाधिकार के मामले से संबंधित सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, यह विषय मेरे विचाराधीन है।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा थी, जब सदन की गरिमा का सवाल है तब जरूर कुछ ऐसा कदम उठाएंगे। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, आप अपने मेम्बर को बैठाओ। पहले आप उनको बैठाओ। सदन को आर्डर में आने के बाद बोलिए। माननीय सदस्य आप बैठ जाइए। हाऊस को आर्डर में आने दीजिए।

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से माफी मांगी है। इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, जो मर्जी होगा वह बोल दो, यह नहीं होगा।

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): Sir, how are you allowing it? …(*Interruptions*) What is this? …(*Interruptions*) She is an accused in that case. …(*Interruptions*)

SHRIMATI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): How can she talk about all these things here? …(*Interruptions*)

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): How can she say all these things? …(*Interruptions*) What is this? …(*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, nobody has called her a terrorist here. …(*Interruptions*)

श्री प्रहलाद जोशी: अध्यक्ष महोदय, उन्होंने माफी मांगी है, No, you would have to listen to me. …(*Interruptions*) पहले सुन लीजिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, इनको माफी मांगना चाहिए, ये हाऊस को गुमराह कर रहे हैं। …(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, उनकी बात कुछ अधूरी रह गई है उसमें माफी वाला विषय है, आप एलाऊ कर दें। …(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: अध्यक्ष महोदय, फर्स्ट सेन्टेन्स में ही इन्होंने माफी मांगी है, माफी मांगने के बाद यह व्यवहार ठीक नहीं है …(व्यवधान) उन्होंने स्पष्ट रूप से और एकदम क्लीयर टर्म से माफी मांगी है और महात्मा गांधी जी के विचार के ऊपर, महात्मा गांधी जी की सेवा के ऊपर उनको श्रद्धा है, ऐसा स्टेटमेंट माननीय सदस्य दे चुकी हैं। …(व्यवधान)

इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे बहाना नहीं बनाना चाहिए। इनके नेता जो सदन के मेंबर हैं, इन्होंने हमारे सदस्य को without any proof कोर्ट या अदालत के फैसले के बिना इनको आतंकवादी कहा है, उसके बारे में भी इन लोगों को सोचना चाहिए …(व्यवधान) साध्वी जी ने स्पष्ट रूप से माफी मांगी है। महात्मा गांधी जी के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, श्रद्धा है, उसको उन्होंने रिपिट किया है। इसीलिए ये इसको अननेसेसरली पॉलिटीकल मुद्दा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है …(व्यवधान) मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। …(व्यवधान)

1219 hours

(*At this stage, Dr. Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members came and stood near the Table.*)

(1220/SK/SPR)

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे रहा हूं। अभी अधीर रंजन जी बोलेंगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर जाएंगे, तभी तो बोलेंगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, आप अपने सदस्यों को सीट पर बिठाइए।

…(व्यवधान)

1222 hours

(At this stage Dr. Thamizhachi Thangapandian, Shri Gaurav Gogoi, Shri Suresh Kodikunnil and some other hon. Members went back to their seats.)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सदन में आपस में डिबेट न करें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जब मैं बोल रहा हूं तो आप चुप रहें।

…(व्यवधान)

1222 hours

(At this stage, Shri Gaurav Gogoio,… and some other hon. Members went back to their seats.)

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं जिस भी देश में जाता हूं, यह देश ही नहीं पूरा विश्व महात्मा गांधी जी के विचारों, आदर्शों, उनकी देश के प्रति निष्ठा, भारत में सत्य और अहिंसा आंदोलन के कारण महात्मा गांधी जी को बहुत आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। यह देश ही नहीं पूरा विश्व महात्मा गांधी जी के विचारों को आज भी आत्मसात करता है। मेरा विचार है कि इस विषय पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर हम राजनीति करेंगे तो पूरे विश्व में यह विषय जाएगा।

(1225/MK/SNT)

इसलिए मैंने माननीय सदस्य से आग्रह किया कि संसद की कार्यवाही में यह कहीं भी हिस्सा नहीं है। यह मैंने पूर्व में बताया था। यह मेरी जिम्मेदारी भी है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, अधीर रंजन जी मेरी पूरी बात सुन लें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने पूर्व में कहा था कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि संसद में महात्मा गांधी जी के बारे में कोई बात किसी भी तरह से रिकार्ड में नहीं जानी चाहिए। मैंने आपको एंश्योर किया है, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कहा और सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं कि महात्मा गांधी जी के बारे में…।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, ऐसे मत कीजिए, आप स्पीकर की पूरी बात सुनिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सुरेश जी, आप स्पीकर की पूरी बात सुनिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: महात्मा गांधी जी की हत्या के मामले में कभी भी किसी व्यक्ति को सदन में या सदन से बाहर महिमामंडित करने की इजाजत सदन नहीं देता है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, मेरी पूरी बात सुन लें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसलिए कल माननीय रक्षा मंत्री जी ने सदन के अंदर सरकार की तरफ से अधिकृत बयान दिया। फिर आप सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि माननीय सदस्य का यह बयान सदन की कार्यवाही का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बात मीडिया में चली गई है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसलिए मैंने माननीय सदस्य से कहा कि वह इसको लेकर…।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, दो मिनट मुझे बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसलिए मैंने माननीय सदस्य से आग्रह किया और माननीय सदस्य ने इस पर माफी मांगी है कि ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है। अब आप बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, देखिए यह मामला सिर्फ एक पार्टी या व्यक्ति का नहीं है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप इनको बोलने दीजिए या आप बोल लीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सभी को बैठाइए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, सदन के अंदर यह घटना घटी है। इसके चलते पिछले दो-तीन दिनों तक यह चर्चा सारे मीडिया पर, टी.वी. पर, पेपर पर छाई हुई है कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर चुने हुए एक नुमाइंदे ने महात्मा गांधी का जो हत्यारा है …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बार-बार इस चीज को क्यों बोल रहे हैं?

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): उस हत्यारे को देशभक्त कहते हैं। …(व्यवधान) इसकी केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में निंदा हो रही है। …(व्यवधान) इस निंदा से बचाने की जिम्मेवारी

सरकार की भी है और आपकी भी है। महात्मा गांधी केवल हिन्दुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पीड़ित लोगों के नेता है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सुनिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): ये *… (Not recorded)*

माननीय अध्यक्ष: यह हिस्सा कार्यवाही में नहीं जाएगा। माननीय सदस्य आप ऐसा आरोप नहीं सकते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी आप एक लाइन में सुनना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप माननीय सदस्य की एक लाइन में जवाब सुनना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

1227 hours

(*At this stage, Shri Shri Gaurav Gogoi and some other hon. Members came and stood near the Table.*)

…(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: शून्यकाल में प्वांइट ऑफ आर्डर नहीं होता है।

…(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, आपने जो महात्मा गांधी जी के बारे में कहा और कल जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, वह पूर्णतया सत्य है। …(व्यवधान) लेकिन, इस सदन के सदस्य राहुल गांधी जी ने इस सदन की सदस्य प्रज्ञा ठाकुर जी के लिए आतंकवाद शब्द का यूज किया है।…(व्यवधान) इसलिए नियम 222 के तहत प्रिविलेज बनता है और मेरा आपसे आग्रह है कि राहुल गांधी जी के ऊपर प्रिविलेज मोशन मूव कीजिए तथा उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए।…(व्यवधान) क्योंकि आतंकवादी कहना उतना ही गलत है, उतना ही घटिया है, सदन के सदस्य के लिए और खासकर महिला के लिए बोलने में इनको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इस सदन में माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी जी को आकर इस सदन में माफी मांगनी चाहिए।…(व्यवधान) क्योंकि यह महत्वपूर्ण सवाल है। एक महिला को आतंकवादी कहना, इस सदन के सदस्य को आतंकवादी कहना महात्मा गांधी जी की हत्या से भी ज्यादा बदतर है। इसलिए आप राहुल गांधी जी के ऊपर प्रिविलेज मोशन मूव कीजिए। …(व्यवधान)

(1230/RPS/GM)

विशेष उल्लेख

…(व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): सर, मेरा नम्बर तभी आता है, जब विपक्ष शोर मचा रहा होता है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यहां उठाने का अवसर दिया है।…(व्यवधान) हम सभी जानते हैं कि दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता को प्रदूषित पानी पिला रही है। …(व्यवधान) दिल्ली में ढाई करोड़ लोग रहते हैं और अभी बीआईएस की एक रिपोर्ट में आया है कि देश में सबसे प्रदूषित पानी दिल्ली में पिलाया जाता है। …(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्य मंत्री के पास केवल एक ही विभाग है और वह है – दिल्ली जल बोर्ड। …(व्यवधान) दिल्ली जल बोर्ड का यह कार्य है कि वह दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी पिलाए, दिल्ली की कालोनियों में सीवर लाइन डाले, मगर आज दिल्ली के घरों में लोगों को जो पानी पीना पड़ रहा है, वह सीवर लाइन का मिक्स्ड पानी पीना पड़ रहा है। …(व्यवधान) दिल्ली में ऐसे एक करोड़ लोग रहते हैं, जो पानी साफ करने वाले आरओ प्लांट या वाटर फिल्टर प्लांट को एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, दिल्ली में गरीब लोग रहते हैं। …(व्यवधान) दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्य मंत्री के घर में आरओ लगा हुआ है, दिल्ली के सारे मंत्रियों और विधायकों के घरों में आरओ लगे हुए हैं। …(व्यवधान) अगर दिल्ली के मुख्य मंत्री यह कहते हैं कि दिल्ली का पानी साफ है तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्य मंत्री को अपना आरओ प्लांट हटाकर, उनको भी वही पानी पीना चाहिए, वही दूषित पानी पीना चाहिए। …(व्यवधान) दिल्ली सरकार के मंत्रियों को भी वही पानी पीना चाहिए जो आज दिल्ली की जनता पी रही है।…(व्यवधान)

(1235/IND/RSG)

अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बुलाकर क्या टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में रहना नरक से भी बदतर है। दिल्ली में जो आदमी रह रहे हैं, वे नरक से भी बदतर स्थिति में रह रहे हैं।…(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की जनता घुट-घुट कर मरे, इससे अच्छा है कि उन्हें बम से क्यों नहीं उड़ा देते। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है और दिल्ली के चीफ सैक्रेटरी को लताड़ा है।…(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहता हूं और भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वह दिल्ली के मुख्य मंत्री को बुलाकर निर्देशित करे कि दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी मिलना चाहिए और यह उनका मूलभूत अधिकार है। दिल्ली सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में यह वायदा किया था कि वह दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी देगी, लेकिन दिल्ली सरकार अपने किए गए 70 वायदों में से सभी में विफल हो चुकी है। दिल्ली सरकार न तो दिल्ली की जनता को साफ हवा दे पा रही है और न ही साफ पानी दे पा रही है। ऐसी सरकार को बुलाकर हमारी सरकार एक बार निर्देशित करे कि वह बीआईएस के नार्म्स फॉलो करे।…(व्यवधान)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): अध्यक्ष जी, आपने मुझे सदन में बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दी है। बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ था और आज बौद्ध धर्म पूरे विश्व में सबसे बड़ा धर्म है और करोड़ों की संख्या में लोग बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं।...(व्यवधान) जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात में कई सारे स्थान बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। वहां करीब 13 डेस्टिनेशन्स हैं जैसे देवनी मोरी, जूनागढ़, हमारे प्रधान मंत्री जी का होम टाउन वडनगर, मोनास्टेरी, साना केव्स, उपरकोट केव्स आदि बहुत जगहें हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनती करना चाहता हूं, यहां पूरे देश से और सारी दुनिया से लोग आस्था से आते हैं इसलिए इन स्थानों के विकास और संरक्षण के लिए फंड का आयोजन किया जाए। जीका जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके द्वारा भी फंड की व्यवस्था की जाए और वहां इन सभी स्थानों पर जो बौद्ध सर्किट बने हैं, उनकी देख-रेख की जाए। यह देश महात्मा गांधी का है, भगवान बुद्ध का है।...(व्यवधान) ये लोग जो सदन में व्यवधान कर रहे हैं, उन्होंने गांधी विचार की हत्या की है और उन्हें इस बात को उठाने का कोई अधिकार नहीं है। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।...(व्यवधान)

विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में

एवं

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण – जारी

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी और हमारे प्रधान मंत्री महात्मा गांधी जी का बहुत सम्मान करते हैं। यहां अभी जितने भी मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम सभी डेढ़ सौ किलोमीटर की पदयात्रा करके आए हैं और गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं।...(व्यवधान) कल महाराष्ट्र में जिस तरह से इन्होंने सरकार बनाई है, मैं यह एडिटोरियल 20 जनवरी, 2013 का लेकर आया हूं। यह 'सामना' का एडिटोरियल है, जो शिव सेना ने बनाया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कागज मत दिखाओ।

...(<u>व्यवधान</u>)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): उस एडिटोरियल में नाथूराम गोडसे को कहा है कि सबसे बड़ा देशभक्त इस देश का यदि कोई है, तो नाथूराम गोडसे है। कांग्रेस ने ऐसी पार्टी के साथ वहां सरकार बनाई है। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखाता है।...(व्यवधान) सरकार बनाने के लिए, सत्ता के लिए, लालच के लिए किसी भी सीमा तक ये जा सकते हैं। इन्होंने जिसके साथ सरकार बनाई, शिव सेना ने, उसी पार्टी के सदस्य *... (Not recorded)* ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि जो नाथूराम गोडसे हैं, वे देशभक्त हैं। इसलिए इन्हें अपनी बातें, ये दोगली चाल, इनका जो लालच है, इसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रधान मंत्री से माफी मांगनी चाहिए जो कि महात्मा गांधी के प्रति इतने समर्पित हैं।...(व्यवधान) हम सभी मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट समर्पित हैं और हमने डेढ़ सौ किलोमीटर की पदयात्रा की है। इनका दोहरा चरित्र इस देश के सामने आया है और इन्हें माफी मांगनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, इनकी पार्टी के राहुल गांधी हैं, जिन्होंने एक महिला के ऊपर आतंकवाद की बात की। उन्होंने यहां के एक सदस्य के ऊपर आतंकवाद की बात कही। मेरा आपसे दूसरा आग्रह है कि उनके ऊपर प्रिविलेज मोशन पेश करना चाहिए। उन्हें इस सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए और सजा देनी चाहिए क्योंकि आप यहां के एक-एक मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट के कस्टोडियन हैं और कांग्रेस के चरित्र को आपको उजागर करना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपने सदस्यों को बैठाएं। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

...(<u>व्यवधान</u>)

1239 hours

(At this stage Dr. Thamizhachi Thangapandian, Shri Gaurav Gogoi, Shri Suresh Kodikunnil and some other hon. Members went back to their seats.)

...(व्यवधान)

(1240/ASA/RK)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, कम से कम आप मुझे अपनी बात समाप्त करने का तो मौका दीजिए। …(व्यवधान) सर, आप मौका नहीं देते। कम से कम मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए।…(व्यवधान) सर, वहां प्रहलाद जोशी जी बोलते रहे, वहां निशिकांत दुबे जी बोलते रहे, जिसके खिलाफ हमारी शिकायत है, वह भी बोलते रहे। लेकिन हमको बोलने का मौका नहीं मिलता।…(व्यवधान) सर, जिस ढंग से आज सत्तारूढ़ पार्टी के लोग तर्क कर रहे हैं, इसने खुल्लमखुल्ला साबित कर दिया है कि यह सही मायने में …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) खुद पार्टी हैं। …(व्यवधान) …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) के खुद समर्थक हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम नहीं आएगा। अब आप बोलते रहो। आप दोनों बोलते रहो। ऐसा कोई भी जो सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम ही नहीं आएगा। बोलते रहो आप।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, सदन के अंदर जो हुआ है, उसके खिलाफ हमने शिकायत की है। …(व्यवधान) सर, सदन के अंदर क्या हुआ था? सदन के अंदर जो हुआ था, उसके बारे में हम न्याय मांगने के लिए आपके पास गये थे। …(व्यवधान) बाहर से कहां के कौन से रेफरेंस लेकर आते हैं, इसके साथ सदन के अंदर की बात का क्या ताल्लुक है? …(व्यवधान) सदन के अंदर जो हुआ है, हम उसी पर बात करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये अनक्वॉलिफाइड अपोलोजी मांगें। यह सदन की नहीं, देश की गरिमा का मसला है। …(व्यवधान) हिन्दुस्तान के राष्ट्रपिता, सारी दुनिया और सारे पीड़ित लोग जिनको गुरू मानते हैं, पूजा करते हैं, उनकी हत्या करने वाले को देशभक्त कहना सारे देशवासियों के लिए अपमान है। हम सारे देशवासियों के लिए अपमान है। ..(व्यवधान) इसी पीड़ा से बचने के लिए हमने, सारी विपक्ष पार्टीज ने आपसे दरख्वास्त की थी कि सदन में हुई बात पर आप आइए। बाहर कौन क्या बोला है, क्या कहा है, 'सामना' में क्या लिखा है, उसकी जिम्मेदारी सदन की नहीं है।…(व्यवधान) सदन के अंदर जो हुआ है, हम उसी पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। सर, मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि जिसके खिलाफ हमारी शिकायत है, वे अनक्वॉलिफाइड अपोलोजी मांगें। …(व्यवधान) सर, वे क्षमा मांगें। यह हमारी मांग है। …(व्यवधान)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, I was party to the proceedings on that day. …(*Interruptions*) Please maintain order. I spoke about the Gandhi's assassination and when I mentioned Nathu Ram Godse's name, the hon. Member said that he is a patriotic…(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No.

… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): You are correct.…(*Interruptions*) You have rightly expunged the matter. But here the question is…(*Interruptions*) Please listen to me.…(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, नहीं। एक्सपंज नहीं किया।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): A categorical observation was made by the Speaker. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एक्सपंज नहीं किया गया। कार्यवाही में पहले से ही नहीं था। आप बोलते रहो। जो विषय कार्यवाही में ही नहीं है, उसको सदन के अंदर बोलते रहो। बाहर आप कुछ भी बोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सदन में तो कार्यवाही के हिस्से से ही बोला जाएगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): It is correct. Whether it was expunged or 'not recorded'…(*Interruptions*) It is altogether a different matter. The question is, …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। अगर आप डिबेट ठीक से करना चाहें तो विराजें। श्री ए.राजा जी, कृपया आप बैठिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

(1245/VB/PS)

माननीय अध्यक्ष: Shri A. Raja, please sit down.

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: दो बातें हैं। सदन के बाद सभी दल के नेता मुझसे आकर मिल लें। श्री मुलायम सिंह जी वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वे इस मामले पर हस्तक्षेप करें। अगर कोई कार्यवाही, जो सदन का हिस्सा नहीं है, क्या उस पर डिबेट होनी चाहिए? यह हम लोग बैठकर फैसला करेंगे।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: श्री ए. राजा जी, मैं पहले पूरी बात बोल लूँ। अभी मैंने आपको बोलने की इजाज़त नहीं दी है।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: बी.ए.सी. में और सभी दलों के नेताओं को एक साथ बैठकर एक लाइन ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी बात पर, जो सदन का हिस्सा न हो, पर डिबेट होनी शुरू हो जाएगी, तो बाहर के हर विषय पर यह होगा। श्री मुलायम सिंह यादव जी और भर्तृहरि महताब जी सीनियर मेम्बर्स हैं। कोई इधर के माननीय सदस्य या उधर के माननीय सदस्य कहीं बाहर बोलेंगे, क्योंकि सदन के बाहर कई सभाओं में आरोप लगाते रहते हैं। क्या उन सारे विषयों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए? आम सभाओं में, जन-भाषणों में रोज आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। वह सदन का हिस्सा कैसे बन सकता है?

मैं पहले श्री मुलायम सिंह जी से आग्रह करूँगा, वे वरिष्ठ सदस्य हैं।

…(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अगर आप मुलायम सिंह जी को नहीं बोलने देना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा है।

…(व्यवधान)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): I fully agree that it is not part of the proceedings.

माननीय अध्यक्ष: हाँ, राजा जी बोल लें।

…(व्यवधान)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): I appreciate the way the matter is being tackled by the Chair. The thing is that it is not recorded in the proceedings. But -- whether it is right or wrong or whether knowingly or unknowingly -- the things have appeared in the Press, as we put it. Now, the matter has been taken into cognizance by the global community. This House is having …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए। मैं जवाब दूँगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: No. मैं जवाब दे रहा हूँ। सदन का स्पीकर मुझे बनाया गया है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप एक लाइन में बोलिए, क्या कहना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Though it has not been the part of the proceedings, somewhere there has been an outburst. Then the entire world took cognizance of the same. Mahatma Gandhi Ji is the Father of the Nation. The entire sovereign power of the country rests upon the Parliament. What is being said outside, is completely immaterial. But since there has been an outburst, some scar has been put on the head of the Father of the Nation. How are we going to remove it? Whatever comments made by me or by Rahul Ji or by anybody, that is a different thing. Even I have come across similar types of comments that were passed in the name of column writers. Individual opinion, whether appeared in the newspapers or in the television interviews, is altogether different. But when a word is being uttered in the House, it will have national importance because the sovereign power rests upon the Parliament.

So, we should not combine what is spoken outside and inside the Parliament. Let the hon. Member, very magnanimously, offer an unconditional apology. Everything will be settled. Through you, it is my prayer.

माननीय अध्यक्ष: मैं आज सबकी व्यवस्था दे रहा हूँ। लास्ट में आप मेरी व्यवस्था भी सुन लें। आप पहले श्री मुलायम सिंह जी को बोलने दें। फिर मैं आपको बोलने का मौका दूँगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मेरा एक सवाल है, आज इस पर खुली डिबेट होनी चाहिए कि क्या प्रेस के किसी वक्तव्य पर या टेलीविज़न के किसी वक्तव्य पर इस सदन में डिबेट होनी चाहिए?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगर सदन सहमत हो, तो मैं उस पर डिबेट कराऊँगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय राजा जी, मैंने आपको बोलने का मौका दिया था। श्री मुलायम सिंह जी पहले आप बोलें। मैं आपको भी मौका दूँगा।

…(व्यवधान)

(1250/PC/RU)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष जी, मैं एक राय दे रहा हूं। …(व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है कि इनको जो परेशानी है, वे यहां इज़हार कर रहे हैं। …(व्यवधान) आप पांच-दस मिनट के लिए सदन बंद कर के इधर-उधर के लोगों को बुला लीजिए और बात कर लीजिए। …(व्यवधान) यह हमेशा होता रहा है। …(व्यवधान) यह मेरी आपको राय है, आपसे प्रार्थना है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी अच्छी राय है। मैं इसे अच्छी राय मान रहा हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। मैं सबको मौका दूंगा।

…(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, in the meeting of the Business Advisory Committee held at 10 a.m. today, this issue was raised by Shri Adhir Ranjan Chowdhury. At that time, I got the impression that if we all mobilise to your office against the concerned Member who accused in the name of our Father of our Nation, Mahatma Gandhi ji, it will be sorted out. It is unnecessarily going to such a height that a discussion is taking place on the issue. It is as if we are all getting involved in a particular issue which should not have been. When a Party itself has taken a decision against a Member by withdrawing her from the Consultative Committee on Defence and not allowing her to attend to their Parliamentary Committee meeting, it is enough indication that the Party is not happy with her opinion. But if the Member herself finally says one line that she apologizes unconditionally about the incident which has happened knowingly or unknowingly, that will sort out the whole problem. My submission to you and the other Members would be that, by not raising any other

issue, if it can be concentrated on this part alone, I think, the Opposition will have nothing to say including, I hope, the ruling Party also. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं दानिश अली जी के बाद आपको मौका दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दानिश जी, आप अपनी बात एक मिनट में कहिए।

…(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): हां सर, मैं एक मिनट में बोलूंगा।

सर, सुदीप ने जैसा कहा, सुबह बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में यह डिस्कशन हुआ था। …(व्यवधान) हमें यह इम्प्रेशन था कि यह इश्यू यहीं बंद हो जाएगा। …(व्यवधान) मेरा आपसे सिर्फ इतना आग्रह है कि जिस तरीके से पिछले सत्र में किसी मेंबर से अपॉलजी कराई गई थी, ऐसे ही इन मेंबर से अपॉलजी कराई जाए। …(व्यवधान) इन्होंने अपने कोर्ट-केस को इस, फ्लोर ऑफ दि हाउस में डिफेंड किया, उसको एक्सपंज किया जाए। …(व्यवधान) The Member should not be given an opportunity to defend himself or herself of the court cases. That is my point. …(*Interruptions*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): स्पीकर सर, मैं आपके नोटिस में दिनांक 2 फरवरी, 1948 को महात्मा गांधी के कत्ल के बाद उस चेयर पर जो स्पीकर बैठे थे, कांस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में एक दिन उस पर बहस हुई। आप मुझे बताने के लिए इजाज़त दीजिए कि स्पीकर ने क्या कहा था।

स्पीकर ने कहा था -

> "It seems we have yet to realise that political violence is the greatest enemy of individual liberty and, therefore, democracy. We cannot condemn this idea of violence for political ends in too strong terms. Mere condemnation of the misguided and mad perpetrator of the tragedy is not enough."

सर, यह स्पीकर ने कहा था। …(व्यवधान) मैं आपके ज़रिए से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या नाथूराम गोडसे देशभक्त था या कातिल था? …(व्यवधान) आप बोलिए कि गोडसे कातिल था या टेर्रिस्ट था? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मेरी बात सुनिए।

…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, देखिए, यह क्या हो रहा है। …(व्यवधान) यह 'जैक इन दि बॉक्स' बिहेवियर है। …(व्यवधान)

सर, इस 'जैक इन दि बॉक्स' को रोकिए। …(व्यवधान) सर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बस, आपकी बात खत्म हो गई है।

…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, आधा मिनट दे दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको मौका दे दिया है।

…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा हूं। …(व्यवधान)

सर, आपने कहा कि यह रिकॉर्ड पर नहीं है। …(व्यवधान) मेरी आपसे गुज़ारिश है। …(व्यवधान) यह इग्रीजियस ब्रीच है। …(व्यवधान) It goes against the basic standards of conduct on the part of the Member. The Member should categorically say that Nathuram Godse is not a *desh bhakht*, he is a terrorist and a murderer of Gandhi ji.…(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: कल रक्षा मंत्री जी ने अधिकृत रूप से सरकार की तरफ से बयान दे दिया है। मैं दोबारा कहूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस विषय पर अधिकृत बयान दे दें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका आधा मिनट पूरा हो गया है। आप सरकार की तरफ से बयान सुनना चाहते हैं? आपने टिप्पणी की कि सरकार इसके बारे में क्या सोचती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन चौधरी जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

(1255/KDS/KKD)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार यह कह रहा हूं कि सदन की गरिमा के साथ इसका ताल्लुक है और इसलिए हम लोग कल से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। …(व्यवधान) बाहर किसने क्या बोला, बाहर किसने क्या किया, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कल श्री राजनाथ सिंह जी ने यह बात जरूर रखी। हमने यह भी देखा कि सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई करने की कोशिश की गई। …(व्यवधान) इसका मतलब यह है कि उन्होंने गलत किया था, यह सरकार ने खुद माना। जब सरकार खुद यह मान रही है कि वह दोषी हैं, तो फिर यह यह लोग ऐसा मानने और क्षमा मांगने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपकी तरफ से एक सदस्य ने बोल लिया है। अधीर रंजन जी, आप गरिमापूर्ण तरीके से समाप्त करिए। श्री महताब जी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, आपको जाना था, अब आप रुक गए। आप कृपया बैठ जाइए। श्री ओवैसी साहब ने जो कहा है, उसके लिए मैं एक बार फिर सदन की चेयर की तरफ से आप सबके बोलने के बाद अधिकृत बयान दे रहा हूं। महताब जी बोलिए।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, when the House becomes volatile relating to certain incident that has occurred inside this House on a given day, ultimately, the Chair has to take a decision. That is how our senior-most Member of this House, Shri Mulayam Singh-ji has just now gave you a way out that 'talk to the respective leaders of different groups and parties of this House in your Chamber, and try to find a way out.' सत्ता पक्ष का कोई मंत्री यहां जितनी बार भी बयान दे, मुझे नहीं लग रहा कि विपक्ष उससे संतुष्ट होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष का बयान सरकार का बयान होगा। सत्ता पक्ष की तरफ से बाहर क्या किया? किसी को कमेटी से रिमूव किया गया, पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं आने दिया गया। यह हाउस की व्यवस्था नहीं है। वह पार्टी की तरफ से किया जाता है, जिसकी जानकारी हमें अखबार से मिलती है। किसी ने किसी को वाट्स एप या सोशल मीडिया पर क्या कमेंट किया, वह भी हमें पता चलता है, पर जो प्रश्न आप यहां बार-बार पूछ रहे हैं, क्या उसको लेकर हमें यहां चर्चा करनी है या नहीं? यह सिर्फ एक मोशन के जरिए ही हो सकती है। जीरो ऑवर में ऐसे खड़े होकर कोई नहीं कह सकता।

अत: मैं आपको यह मशविरा देना चाहता हूं और हाउस को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहता हूं कि जो उस दिन हुआ, वह रिकॉर्ड में है या नहीं है, इसको लेकर कुछ लोगों के मन में संशय है। अत: मैं आपसे यह कहने की गुजारिश करूंगा, जो कि मैं आपके चैंबर में बोलने वाला था। चूंकि यह बहस थम नहीं रही है, इसलिए मुझे यहां कहना पड़ रहा है कि सिर्फ रिकॉर्ड में यहां लिखा गया कि नहीं लिखा गया, यह आप देख सकते हैं। हाउस में और भी व्यवस्थाएं हैं। कैमरा लगा हुआ है, जितने समय तक यह हाउस चलता है, उसके बाद भी एक और कैमरा लगा हुआ है। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। आप जब लीडर्स के साथ बात करेंगे, तो सेक्रेटेरिएट को भी कहिए कि वह यह देख ले। हमाने मन में या किसी के मन में अगर कुछ संशय है, वह भी क्लीयर हो जाएगा …for all time to come.

(1300/MM/RP)

इसके आगे मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस मीडिया ने, अगर यह गलत साबित हो गया, उस मीडिया ने इस तरह का माहौल बनाया, उसके ऊपर इस हाउस को क्षमता है, पावर है to take action. जहां तक अनकंडिशनल अपोलॉजी मांगने की बात है, मैं समझता हूं कि हम आज यहां इंसिस्ट न करें। पहले उसको देख लें और उसके बाद आगे की कार्रवाई करने के बारे में सोचें।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने सभी को बोलने का मौका दिया है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रेमचंद्रन जी, मैं अभी सभी को बुलाकर चर्चा कर रहा हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उनको जल्दी जाना है।

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, महात्मा गांधी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी का और आज के दिन में जो विश्व प्रिय नेता हैं और हमारे प्रधान मंत्री हैं, श्री नरेन्द्र मोदी जी का कितना सम्मान है, यह देश जानता है। उन्होंने खुद हम सब लोगों को, राज्य सभा और लोक सभा के भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को इनक्लुडिंग मंत्रियों को महात्मा गांधी के 150 वर्ष कैसे मना सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने कहा था, We have to take up Padayatra for 150 kilometres. इस पदयात्रा में महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं, महात्मा गांधी जी के लिए जो विश्व में सम्मान है, भारत में सम्मान है, महात्मा गांधी जी का त्याग, बलिदान, परिश्रम और सेवा के बारे में चर्चा करनी है, लोगों को उसके बारे में बताना है, ऐसा उन्होंने कहा है। हमारे सभी 380-383 लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य हैं, उन सभी ने पदयात्रा की है। मैंने स्वयं और प्रधान मंत्री जी ने स्वयं महात्मा गांधी जी के विचारों को फैलाने के लिए बहुत रुचि ली है। माननीय प्रधान मंत्री जहां जहां भी विदेश में जाते हैं, …(व्यवधान) हमने आपकी सब बात सुनी है। महात्मा गांधी जी के बारे में दुनिया भर में जाकर माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी उनके विचारों को, जो केवल भारत के ही नहीं वर्ल्ड के आइकॉन बन गए हैं, प्रधान मंत्री जी सभी देशों में फैला रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि गोडसे के बारे में सोचना ही गलत है। गोडसे को देशभक्त कहना, यह कहना, वह कहना, वह तो छोड़ दीजिए, बल्कि उसके बारे में सोचना भी गलत है। ऐसा माननीय राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। On the Floor of this House, he has told that. There is no question that गोडसे के बारे में कोई भी ऐसा बयान नहीं कर सकता है। वह रिकार्ड पर है या नहीं है, सदस्य ने स्पष्ट रूप से माफी मांगी है। आप पहले के संटेंसेज़ कृपया देख लीजिए। अगर स्पीकर को लगता है…(व्यवधान) You listen to me first. …(*Interruptions*) You listen to me first. …(*Interruptions*) You have to listen. …(*Interruptions*) उन्होंने स्पष्ट रूप से माफी मांगी है।…(व्यवधान) अगर स्पीकर यह समझते हैं कि यह स्पष्ट नहीं है…(व्यवधान) तो जो स्पीकर डायरेक्शन देंगे वह हम सदस्य मानने के लिए तैयार हैं…(व्यवधान) लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, वह रिकार्ड में है या नहीं है, सदस्य ने माफी मांगी है। इसलिए सदस्य जीरो ऑवर चाहते हैं। निशिकांत जी ने भी कहा है और सदस्य ने भी कहा है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन के सभी राजनैतिक दलों के नेताओं की बैठक 1 बजकर 15 मिनट पर मेरे कक्ष में रखी गई है। सदन की कार्यवाही ढाई बजे तक भोजनावकाश के लिए स्थगित की जाती है।

1304 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न-भोजन के लिए
चौदह बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

(1430/SJN/RCP)

1432 बजे

मध्याह्न-भोजन के पश्चात् लोक सभा चौदह बजकर बत्तीस मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

विशेष उल्लेख – जारी

माननीय अध्यक्ष : श्री तीरथ सिंह रावत।

…(व्यवधान)

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से वन एवं पर्यावरण और परिवहन मंत्री (भारत सरकार) का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तराखंड राज्य बनने के डेढ़ दशक के बाद भी हमें आज अपने ही क्षेत्र में जाने के लिए दूसरे प्रदेश से होकर गुजरना पड़ता है। यदि हम देहरादून से निकलते हैं, तो हरिद्वार, लालढांग से कंडी मार्ग होते हुए कोटद्वार, पाखरों, कालागढ़ तथा रामनगर की सड़क अंग्रेजों के समय में चलती थी। उसके बाद वन मंत्रालय के द्वारा जो कानून बनाया गया था, उसके कारण वह रोक दी गई है। इस रोड के न होने से हमको उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद, बिजनौर, नगीना, धामपुर, अफजलगढ़ और काशीपुर होते हुए दूसरी कमिश्नरी से नैनीताल के लिए जाना पड़ता है। यानी हमें 150-200 किलोमीटर के दायरे से घूमते हुए और दूसरे प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से गुजरकर अपने ही प्रदेश के अंदर एक कमिश्नरी से दूसरी कमिश्नरी में जाने के लिए इन रास्तों को तय करना पड़ता है। इतना ही नहीं, मेरे लोक सभा क्षेत्र गढ़वाल से जब मैं दूसरी विधान सभा रामनगर की तरफ जाता हूं, तो मुझे कोटद्वार से होते हुए इन्हीं मार्गों - नजीबाबाद, धामपुर, नगीना और काशीपुर होते हुए रामनगर जाना पड़ता है।

(1435/GG/SMN)

एक कोटद्वार विधान सभा है, उसी के एक मंडल होते हुए, कालागढ़ और वहां भी उसी विधान सभा के एक क्षेत्र से, दूसरे प्रदेश से गुजरना पड़ता है। यह बड़ी विडंबना है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से वन एवं पर्यावरण मंत्री, भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे देहरादून, हरिद्वार, लालढांग, कंडीमार्ग, कोटद्वार, कालागढ़ और पोगर होते हुए राम नगर के लिए इस रोड को बनाने, आगे चालू करने के लिए इस कार्य को गति दें। मेरा आपसे निवेदन और आग्रह है कि भारत सरकार इसमें संज्ञान ले ताकि हमें अन्य जगहों से गुजरना न पड़े।

माननीय अध्यक्ष : श्री अजय टम्टा को श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय अधीर रंजन साहब, माननीय सदस्य साध्वी जी आ रही हैं। एक मिनट बात तो सुनिए। सभी दलों की राय-मश्विरा और सहमति से जो फैसला हुआ है, जो निर्णय हुआ है, सदन उनसे अपेक्षा करेगा कि…

…(व्यवधान)

OBSERVATION BY HON. SPEAKER

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट मेरी पूरी बात तो सुनिए। सदन फ्लोर लीडर्स ने जो तय किया है, यह सदन उनसे अपेक्षा करेगा कि वे उतना ही वक्तव्य पढ़ें, जितना सदन ने सर्वदलीय सभा में तय किया है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि सदन की उन माननीय सदस्या के आने तक मैं दो विषयों पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। नंबर एक, आज शून्य काल में मैंने कई माननीय सदस्यों को आग्रह किया था कि मैं शून्य काल में उनको बोलने का अवसर दूंगा। आज चूंकि प्राइवेट मैंबर्स बिल का भी समय है। इसलिए मेरा इतना सा अ ाग्रह है कि अगर सदन की इस बात में सहमति हो तो चार-साढ़े चार बजे तक जीरो ऑवर चला दें? सदन सहमत हो तो फिर प्राइवेट मैंबर्स बिल डेढ़ घंटे के लिए आगे ले लेंगे, क्योंकि उस पर लंबी डिबेट पहले हो चुकी है। क्या सदन इस बात से सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ महोदय।

माननीय अध्यक्ष: सबकी सहमति है तो साढ़े चार बजे तक शून्य काल चलाएंगे और साढ़े चार बजे के बाद प्राइवेट मैंबर्स बिल लेंगे। मैं सदन में सबको आश्वस्त करता हूँ कि यह सदन सबकी सहमति से चलता है। सभी दलों के लोग भी चाहते हैं कि सदन चले, स्मूथली चले, व्यवस्थित चले। सभी दलों की सहमति थी कि कभी भी संसद के बाहर वाले वक्तव्यों के बारे में चर्चा यहां पर नहीं होगी। क्या आप सब सहमत हैं न इस बात पर?

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आज तो शुक्रवार है। यह प्राइवेट मैंबर्स बिल का दिन है। साढ़े तीन बजे से प्राइवेट मैंबर्स बिल होता है। यह हमारे यहां का रीति-रिवाज है। लेकिन आज जो पीएमबी का मुद्दा है – केन बेतवा रिवर लिंकिंग का, उस पर बहुत भारी चर्चा यहां पर हो चुकी है। आप अगर चाहें, जीरो ऑवर में शामिल होने के लिए हमारे काफी सदस्य हैं, उनकी सुविधा के लिए आप अगर चाहें तो आधा घंटा या 45 मिनट प्राइवेट मैंबर्स बिल से हटा लिया जाए। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस पर लंबी बहस हो चुकी है।

माननीय अध्यक्ष: महताब जी, बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, वे आ रही हैं, तब तक महताब जी इसी विषय पर बोल लें।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): अध्यक्ष जी, आपने एक व्यवस्था हाउस के सेंस के लिए रखी है। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। यह मैं नम्रता के साथ बोलता हूँ। प्राइवेट मैंबर बिल इंडिवीजुअल मैंबर का बिल होता है या बिज़नस होता है।

(1440/KN/MMN)

आज के दिन ही नहीं, हर वक्त मैंने पिछले तीन–14वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभा सत्र में देखा है कि हर बार प्राइवेट मैम्बर बिजनेस की कैजुअलिटी होती है। यूपीए गवर्नमेंट में भी यही हुआ था और एनडीए गवर्नमेंट में भी वही हो रहा है। आज आप एक राय ले रहे हैं और ज़ीरो अवर के लिए रूल्स कमेटी में, जिसके आप अध्यक्ष हैं, उसमें एक दिन रख दीजिए, उसी दिन सारा ज़ीरो अवर कर लीजिए, चाहे वह फ्राइडे क्यों न हो और हमारा प्राइवेट मैम्बर बिजनेस वीरवार को ले लीजिए।

मिड ऑफ द वीक जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्राइवेट मैम्बर बिजनेस वीरवार को होता है, उसी हिसाब से हमारे यहाँ प्राइवेट मैम्बर बिजनेस फ्राइडे में न रख कर वीरवार को रखिए और ज़ीरो अवर आफ्टर लंच पूरा 6 बजे तक चलाया जाए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I fully endorse the views expressed by Mahtab Ji. Now-a-days a debate is going outside the House whether the Private Members' Business is needed or not. That discussion is going on. Most of the media people have contacted me last time when I had introduced three Bills. What is the scope of these Bills? The Private Members' Business should be given much more importance and significance. It is having its own impact. From my own experience, I am telling here and also the hon. Minister of Parliamentary Affairs may be well aware that on moving a Resolution on the EPF pension, 6.5 lakh pensioners were benefitted. It was only on the basis of a Resolution moved in the House. So, it is having its own impact. Sometimes, we have to cut short the Private Members' Business. But it should be only due to unavoidable circumstances that the time of the Private Members' Business be cut down. Otherwise, that should be kept intact. The time from 3.30 p.m. to 6 p.m. should be confined for the purpose of the Private Members' Business, unless some extraordinary situation demands. Otherwise, please do not cut down the time of the Private Members' Business. That is the humble submission which I would like to make.

Also, I fully support the suggestion that let it be on Wednesday. Most of the Members and even the Prime Minister will be here and it will be having its own importance, if it is on Wednesday.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, the Private Members' Business has a special position in the House. The Members, no doubt, wait for the Private Members' Business but the maximum of us will leave for our own constituencies. Today I am here because my flight is late by three hours. जैसे फ्राइडे को प्राइवेट मैम्बर बिल की जरूरत होती है, वैसे ही मैम्बर्स को घर वापस जाने की जरूरत होती है। So, as Shri Bhartruhari Mahtab rightly said, if it can be brought on Wednesday, it is better. Sir, you are on way to making history in Parliament. Take such a step so that the Private Members' Business is shifted to Wednesday. फ्राइडे को ज़ीरो अवर जितना चाहे, जिसको अपनी कॉन्स्टीट्यूएंसी में जाने की जरूरत नहीं है, वे सब यहाँ बैठेंगे। So, I do not oppose the suggestion proposed by Shri Bhartruhari Mahtab.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से एक सांसद के नाते प्राइवेट मैम्बर बिल का पूरे सप्ताह इंतजार रहता है। प्राइवेट मैम्बर बिल के लिए दो सप्ताह का समय लगता है। उसका पूरा इंतजार रहता है और इसमें धीरे-धीरे सांसदों की रुचि भी बहुत बढ़ी है। मेरा भी आग्रह है कि भर्तृहरि महताब जी प्राइवेट मैम्बर बिल के बारे में जो बात कह रहे हैं, वह सांसदों का अपना एक तरह का समय का उपयोग है, उनका अधिकार है। उसमें कटौती न की जाए। वैसे भी आपके नेतृत्व में ज़ीरो अवर खूब चला है और अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो किसी विशेष दिन ज़ीरो अवर को पूरे दिन ले लिया जाए। लेकिन यह प्राइवेट मैम्बर बिल या प्राइवेट सांसदों को जो अधिकार है या अवसर है, वह कम न किया जाए। यह मेरा आपसे आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजीव रंजन। सदन का सेंस ले रहे हैं, उसके बाद व्यवस्था दे देंगे।

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): अध्यक्ष महोदय, महताब जी ने जो बात रखी है, वह बहुत वाजिब बात है। सदस्यों का समय या तो क्वेश्चन अवर है या फिर प्राइवेट मैम्बर्स डे है। सदस्यों के लिए यही दो समय हैं, बाकी तो सरकार का बिजनेस होता है। पार्टी का भी बिजनेस होता है और सरकार का भी बिजनेस होता है। अब प्राइवेट मैम्बर्स बिल के लिए मैम्बर्स बहुत मेहनत करते हैं। बिल को ड्राफ्ट करते हैं। उनका बिल लॉटरी में आता है, बिल इंट्रोड्यूस होता है। बिल पर चर्चा होती है, उसकी चर्चा के लिए वह तैयारी करते हैं।

(1445/CS/VR)

महताब जी ने जो कहा है, वह बहुत सही है। वैसे भी शुक्रवार को बहुत लोगों को जाने की हड़बड़ी रहती है। हम इससे सहमत हैं कि बुधवार कीजिए, बृहस्पतिवार कीजिए, लेकिन वीक डेज में उसे आप कर दीजिए। यह भी सदस्यों के हित में आपके द्वारा उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम होगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, आपने कहा कि आज आधा घंटा, 45 मिनट प्राइवेट मेंबर बिल से कटौती करके जीरो ऑवर को लेना है या ऐसी आपने इच्छा जताई है। केन-बेतवा मुद्दे पर आज चर्चा होनी है, उस पर बहुत सारी चर्चा हुई है। अगर प्राइवेट मेंबर बिल के समय में कोई कटौती होती है, तो जितनी कटौती आप कर रहे हैं, छ: बजे के बाद उसे काम्पन्सेट कर दीजिए। यह एक चीज है। आपने आधा घंटा इधर से लिया, तो आधा घंटा उधर दे दीजिए। आप साढ़े छ: बजे तक प्राइवेट मेंबर बिल का समय कर दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : आप भी इस विषय पर अपनी कुछ टिप्पणी कीजिए। आज संजय जी का जन्मदिन भी है।

…(<u>व्यवधान</u>)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे भी लगता है कि प्राइवेट मेंबर बिल हमारे माननीय सदस्यों का अधिकार है और यह दो हफ्ते में एक बार पड़ता है, इसलिए इसको चलाना चाहिए। हम लोग भी लाटरी का इंतजार करते रहते हैं, सौभाग्य से किसी-किसी की लाटरी निकलती है और उसको उस विषय पर चर्चा करने का मौका मिलता है। मेरा भी आपसे अनुरोध रहेगा कि प्राइवेट मेंबर बिल पूरा चलने दिया जाए।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि प्राइवेट मेंबर बिल का जो मेंबर्स का अधिकार है, वह तो आप पूरा करवाते ही हैं, लेकिन जीरो ऑवर के अंदर आपने 5-6 लोगों को बुलवा दिया है। लाटरी के अंदर 20 लोगों के नाम आए हैं। दो-दो मिनट के अंदर सभी लोग अपनी बात रख लेंगे, इसमें कोई ज्यादा समय नहीं जाएगा। अभी पौने तीन बजे हैं, साढ़े तीन बजे आप प्राइवेट मेंबर बिल ले लेना। साहब, हमारी बहुत मुश्किल से लाटरी खुलती है। आज आप इतना कीजिए। हम सभी लोगों ने सम्मिलित रूप से सदन चलने दिया है, आज इन्होंने डिस्टर्ब किया, फिर भी आप जीरो ऑवर में बचे हुए लोगों को मौका दे दीजिए। आप जीरो ऑवर पहले करा दीजिए। आप छ: लोगों को जीरो ऑवर में बुलवा चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष : कनिमोझी जी, आप भी इस पर अपने विचार रख दीजिए। सभी दलों के लोगों के विचार आ जाएंगे।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, from personal experience I know how difficult it is to get an opportunity to bring in a Bill as a Private Members Bill. I think that importance of the Private Members Bill should not be compromised for anything.

We should give it importance and we should allow the Members to discuss these Bills completely because this is the only time a Member, as a private person, is allowed to express his point of view. I think that we should not compromise on it.

SHRI KANUMURU RAGHURAMA KRISHNARAJU (NARSAPURAM): Sir, as Mahtab ji has said and everyone is of the same opinion that Private Members Bill should be given the priority. I also request to shift it to Wednesday as everybody is in a mood to leave on Friday. This is a very important time when private Members can express their individual opinion. My hon. friend has rightly said that all the days we participate in the Government business and have only a few hours to discuss Private Members Bills. So, I request you to kindly look into it.

Sir, I also have a small request to make in respect of lottery system for Members to speak in Zero Hour. As hon. Speaker is kind enough and gives two minutes to each Member to speak, we are left with 20 more minutes. If the number of lotteries is enhanced from 20 to 30 as many hon. Members are very anxious to participate in it, 10 more Members would be accommodated in the ballot. I humbly request the hon. Speaker to consider it, if possible. Thank you, Sir.

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): महोदय, लाटरी/बैलेट के मामले में मेरा बहुत ही बैड लक है। मैं कहीं भी रहता हूँ, छ: बजे से पहले आकर बहुत निष्ठापूर्वक नोटिस डालता हूँ। आज जिन्दगी में पहली बार मेरा जीरो ऑवर की लिस्ट में नाम आया है। अन्य नये माननीय सदस्यों के मुकाबले हम बहुत अनफॉर्चुनेट हैं। मैं आज ही लोगों से पूछ रहा था, कई लोगों ने अभी तक जीरो ऑवर में आठ-आठ, दस-दस बार बोला है। मैं आज तक अपने जनपद की समस्याएं उठाने के लिए जीरो ऑवर में नहीं बोल पाया हूँ। बहुत मुश्किल से आज मेरा जीरो ऑवर की लाटरी में नाम आया है। पीएनओ में जहाँ नोटिस दिया जाता है, मैं बहुत भगवान को मानकर निष्ठापूर्वक नोटिस देता हूँ, तो आज मेरा लाटरी में नाम निकला है। आज जीरो ऑवर को काटा न जाए, अगर काटा जाए तो इसके बदले मुझे दो-चार मौके दिए जाएं। मेरा यही कहना है।

(1450/RV/SAN)

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): सर, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। पिछले दो हफ्ते से रोज मैं लॉटरी के लिए ट्राई कर रहा हूं, पर मेरा नाम ज़ीरो आवर में नहीं आ पाया। मैं परसों मौजूद था, कल भी था और कल आपने कहा था कि कल जो-जो मौजूद थे, जिन्हें ज़ीरो आवर में मौका नहीं मिला, उन्हें आप मौका देंगे and you have been very much liberal in giving chances to Members to participate in the 'Zero Hour'.

इसके साथ ही, मेरे कुलीग और सीनियर महताब जी ने प्राइवेट मेम्बर्स बिल के बारे में जो सजेशन दिया, I strongly support that क्योंकि प्राइवेट मेम्बर्स बिल के लिए मेम्बर्स बहुत प्रिपेयर होकर आते हैं। वह भी लॉटरी से ही तय होता है। इसलिए दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो केवल 20 या 30 नहीं, बल्कि जो मेम्बर्स कल ज़ीरो आवर में बोलने के लिए बैठे हुए थे या परसों बोलने के लिए बैठे हुए थे, उनमें से मैं भी एक हूं तो मुझे भी ज़ीरो आवर में बोलने का मौका दिया जाए। प्लीज, सर।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं प्रेमचन्द्रन जी से सहमत हूं कि आज लोगों के बीच यह एक प्रश्न आ रहा है कि यह जो प्राइवेट मेम्बर्स बिल है, इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि बार-बार बिल्स इंट्रोड्यूस तो होते हैं, लेकिन बहुत-से कम बिल्स चर्चा के लिए आते हैं और उनसे भी बहुत कम बिल्स को सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। हमारे इतिहास में शायद दस या ग्यारह ही प्राइवेट मेम्बर्स बिल्स ऐसे होंगे, जिन्हें सरकार ने स्वीकृत किया है। इसे बुधवार को लाकर इस पर जरूर ध्यान और समय देना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास लोकतंत्र में और पार्लियामेंट के नियमों में बना रहे। इसके लिए प्राइवेट मेम्बर्स के और बिल्स चर्चा के लिए आएं, इसके लिए भी प्रयत्न करने चाहिए।

ऐसे बिल्स, जिनके कारण देश में उन्नति और देश की प्रगति हो सकती है, उन्हें स्वीकृत करना चाहिए। मैंने भी इस सत्र में वायु प्रदूषण पर एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल डाला है। मैं उसके इंट्रोडक्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आशा करता हूं कि अगले हफ्ते उसे इंट्रोड्यूस करने का मुझे मौका मिले। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. सत्यपाल जी को जन्मदिन की शुभकामनाएँ।

मैं सभी को सुबह में ही शुभकामनाएँ दे देता हूं।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, आपने मेरे जन्मदिवस पर अपना जो आशीर्वाद दिया और जो शुभकामनाएँ दीं, इसके लिए मैं आपके प्रति अत्यन्त आभार व्यक्त करता हूं। इस सदन के सभी सम्माननीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मैं दूसरी बार चुना गया। पिछले सेशन में, यह जो लॉटरी का सिस्टम है तो मैंने बहुत बार अपना नाम दिया था, पर लॉटरी में वह निकली नहीं। मैंने एक बार शून्य काल में यह मामला उठाया कि क्या यह देश लॉटरी से चलेगा या मेरिट से चलेगा, इसे तय करना चाहिए। क्या हम यह तय कर सकते हैं कि 50 प्रतिशत विषय, जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे? मैं इस बात को बड़े दु:ख के साथ कहता हूं कि देश के लिए कुछ ऐसे गम्भीर विषय हैं। उदाहरण के लिए, इस देश में कैसी शिक्षा नीति होनी चाहिए, इस देश से आतंकवाद कैसे खत्म होगा, इस देश से नक्सलवाद कैसे खत्म होगा, इन विषयों में जो महत्वपूर्ण विषय हैं, इन्हें लॉटरी में न रखा जाए, बल्कि इन पर गम्भीर चर्चा की जाए। इसके अलावा, लगभग 50 प्रतिशत लोगों को शून्य काल में अपने विषय को रखने का मौका दिया जाए। लेकिन, केवल लॉटरी के आधार पर यहां बोला जाएगा तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो हम इस देश को मेरिट के आधार पर आगे ले जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ जुआ और लॉटरी के आधार पर चलाना चाहते हैं। इस पर भी हम लोगों को निर्णय लेना चाहिए।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सदन का बहुमत इस बात का बन रहा है, लेकिन अगर आपकी परमिशन हो तो आज शून्य काल को चार बजे तक चलाया जाए?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैंने कल भी आपको कहा था कि आपके हाथ में सब कुछ है। साढ़े तीन बजे प्राइवेट मेम्बर्स बिल्स का समय है, जो कि हमारा अधिकार भी है।

माननीय अध्यक्ष: अगर छ: बजे तक माननीय सदस्य उपस्थित रहेंगे तो साढ़े छ: बजे तक इसे करेंगे।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आपने कभी नहीं यह कहा, आप पहली बार यह कह रहे हैं कि यहां से आधे घंटे के समय की कटौती करना चाहते हैं। कुर्सी से जब कुछ कहा जाता है तो हमें भी उसे मान्यता देनी पड़ती है।

सर, इसके साथ-साथ मैं यह भी गुजारिश करूंगा कि आप इधर से आधे घंटे की कटौती कर देंगे तो आप उधर से इसकी भरपाई भी कर सकते हैं क्योंकि सदन आपके हाथ में है।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

यह मत बन गया है, आज मैंने व्यवस्था दे दी है तो हमारे सदन के फ्लोर नेता ने कहा कि आज जो व्यवस्था दे दी है, उसे रेगुलर करिए।

सदन का मत है कि प्राइवेट मेम्बर्स बिल के समय दूसरा बिजनेस कभी नहीं लिया जाएगा। क्या यही मत है न?

अनेक माननीय सदस्य: जी, हाँ।

(1455/MY/RBN)

विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में

एवं

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण – जारी

माननीय अध्यक्ष: माननीय सांसद प्रज्ञा सिंह जी।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): अध्यक्ष महोदय, मैंने दुश्मनों के द्वारा दिए गए बहुत सारे अत्याचार सहन किए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

...(व्यवधान)

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): महोदय, मैं अपनी बात तो कह सकती हूं।...(व्यवधान) मेरी पुरानी बात भी अधूरी रह गई थी।...(व्यवधान) महोदय, मैं जो कहना चाहती हूं, उसको सुनिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): महोदय, मैं देश के लिए जो करती हूं, बस उतना ही कहना चाहती हूं। मैंने 27.11.2019 को एस.पी.जी. बिल की चर्चा के दौरान नाथूराम गोडसे को देशभक्त नहीं कहा। मैंने नाम ही नहीं लिया, फिर भी किसी को ठेस पहुंचती हो, तो मैं खेद प्रकट करते हुए क्षमा चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

विशेष उल्लेख – जारी

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): अध्यक्ष महोदय, आज मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जीरो आवर के अंदर जिनकी लॉटरी खुली है, उनको बोलने का अवसर दिया।

महोदय, मैं विदेशों में पढ़ रहे हमारे देश के विभिन्न राज्यों के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार और विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। लोक सभा में एक सवाल के अनुसार देश के 6 लाख से भी अधिक छात्र-छात्राएं विभिन्न देशों में पढ़ रहे हैं। हाल ही में तीन दिन पहले अमेरिका के शिकागो में हैदराबाद की रूथ जॉर्ज नामक 19 वर्षीय छात्रा की वहां के इलीनियोस यूनिवर्सिटी कैम्पस में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। जुलाई 2018 में अमेरिका के कंसास शहर में 25 वर्षीय भारतीय छात्र शरत कप्पू की हत्या का मामला आया था। इसी शहर में वर्ष 2017 में भारतीय मूल के श्रीनिवास कुचीबोतला की हत्या कर दी गई।

महोदय, चाहे डेनमार्क में गुजरात के मेहसाणा के दो युवकों की हत्या का मामला हो, चाहे वर्ष 2008-09 और उसके बाद कई बार आस्ट्रेलिया में हिन्दुस्तान के छात्रों पर हुए हमलों का मामला हो, हम कई बार अखबारों में भारतीय छात्रों पर हमले और उनके साथ नस्लीय भेदभाव जैसी घटनाओं का जिक्र भी सुनते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने जब वर्ष 2014 में सत्ता संभाली, निश्चित रूप से भारतीय छात्रों का मान विश्व के अंदर बढ़ा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी द्वारा सत्ता संभालने के बाद विदेशों में भारतीय प्रवासी छात्रों की इज्जत बढ़ी है और उन पर होने वाले हमले की घटनाएं भी कम हुई हैं। अभी मैंने जिस प्रकार की घटनाओं का जिक्र किया, उनसे देश के लोगों का मन आहत हो जाता है। आज हमारे बीच सुषमा स्वराज जी नहीं है। देश के जो लोग खाड़ी के देशों में थे, उन्होंने सजगता से उन्हें देश में लाने का काम किया। विदेशों में भारतीय छात्रों पर जो क्राइम होता था, इस सरकार ने हिन्दुस्तान के छात्र-छात्राओं की हमेशा ही मदद की है। …(व्यवधान)

महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं विदेश मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं, तत्काल उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए संबंधित दूतावासों को पुख़्ता पाबंद करने के लिए निर्देश जारी किया जाए और सुरक्षा का एक ड्राफ्ट संबंधित देशों को भेजा जाए। मेरी मूल भावना इस मुद्दे को सदन में रखने के लिए यह थी कि हमारे देश के जो छात्र विदेशों में पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। उनके लिए देश की सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरुरत है, क्योंकि सरकार द्वारा कदम उठाने से ही विदेशों में पढ़ रहे देश के छात्र-छात्राओं का मनोबल बढ़ेगा।

महोदय, हमारे यहां जिस तरह से विदेशी छात्र-छात्राओं का सम्मान होता है। उनके लिए आई.पी.सी. के अंदर अलग से प्रावधान भी है। अगर उनके साथ बदमाशी होती है, तो उसके लिए अलग धाराएं लगती हैं। उसी तरह से बाहर पढ़ने वाले हमारे देश के छात्र-छात्राओं की सुरक्षा कैसे हो, इस बारे में मोदी जी गंभीर है। मैं विदेश मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे देश के छात्र-छात्राएं वर्ल्ड के अंदर सुरक्षित रहें, इस मामले में देश की सरकार ठोस दिशा-निर्देश जारी करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री हनुमान बैनिवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): Respected Speaker Sir, Coimbatore-Edapalli Highway 544 is one of the major Highways in Kerala. It is a four-lane road. But the route between Mannuthy and Vadakkanchery is in wretched condition. The National Highway Authority of India has given this work to contractors. But the work between Kuthiran-Mannuthy and Vadakkanchery flyover has not been completed yet. It is a very shameful thing to the Central Government.

Now, the Sabarimala season has begun. Thousands of vehicles carrying pilgrims from Tamil Nadu and other States, and pilgrims to Guruvayur pass through this road.

(1500/SM/CP)

But the vehicles are struck here due to traffic blocked for hours. The people use this route to go to Thrissur Medical College for their medical facilities. The condition of vehicles, even ambulance, has been struck here due to traffic block.

I humbly request to take positive steps to open one of the tunnels during the time of Sabarimala season with immediate effect assuring safety. 99 per centage of its work are already completed. It will be a blessing to both pilgrims and common people. I request to take further steps to complete the work of Vadakkencherry flyover.

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल की लिस्ट में उनका नाम है। आपकी मेहरबानी नहीं है। माननीय सदस्य बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): लॉटरी में नाम आया है। किसी की दया से नहीं है।…(व्यवधान) यह मेरा पर्सनल एजेंडा है।

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए, मैं चुप कराऊंगा।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): लॉटरी से नाम आया है, लिस्ट देख लीजिए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है। आप बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैं जानता हूं। वे हमारे पुराने मित्र हैं। बिहार, छोटा नागपुर, बंगाल, ओडिशा, ये जो हिंदुस्तान के स्टेट हैं, यहां लाखों की तादाद में कुर्मी लोग रहते हैं, जिनको

आदिवासी कुर्मी कहते हैं। …(व्यवधान) आदिवासी कुर्मी के बारे में यह कहा जाता है कि "कोल, कुर्मी, कोरा, वेद शास्त्र छारा"। It means, Kurmis are far from Vedic culture of aforesaid areas. They believe in totem like other Scheduled Tribes of the areas concerned and are divided in 81 main totems such as Dumariar, Bansiar etc. छोटा नागपुर, संथाल परगना, झारखंड,बंगाल और ओडिशा के विस्तीर्ण इलाके में ये लोग रहते हैं। इन लोगों की वर्षों से यह मांग है कि हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, लेकिन इन लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। अभी भी ये लोग पिछड़े वर्ग की जनजाति के रूप में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दामोदर, कांसाबती, सुबर्णलेखा, बैतरणी नदियों के आसपास इनकी घनी बस्तियां होती हैं। इनकी भाषा, वेशभूषा सब कुछ अलग होता है। इनकी कल्चरल आइडेंटिटी बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। हम चाहते हैं कि कुर्मीज़ लोग, जो इन एरियाज़ में रहते हैं, इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। उनकी वर्षों पुरानी यह मांग पूरी हो और साथ-साथ इन लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी और लैंगुएज आइडेंटिटी की रक्षा हो।

Sir, until and unless the Kurmis of Chotanagpur, Santhal Pargana of Jharkhand, West Bengal and Odisha and of its adjoining aforesaid places are scheduled in the enlistment of Scheduled Tribes, the continuance of totemistic socio-culture and heritage of this Kurmis Tribe will not be protected in its existence like the other neglected tribes of the world. इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि आदिवासी कुर्मी समाज की जो मांग है, उसे सरकार पूरा करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री सप्तगिरी उलाका और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राम शिरोमणि (श्रावस्ती): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के जिला बलरामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 730 पर झारखण्डी मंदिर रेलवे लाइन के ऊपर एक ओवर ब्रिज बनना नितान्त आवश्यक है। यह शहर का मुख्य मार्ग होने के नाते जब रेलवे क्रासिंग बंद हो जाती है, तब गाड़ियों का लंबा जाम लग जाता है, जिससे यातायात काफी बाधित हो जाता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिला बलरामपुर, उ.प्र. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 730 का सर्वे कराकर झारखण्डी मंदिर रेलवे लाइन के ऊपर ओवर ब्रिज बनाया जाए।

श्री अरूण साव (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वन धरती का श्रृंगार है और वन है तो जीवन है। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए देश में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद सरकार के प्रयासों से लगातार वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की जा रही है।

(1505/NK/AK)

वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों से लगातार वनों की अवैध कटाई का मामला सामने आ रहा है। कुछ समय पूर्व कवर्धा जिले में अवैध वन की कटाई का मामला सामने आया था। अभी-अभी मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत रतनपुर में कक्ष क्रमांक 1622 में लगभग 300 से अधिक सांगवान वृक्षों की कटाई का मामला सामने आया है।

मैं भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में वनों की अवैध कटाई रोकें, इसके साथ ही इस संबंध में राज्य सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री अरुण साव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI SAPTAGIRI ULAKA (KORAPUT): Thank you, Speaker, Sir, for letting me raise an important issue during '*Zero Hour*'.

Today, I want to raise an important issue of an unfortunate incident that has occurred in Dharmasala Block in Jajpur District in which there was a mysterious death of Shrimati Smitarani Biswal. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको भी मौका दूंगा।

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Sir, the matter being raised here is *sub-judice*. …(*Interruptions*) How can it be raised here? …(*Interruptions*) We need your protection in the matter. …(*Interruptions*)

SHRI SAPTAGIRI ULAKA (KORAPUT): She was the VLW of Haridaspur GP under Dharmasala Block in Jajpur District. …(*Interruptions*) It is mysterious because the facts behind her death are yet to be ascertained, and the suspicious manner in which the local police is investigating the matter. …(*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, it is a law and order issue of the State. …(*Interruptions*)

SHRI SAPTAGIRI ULAKA (KORAPUT): Further, it was declared as a suicide without any investigation and made public by none other than the accused himself. …(*Interruptions*) It is very sad that the Administration has accepted it, and is character-shaming the victim. …(*Interruptions*) Sir, the five main people are involved and …(*Interruptions*) We demand CBI investigation in the matter, and I would request the Home Minister to have a look at it. …(*Interruptions*)

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि यहां कन्वेंशन है कि जो ज्युडिशियल डिसीजन पेंन्डिग है या जिसका स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कशन हो चुका है, यह पूरी तरह से स्टेट मैटर है,…(व्यवधान) इसको यहां पर पार्लियामेंट में पॉलिटीकल रीजन की वजह से उठाने का कोई औचित्य नहीं है। …(व्यवधान) इनको जीरो ऑवर का एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। बैलट में जो भी

आ जाए उसके बाद आप अपना मनचाहा बोलना शुरू कर देंगे, …(व्यवधान) इसका एडवांटेज नहीं होना चाहिए। हम आपका संरक्षण चाहते हैं। It is a State matter as well as judicial proceedings. Both are pending, so he should not be allowed to raise it here.

माननीय अध्यक्ष: मैं रिकार्ड मंगा कर देख लूंगा।

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Thank you, Sir. In my Arani Parliamentary Constituency, there is dam called the Shenbaga Thoppu Dam, which was proposed by Dr. Kalaignar in 1989. Immediately after that, the other Government came and the file kept gathering dust. Again, in 1996, Dr. Kalaignar came to power and so he got all the environmental clearances and the work was about to start. Then, after the Government changed, somehow the work on the Shenbaga Thoppu Dam began, but unfortunately, they have not constructed the dam as per the specifications. The dam was so weak that as some rain came, the shutters got washed away. Finally, the shutters went into to the gutters because of the quality of construction of this dam.

Now, I would urge upon the Union Government to intervene immediately in this matter. The Jal Shakti Ministry has to intervene in the matter. In 1999, this project's cost was Rs. 30 crore. Now, the estimated cost for its repair is Rs. 30 crore. The work on this dam is pending for nearly 30 years; 4,000 hectares of irrigation land is getting dried-up; and many thousand families of agriculturists are suffering due to it. So, I would urge upon the Jal Shakti Ministry and the Government to kindly intervene in the matter and finish the work on the Shenbaga Thoppu Dam in Polur in my Arani Parliamentary Constituency. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर):अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के हर बच्चे को अधिकार है कि वह अच्छे से शिक्षित हो, अच्छी शिक्षा मिले। हमारी सरकार के यशस्वी प्रधान मंत्री के नेतृत्व में अच्छी शिक्षा के कई अच्छे प्रावधान किए हैं, जिसके माध्यम से उनको सस्ते में एनसीईआरटी की बुक उपलब्ध हो, इसके लिए कई प्रावधान सरकार ने किए हैं। सौभाग्य से माननीय एचआरडी मंत्री जी बैठे हैं। मैं इनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

एनसीईआरटी पुस्तकों का मूल्य कक्षा एक से पांच तक का दो सौ रुपये और कक्षा छह से आठ तक की पुस्तकें पांच सौ चालीस रुपये में मिल जाती हैं।

(1510/SK/SPR)

इसके अलावा वितरण के लिए 895 अधिकृत विक्रेता और मुद्रण के लिए 140 मुद्रक सूचीबद्ध हैं। घर में ऑनलाइन सेवा द्वारा पुस्तकें भिजवाने की सुविधा है,वैबसाइट पर नि:शुल्क डाउनलोड की सुविधा उलपब्ध है और ई-पाठशाला द्वारा एप्प भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो विद्यालय सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, वहां पुस्तकें 250 या 500 रुपये में मिलती हैं, लेकिन इन स्कूलों में पुस्तकें 2500 से 3500 रुपये में दी जा रही हैं। देश में प्राथमिक शिक्षा संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार को सीबीएसई के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा लोक दिखावे के नाम पर शिक्षा को व्यवसायीकरण में बदलकर देश के बच्चों के अधिकारों का खुलेआम हनन किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं और एनसीईआरटी पुस्तकों का पालन नहीं कर रहे हैं, सख्ती से पालन कराया जाए और जो पालन नहीं करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री भोला सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जम्मू-कश्मीर के लोगों की समस्या को रेल मंत्रालय के ध्यान में लाना चाहता हूं।

जम्मू-कश्मीर के लोग रोज़ाना परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हरिद्वार बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवर्ष के लोगों की आस्था हरिद्वार के साथ जुड़ी हुई है। विशेषकर उत्तरी भारत में किसी का स्वर्गवास होता है तो उसकी अस्थियां हरिद्वार में गंगा जी के दर्शन करने के बाद प्रवाहित की जाती हैं। जम्मू-कश्मीर से हरिद्वार जाने के लिए हेमकुण्ड एक्सप्रैस है, यह रोज चलती है। मंत्रालय के ध्यान में लाने के बाद एक और गाड़ी हरिद्वार एक्सप्रैस के नाम से चल रही थी, अब यह बंद हो गई है। यह गाड़ी साप्ताहिक थी।

मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से प्रार्थना है कि एक रेलगाड़ी रोज जम्मू से हरिद्वार चलाई जाए क्योंकि चाहे सूर्य ग्रहण हो, पूर्णमासी हो या अमावस्या हो, लोग हरिद्वार और गंगा माता के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मंत्रालय को आदेश दिया जाए कि हरिद्वार से जम्मू के लिए एक और ट्रेन चलाई जाए ताकि लोगों को समस्या न हो और लोग गंगा माता के दर्शन के लिए रोज जा सकें।

माननीय अध्यक्ष: जितेन्द्र सिंह जी भी आपकी बात से सहमत हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में शेखावटी का झुन्झुनू जिला रेलवे की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। झुन्झुनू जिले ने भारत को

सबसे ज्यादा सैनिक, उद्योगपति, राज्य और केंद्र सरकार में सबसे अधिक कर्मचारी और अधिकारी दिए हैं, फिर भी यह जिला रेलवे की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।

सैनिक एक्सप्रैस संख्या 14021 और 14022 सप्ताह में तीन दिन ही दिल्ली से जयपुर जाती है। मेरी मांग है कि इसे प्रतिदिन किया जाए। कोटा से जयपुर एक और ट्रेन चलने वाली है, जो हिसार से लोहारू आएगी। हम चाहते हैं कि यह ट्रेन लोहारू से झुन्झुनू होकर जयपुर जाए। उत्तर पूर्वी रेलवे द्वारा मांग भी भेजी गई है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ट्रेन हिसार से जयपुर जाए और इसके साथ ही मैं इन दोनों ट्रेनों को प्रतिदिन चलाने का निवेदन करता हूं।

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं आपके माध्यम से सदन के सामने डेढ़ करोड़ गोरखाओं की समस्या रखना चाहता हूं। हाल ही में असम में एनआरसी के प्रॉसेस के दौरान गोरखाओं की अनेक संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम छूटे हैं, इसके कारण इनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा।

(1515/MK/KMR)

गोरखाओं ने हमारे राष्ट्र निर्माण में महान योगदान दिया है। इसके बावजूद असम की एनआरसी प्रोसेस के दौरान अनेक परिवार जिनके संबंध स्वतंत्रता सेनानियों, साहित्यकारों और सैनिकों से थे, उनके भी नाम छूट गए हैं। हमारे राष्ट्र के प्रति गोरखाओं का योगदान अतुलनीय है। उन पर असम एनआरसी जैसी गलत प्रक्रिया नहीं डाली जानी चाहिए थी। मेरे क्षेत्रवासियों के दिल में बसने वाले प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने कई बार गोरखाओं की वीरता और देशभक्ति का अपने भाषणों में जिक्र किया है। देश की रक्षा के लिए उनके त्याग और बलिदान से यह सदन भलीभांति परिचित है। असम के इस एनआरसी प्रोसेस ने कई महान गोरखा फ्रीडम फाइटर के बलिदानों पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। जैसे असम के छबिलाल उपाध्याय, दार्जिलिंग के पुष्पा कुमार घिसिंग, सिक्किम के हेलेन लेपचा, कलिम्पोंग के दल बहादुर गिरी, मणिपुर के सुबेदार निरंजन छेत्री, हिमाचल के कैप्टन राम सिंह ठकुरी, उत्तराखंड के मेजर दुर्गा मल्ल जी, जिनकी प्रतिमा पार्लियामेंट कॉम्पलेक्स में स्थापित है, मेरे क्षेत्र दार्जिलिंग के श्री डम्बर सिंह गुरुंग और श्री अरी बहादुर गुरुंग जी, जो कांस्टिट्यूएंट असेम्बली के मेम्बर थे, जिन्होंने हमारे देश के संविधान की रचना में बड़ा योगदान दिया था। अत: आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि देशभक्त गोरखाओं को एसटी का दर्जा प्रदान किया जाए, उनको संरक्षण दिया जाए तथा उन्हें ओरिजिनल इनहैबिटैंट्स के रूप में मान्यता प्रदान की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री राजू बिष्ट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जॉन बर्ला (अलीपुरद्वारस): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि उत्तर बंगाल के डूअर क्षेत्र में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। पानी का जलस्तर नीचे होने के कारण कुआं और नल सभी जगह पानी उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए लोगों को केवल नदी के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। पूरे क्षेत्र में साफ जल का अभाव है। जो पानी लोगों को मिल रहा

है, वह शुद्ध न होने के कारण, लोगों में कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। विशेषकर, भूटान बार्डर क्षेत्र के पानी में डोलोमाइट अधिक मात्रा में होने के कारण लोगों को चर्म रोग और कई प्रकार की भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उपर्युक्त विषय के बारे में बंगाल सरकार को बार-बार सूचित करने के बाद भी बंगाल सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। अत: सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और छोटे-छोटे पानी की टंकी बनाकर हर घर के नल को शुद्ध जल पहुंचाया जाए। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए। धन्यवाद।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, this august House is aware of the importance of Sabarimala temple. Festival season has already started at Sabarimala temple. Lakhs and lakhs of devotees are everyday coming to Sabarimala for a darshan of the deity. However, Sabarimala temple is facing a lot of problems and the House is also very much aware of that.

Sir, more than four to five crore devotees come to Sabarimala shrine every season. The Government of Kerala and the Travancore Devaswom Board had requested the Ministry of Environment and Forests of the Government of India to hand over sufficient forest land in that area so that lakhs and lakhs of devotees visiting Sabarimala temple can be facilitated. The entire surrounding area is a forest area as a result of which the Travancore Devaswom Board is unable to accommodate the pilgrims at present. Hon. Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri Kishan Reddy, is very much aware of this problem because majority of the devotees are coming from the State of Andhra Pradesh. I would request the Government of India, Ministry of Forests and Environment, to hand over sufficient land for the development of Sabarimala.

Also, Sabarimala temple is included by the Ministry of Tourism of the Government of India in its list of pilgrim centres. The Government of India promised an allocation of Rs.100 crore for the development of Sabarimala but unfortunately that amount has not been released so far.

(1520/SNT/RPS)

Another important subject is Sabari Rail Project. During the Vajpayee Ji's Government, the Government of India had announced a Sabari Rail Project to provide connectivity to devotees who visit Sabarimala from various parts of the country. During 1999-2000, I was also the Member of Parliament, but, unfortunately, that railway line is yet to be completed. That project is still going very very slowly. The Ministry of Railways is asking the State Government to

contribute its share for the project. Then only, they will complete the project. The Government of Kerala is also facing severe financial crisis. That is the difficulty. How the Government of Kerala can contribute for the project? When the project was announced, it was decided that the full amount of the expenditure will be borne by the Railway Ministry. Now, the Railway Ministry has changed its stand. The Railway Ministry is asking the State Government to contribute its share for the Sabarimala Rail Project.

Sir, another thing is regarding Sabarimala air connectivity. There is a proposal for setting up an airport in Aranmula. I would like to request the Union Government, through you, Sir, to set up an airport in Central Travancore area to provide air connectivity to Sabarimala. Earlier, there was a proposal to set up an airport in Aranmula. Now, another proposal has come from the State Government to set up an airport in Erumely.

I would also like to mention Pamba river. It is a holy river just like Ganga. Around, 4-5 crore Ayyappa devotees come and bath in Pamba river before going to Shrine. So, the water of Pamba river gets polluted and contaminated. There is no scheme for cleaning Pamba river. So, I would like to request the Union Government to implement Pamba Action Plan. There is a proposal before the Government to implement Pamba Action Plan.

Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज जीरो ऑवर को रिटेन किया, जिससे मुझे बोलने का मौका मिला।

बनारस के पड़ोस में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेरा जौनपुर एक बहुत खूबसूरत सा जिला है। उसकी बहुत-सी समस्याएं हैं और ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी समस्या वहां पर है। रेलवे विभाग पैसेंजर्स को ढोने का, ले जाने का बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जौनपुर की ट्रैफिक की समस्या को बढ़ाने में रेलवे विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। जौनपुर से मिर्जापुर, जौनपुर से वाराणसी, जौनपुर से आजमगढ़-गाजीपुर, जौनपुर से लखनऊ और जौनपुर से प्रयागराज, इन सभी रोड्स पर रेलवे की क्रॉसिंग्स हैं। यह जौनपुर की एक विशेष समस्या है, जिसे रेलवे विभाग ने क्रिएट कर रखा है। कहीं-कहीं एक की जगह, दो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, जैसे बनारस रोड पर। जौनपुर से मिर्जापुर रोड पर, जो जौनपुर सिटी का फ्लाईओवर बन रहा है, वह वर्ष 2013 से बन रहा है। वहां रेलवे क्रॉसिंग बन्द कर दी गई है और जैसे हम लोग एक कहावत सुनते आए हैं – 'बीरबल की खिचड़ी' की तरह वह बन रहा है। आज तक वह आधा भी नहीं बना है और सारे लोग वहां दस किलोमीटर चक्कर काटकर जाते हैं।

इससे भी ज्यादा खराब स्थिति यह है कि प्रयागराज रोड पर फ्लाईओवर सैंक्शन तो हो गया है, लेकिन वह कब बनना शुरू होगा, आज तक इसका पता नहीं है। वहां लोगों का इतना धन, जन, समय, फ्युल आदि की इतनी बर्बादी होती है कि अगर आप उसे कैलकुलेट करिए तो जितना उससे फायदा नहीं होगा, इतना आलरेडी नुकसान हो चुका है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और विशेष रूप से आपसे विनती है कि कम से कम जौनपुर से मड़ियाहूं और जौनपुर से प्रयागराज रोड के फ्लाईओवर ब्रिज को शीघ्र से शीघ्र बनवाया जाए। …(व्यवधान) मान्यवर, मेरे सिलसिले में आपकी घण्टी जल्दी बज गई है, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। पहले जौनपुर में एक गन्ना मिल हुआ करती थी, जो बन्द चल रही है। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करूंगा कि एक नई गन्ना मिल की जौनपुर में स्थापना हो। इसके साथ ही, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लेकिन वह भी बहुत धीमी गति से बन रहा है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दें कि मेडिकल कॉलेज को भी शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कराएं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री श्याम सिंह यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1525/IND/GM)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है और मेरा सौभाग्य है कि श्री जितेन्द्र सिंह जी सदन में हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस विषय को उठा रहा हूं। देश और विदेश के करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र शारदापीठ है। पूरे देश में 18 शारदापीठों में से एक शारदापीठ लाइन ऑफ कंट्रोल से 10 किलोमीटर अंदर है। हम अपनी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि बरसों से लोगों की इच्छा थी, न केवल हिंदुस्तान के सिखों की बल्कि पूरी दुनिया के सिखों की इच्छा थी कि करतारपुर कोरिडोर खुले। जैसे बहुत-सी असंभव चीजें धारा 370, अनुच्छेद 35ए या अयोध्या फैसला हो, इसी तरह से एक असंभव चीज को करने का काम भारत सरकार ने करतारपुर कोरिडोर को खोल कर किया है। जब करतारपुर साहब का कोरिडोर खुल गया, तो हम सभी को आशा और उम्मीद बंधी है कि जिस जगह पर आदि शंकराचार्य जी गए हों, जिस पर रामनुजाचार्य गए हों या जहां देश और दुनिया के बड़े-बड़े संत गए हैं, उन शारदापीठ पर, चाहे कल्हण हों, कुमारजीव, थुनामी समोता हो, ऐसे-ऐसे स्कार्ल्स हैं, जिन्होंने शारदा स्क्रिप्ट लिखी। आज भी गुरमुखी के हमारे सिख साथी हैं, उन्होंने भी गुरमुखी में शारदा स्क्रिप्ट के अंदर इतनी चीजों का प्रयोग किया गया है कि आज कहा जाता है कि जैसे गुरमुखी में संस्कृत के शब्द हैं, वैसे ही उसमें शारदा स्क्रिप्ट के शब्द है। आज जम्मू-कश्मीर में शारदा स्क्रिप्ट का उपयोग पूजा-पाठ में होता है और जिस तरह से आदि शंकराचार्य जी प्रपंच सार लिखा, पूरी दुनिया में उस पर रिसर्च हो रही है।

महोदय, मैं ऐसी चीज का उल्लेख कर रहा हूं जिसमें मैं आपका भी समर्थन चाहता हूं। यह विषय सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष का भी नहीं है। इस विषय में सारे सदन की, पूरे देश की और दुनिया में रहने वाले सभी भारतीयों की भावनाएं एक हैं, जिन्हें शारदापीठ के प्रति आस्था है। श्री जितेन्द्र सिंह

जी बैठे हैं, Kashmiri pandits believe that Sharda in Kashmir is the tripartite environment of the Goddess Shakti. Sharda is the Goddess of Learning; Sarasvati is the Goddess of Knowledge, and Vagdevi is the Goddess of Speech which articulates power. आज स्पीच हो, नॉलेज हो, लर्निंग हो, उसके यदि प्रतीक हैं तो आदि शक्ति शारदापीठ हैं और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को अंगीकार करेगी। यह अवैध रूप से पाकिस्तान ऑकोपाइड कश्मीर के पास है, यह उनके हिस्से में नहीं है। यह बात जितेन्द्र सिंह जी कह चुके हैं कि वह हमारा हिस्सा है और हम उसे लेकर रहेंगे। निश्चित रूप सरकार हमारी भावनाओं को ध्यान में रखेगी कि शारदापीठ का भी कोरिडोर खुलना चाहिए क्योंकि वह हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र बिंदु है।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रमा देवी और डॉ. सत्यपाल सिंह को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Speaker, Sir, thank you for allowing me to place an important issue about one of the major problems of almost all the women in the world. The role of women in this world is so diverse and multi-functional that they are subject to accept a new kind of responsibility every now and then. According to the census of 2011, the urban and metropolitan population of women in Chennai was almost 43 lakhs which would have definitely increased manifold by now. We are proud multi-taskers but the amount of pressure we undergo when we need to balance our home and career is so acute that most of the women fall prey to depression; and mental health is one of the major problems faced by women all over the world. Talking about it openly is still considered a taboo. Therefore, I would like to suggest the Government to establish counselling centres or welfare centres under the Nirbhaya fund and the One Step Centres to attend to the mental well-being of women as well by appointing a full-time psychologist using the remaining funds allocated. According to the official data, States and Union Territories have utilized less than 20 per cent of the budget allocated to them under the Nirbhaya fund for the safety of women by the Central Government between 2015 and 2018. Additionally, I would like the Government to urge the States to establish more One Step Centres in Chennai as there is only one such facility for more than 40 lakh women residing in Chennai, especially none in my South Chennai constituency which is a big one. Therefore, I would like to request the Minister of Women and Child Development to take the suggestion and to make necessary implements.

HON. SPEAKER: Shri Kuldeep Rai Sharma and Shrimati Vanga Geetha Viswanath are permitted to associate with the issue raised by Dr. Thamizhachi Thangapandian.

(1530/ASA/RSG)

*SHRI JAGANNATH SARKAR (RANAGHAT): Hon. Speaker Sir, my Ranaghat Lok Sabha constituency is a bordering area adjoining Bangladesh. As it is a border area, smuggling, cattle trafficking, drug peddling used to be a regular affair. At present, because of the stringent actions taken by the Central Government, the situation is a bit under control. However everyday about 200 to 300 cows are detained and these are transferred to the temporary camps. But there is no proper arrangement for their upkeep, medical treatment or fodder in those shelters as a result of which, on an average 15 to 20 cows die daily. Moreover the farmers also face difficulties in performing agricultural activities on the cultivable land on the other side of the barbed wire fencing. These are the two major problems regarding which I had a talk with the State Government but the issues could not be solved. There is lack of proper system to take care of these cows, to feed them. The Central Government must take appropriate steps to stop such untimely deaths of cattle. It should also issue special permanent permits to the agriculturists to cross over the border to undertake farming activities. This will prove to be extremely beneficial to the common people of the region. Thank you Sir for allowing me to raise this urgent matter in this august House.

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस सदन में नॉर्थ-बंगाल के टी-गार्डन के गंभीर विषय को उठाना चाहती हूं। बंगाल में टी-गार्डन जो सबसे बड़ा उद्योग था, आज वह सबसे बड़ी मुसीबत हो गया है। तीन लाख से ज्यादा श्रमिक उसमें काम करते हैं और 20 लाख से ज्यादा लोग चाय बागान से जुड़े हुए हैं। टोटल नॉर्थ-बंगाल में 300 चाय बागान हैं और उसमें 200 चाय बागान बंद हो गए हैं। अभी जो श्रमिक हैं, उनको 176 हजीरा मिलता है, लेकिन जो प्लांटेशन लेबर एक्ट है, उसमें जो मिलता है, वह श्रमिक लोगों तक नहीं पहुंचता है। राशन, दवाई, जूते, पीने का पानी और घर कुछ भी नहीं मिलता है। वे कहते हैं कि यह सारा पैसा टी-गार्डन के मालिक को जाता है, नहीं तो सरकार के जो दलाल हैं, उनके पास जाता है। अभी मैं कुछ दिन पहले वहां गई थी, उन्होंने बताया कि 150 से 200 साल से इन श्रमिक लोगों के परिवार इन चाय बागानों में बहुत मेहनत

* Original in Bengali.

करते आए हैं लेकिन मालिक बदल जाता है और जो श्रमिक 200 साल से मेहनत करते आ रहे हैं, उनके पास अपनी जमीन भी नहीं है। उनका अपना मकान भी नहीं है। सब लोगों को घर देते हैं लेकिन टी-गार्डन वाले श्रमिकों को कुछ भी नहीं देते हैं।

अभी जब पूजा का समय आता है, जब प्रोविडेंट फंड और सैलरी का टाइम आता है, तो मालिक लोग भाग जाते हैं। उसके बाद जो श्रमिक लोग हैं, रास्ते में आकर आंदोलन करके अपनी आवाज उठाते हैं, तब पुलिस लोग आकर श्रमिकों को पकड़ लेती है और उन पर केस दर्ज कर देते हैं। लेकिन मालिकों को नहीं पकड़ते हैं क्योंकि मालिक के साथ प्रशासन का पूरा कनैक्शन होता है। इसकी वजह से दार्जिलिंग, जलपाईगुढ़ी और अलीपुरद्वार में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं। ये लोग दूसरा काम ढूंढ़ने के लिए दूसरे शहर में चले जाते हैं और खराब काम में इनवॉल्व हो जाते हैं। महिला श्रमिक सबसे ज्यादा टी-गार्डन में हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि टी-गार्डन में एक हाइ-पॉवर्ड कमेटी होनी चाहिए जिससे तथ्यों का पता चल सके और उस कमेटी में टी-गार्डन और टी-बोर्ड का एक-एक जनप्रतिनिधि होना चाहिए और यूनियन का भी एक जनप्रतिनिधि होना चाहिए जिससे टी-गार्डन की जो समस्याएं हैं, उनको दूर कर सकें।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती लॉकेट चटर्जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले दो दिन में जिस तरीके से बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि हुई है, उससे मेरे क्षेत्र अमरोहा में भी बहुत ज्यादा किसानों की फसल बर्बाद हुई है।

(1535/VB/RK)

खास तौर से जो आलू के किसान हैं, सरसों के किसान हैं, उनकी पूरी फसल नष्ट हो गई है। सरकार से मेरी गुजारिश है कि पिछले वर्ष भी, मैं उदाहरण दूँगा, आलू के किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। प्रदेश सरकार ने घोषणा भी की थी कि हम खरीददारी के लिए उनकी मदद करेंगे, लेकिन किसानों को कोई मदद न प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है, न ही केन्द्र सरकार द्वारा दी गई है। किसान पहले से ही बहुत परेशान हैं और पता नहीं क्यों, प्रकृति भी उनका साथ नहीं दे रही है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि किसानों के लिए, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कुछ-न-कुछ सोचें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप इस पर लोक सभा में चर्चा के लिए अलाऊ करें कि देशभर में जो किसानों की समस्याएँ हैं, उन पर चार-घंटे यहाँ चर्चा होनी चाहिए। सरकार किसी पॉलिसी के तहत उनको मदद दे, क्योंकि कई ऐसी फसलें हैं, जिनकी सरकारी खरीदारी नहीं होती है। ऑन-पेपर तो यह कहा जाता है कि सरकार प्रोक्योरमेंट कर रही है। मैं किसी पार्टी की सरकार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन किसानों के साथ सौतेला व्यवहार इस देश में होता रहा है।

मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से मेरी बात सरकार तक पहुँचेगी।

बहुत-बहुत शुक्रिया।

کنور دانش علی (امروہہ): محترم اسپیکر صاحب، مغربی اتر پردیش میں پچھلے دو دن میں جس طریقے سے بے موسم برسات اور اولا باری ہوئی، اس سے میرے پارلیمانی حلقہ امروہہ میں بھی بہت زیادہ کسانوں کی فصل برباد ہوئی ہے۔

خاص طور سے جو آلو کے کسان ہیں، سرسوں کے کسان ہیں، ان کی پوری فصل برباد ہو گئی ہے۔ سرکار سے میر گزارش ہے کہ پچھلے سال بھی میں مثال دوں گا، آلو کے کسان پوری طرح سے برباد ہو گئے تھے۔ پردیش سرکار نے اعلان کیا تھا کہ ہم خریداری کے لے ان کی مدد کریں گے، لیکن کسانوں کو نہ ریاستی سرکار کے ذریعہ مدد دی گئی اور نہ مرکزی سرکار کے ذریعہ دی گئی ہے۔ کسان پہلے سے ہی بہت پریشان ہیں اور پتہ نہیں کیوں، قدرت بھی ان کا ساتھ نہیں دی رہی ہے۔

میری آپ کے ذریعہ سرکار سے گزارش ہے کہ کسانوں کے لئے خاص طور سے مغربی اُتر پردیش کے کسانوں کے لئے کچھ نہ کچھ سوچیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ اس پر لوک سبھا میں بحث کے لئے اجازت دیں کہ ملک میں جو کسانوں کے مسئلے ہیں، ان پر چار گھنٹے یہاں بحث ہونی چاہئیے۔ سرکار کسی پالیسی کے تحت ان کو مدد مہیا کروائےکیونکہ کئی ایسی فصلیں ہیں جن کی سرکاری خریداری نہیں ہوتی ہے۔ آن پیپر تو یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار پروکیورمینٹ کر رہی ہے۔ میں کسی پارٹی کی سرکار کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ کسی کی بھی سرکار رہی ہو، لیکن کسانوں کے ساتھ سوتیلا برتاؤ اس ملک میں ہوتا رہا ہے۔

مجھے امید ہے کہ آپ کے ذریعہ میری بات سرکار تک پہنچ جائے گی۔ بہت بہت شکریہ ۔۔

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

गत् 19 नवम्बर को मेरा एक अन-स्टार्ड क्वेश्चन था- क्वेश्चन नम्बर 234. उसका जवाब मिला है कि असम में 1043 फॉरेन नेशनल्स डिटेंशन कैम्प में हैं। उनमें से 1025 लोग बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, 18 म्यांमार के नेशनल्स हैं। होम मिनिस्ट्री ने यह जो डाटा दिया है, इसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि एक व्हाइट पेपर भी होना चाहिए। ग्वालपाड़ा डिटेंशन कैम्प में पोना मुण्डा का देहांत हुआ। पोना मुण्डा किस देश के नागरिक थे, वे बांग्लादेश के थे या म्यांमार के थे? यह सरकार

बांग्लादेश में हिन्दुओं का जो हैरेसमेंट होता है, उस पर बात करती है, लेकिन दुलाल पाल और फालू दास का देहांत डिटेंशन कैम्प में हुआ। इन दोनों का क्रिमेशन असम में हिन्दुस्तान की धरती पर हुआ और उनकी फैमिली के लिए यह लॉस समझा गया।

महोदय, इसलिए एक व्हाइट पेपर होना चाहिए। फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के जितने भी जज़मेंट्स हैं, उनको सदन के पटल पर रखना चाहिए।

श्री निसिथ प्रामाणिक (कूचबिहार): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि पूरे भारत में साढ़े तीन करोड़ लोग राजवंशी समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इसमें ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और मेघालय में जीवनयापन करते हैं।

राजवंशी भाषा लोगों में अपनापन, मिठास और मधुरता पैदा करने वाली भाषा है। यह मधुर भाषा विलुप्त न हो जाए, इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस भाषा को आठवीं अनुसूची में एक जनजातीय भाषा के रूप में भारत की भाषा सूची में जगह दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. सुकान्त मजूमदार को श्री निसिथ प्रामाणिक द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि हमारे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र प्रतापगढ़ में पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना व सौभाग्य योजना पूर्ववर्ती सपा सरकार की नीतियों के कारण पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सभी गरीब तबके के वंचित लोगों को नि:शुल्क कनेक्शन देने की योजना को स्थानीय अधिकारियों, कार्यदायी संस्थाओं ने बड़े पैमाने पर आकंठ भ्रष्टाचार फैलाकर अधर में छोड़ दिया। प्रतापगढ़ में आज की तारीख में लगभग 1500 मजरे विद्युतीकरण से पूरी तरह वंचित हैं और लाखों की संख्या में सौभाग्य योजना में फार्म भरकर देने वाले ग्रामीण किसान, मजदूर, गरीब तबके के लोग कनेक्शन पाने की राह देख रहे हैं। बगैर कनेक्शन दिए ही तमाम घरों में मीटर लगा दिए गए और गरीबों को बिजली का बिल आने लगा और वे बेचारे मारे-मारे फिर रहे हैं।

(1540/PC/PS)

भारत सरकार द्वारा विद्युतीकरण की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2019 घोषित कर दी गई है। प्रतापगढ़ में काम करने वाली कंपनियों ने कामकाज के नाम पर कार्य पूरा दिखाकर पैसों का बंदरबाट कर दिया है। अगर इसकी जांच की गई तो इसमें वर्षों बीत जाएंगे और फिर बाद में कभी भी उनका विद्युतीकरण नहीं हो पाएगा।

इसलिए, मेरी सरकार से मांग है कि प्रतापगढ़ जनपद में सभी छूटे हुए मजरों का तत्काल विद्युतीकरण कराया जाए और पूर्व में हुए घोटालों की जांच कराकर दोषियों को दंडित किया जाए तथा सौभाग्य योजना के तहत आवेदन करने वालों को तत्काल नि:शुल्क कनेक्शन दिलाया जाए।

धन्यवाद।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Hon. Speaker, Sir, a drastic fall in the price of black pepper is the main concern of farmers in Kerala and especially in my area, which is the maximum pepper-producing region.

Sir, the prices of pepper crashed down in the year 2017 and now, in 2019, it is at Rs. 290. The main reason behind the fall in price is the unlimited import of Vietnamese pepper through Sri Lanka.

Our Directorate General of Foreign Trade issued a notification of MIP for pepper at Rs. 500 per kg. for protecting our domestic farmers and to prevent unlimited import of Sri Lankan pepper. However, it is necessary to strengthen the implementation of MIP in its true spirit. Despite the imposition of MIP at Rs. 500 per kg., our farmers have already expressed their concerns about the increasing rate of import of Vietnamese pepper.

As per the South Asian Free Trade Agreement, Sri Lanka can easily export up to 2,500 tonnes of pepper without any duty. About 8 per cent duty is applicable when the quantity is beyond 2,500 tonnes. It means that Sri Lankan traders can re-export the Vietnamese pepper easily.

Therefore, I urge upon the Government to increase the MIP rate to Rs. 750 per kg. Thank you.

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Thank you, hon. Speaker, Sir.

I am requesting for exemption of GST on Life Insurance premiums all over India. The Government of India had rolled out the Goods and Services Tax (GST) from July, 2017. The GST on all essential items like food-grains, pulses, vegetables and milk, have been fixed at zero. After food, clothing and shelter, insurance protection is an important need of the people. As such, encouragement of savings by giving tax incentives on insurance schemes, is highly considerable. This will help in greater insurance penetration in the country.

The insurance not only provides the necessary financial security to the family of the policy holder, in case of untimely death of the policy holder, but also helps the Government in investing the long-term savings of the people in nation-building.

Sir, at present, as on date, the GST on term insurance, GST on health insurance and the GST on insurance products, have been fixed at 18 per cent. The GST on new business premiums, the GST on single premium for life and the GST on pension products have been fixed at 4.5 per cent. A GST of 2.25

per cent is fixed for renewal premiums. Lastly, a GST of 18 per cent is fixed on single premium annuity.

Imposing GST on Life Insurance products and premiums will be burdensome and also a huge disincentive for savings.

Through you, on behalf of a large number of policy holders all over of India, I would like to request the hon. Finance Minister to exempt insurance policies from GST.

(1545/KDS/RU)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): बहुत-बहुत शुक्रिया सर। मैं किशनगंज से हूं और किशनगंज से एनएच31 जाता है, जो भारत को नॉर्थ-ईस्ट से जोड़ता है, जिस कारण ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इस पर बायपास बनाने की बात चल रही थी, जिसकी जगह एक फ्लाई ओवर बन रहा है। उसकी वजह से बाय-लेन में कंजेशन रहता है और उस कारण एक्सिडेंट्स होते हैं। ड्रेनेज नहीं है, जिस कारण पानी भर जाता है। अत: आपके माध्यम से मेरी गुजारिश है कि श्री गडकरी साहब की मिनिस्ट्री से बायपास का निर्माण करवाया जाए तथा ड्रेन बनवाई जाए।

महोदय, इसके अलावा मैंने एक सप्लिमेंट्री मांगा था, जिसमें मुझे फॉरेस्ट्री के संबंध में बात रखनी थी। देश में 21.3 प्रतिशत फॉरेस्ट्स हैं और बिहार में मात्र 7 प्रतिशत फॉरेस्ट्स हैं। यही नहीं, अगर हम आंकड़े देखें तो पता चलता है कि हमारे यहां सिर्फ 7 सैंक्च्युअरीज हैं, जबकि पूरे भारत में टोटल सैंक्च्युअरीज और नैशनल पार्क 650 हैं। अत: मेरी गुजारिश है कि फॉरेस्ट एरिया, जैसे चिछोराझार, टेढ़ागाछ जो मेरे संसदीय क्षेत्र में है, वह काफी पुराना फॉरेस्ट एरिया है। यह नेपाल से जुड़ा हुआ है। मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि इसे सैंक्च्युअरी घोषित किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए। उसी के तहत ठाकुरगंज में कछुदाह झील है, जिसके लगभग 200 एकड़ पानी में माइग्रेट्री बर्ड्स आती हैं, इसे भी सैंक्च्युअरी बनाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI BRIJENDRA SINGH (HISAR): Sir, it has come to light recently that a large quantity of paddy is being procured fictitiously by the rice millers in Haryana. The total estimated production of paddy in Haryana is 58 Lakh Metric Tonnes. Out of this, more than 50 per cent is Basmati, and Basmati is not procured by the Government. Against this procurable 25 LMT to 30 LMT of estimated paddy production, more than 63.8 LMT has already been procured. Quite a lot of paddy from neighbouring States finds its way to Haryana mandis. But what is really disturbing is that a large quantity of this paddy is actually rice siphoned off from the Public Distribution System of the consuming States and is then ploughed back to the FCI as Custom Milled Rice (CMR).

The State Government of Haryana has already ordered a comprehensive investigation into the matter. However, I would urge the Minister of Food and

Public Distribution to act on this issue in a decisive manner, maybe, by having its own independent investigation preferably by a third party, as it is ultimately the FCI which is paying for all these procurements. The FCI should also device a sound mechanism to ensure that there is no recurrence of such organised graft in the name of farmers.

Also, the Ministry of Food and Public Distribution needs to take up the matter with the consuming States wherefrom the PDS rice, meant for the poor, is being siphoned off in bulk quantities and being sold back again to FCI as CMR.

I thank you once again, Sir.

माननीय अध्यक्ष: डॉ बी.वी. सत्यावती, उपस्थित नहीं।

श्रीमती रंजीता कोली, उपस्थित नहीं।

श्री तापिर गाव।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): मैं अपनी कॉंस्टीट्यूएंसी और अपने स्टेट से हटकर देशहित में अपनी बात इस सदन में रखना चाहता हूं। मिनिस्टर साहब भी यहां हैं। मेरी आवाज भारतवर्ष की बेटियों की पुकार है। आज मोदी जी के 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' मिशन में हम शामिल हैं। देश भर में सैनिक स्कूल हैं। उनमें से एक-दो स्कूलों में को-एजुकेशन है, बाकी सैनिक स्कूलों में पढ़ने से हमारी बेटियां वंचित हैं। एयर फोर्स में हमने महिलाओं को कॉंबैट ऑपरेशन में डाला है और पैरा मिलिट्री में हमने अपनी बहनों को कॉंबैट ऑपरेशन में डाला है।

(1550/MM/NKL)

क्यों न हम अपनी बेटियों को, जहां-जहां भी सैनिक स्कूल हैं, उनको को-एजुकेशन करने का ऑर्डर दिया जाए। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" मिशन मोदी जी के नेतृत्व में हम चला रहे हैं तो हर प्रदेश में न सही, हर जोन में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और पूरे भारतवर्ष में बेटियों के लिए सैनिक स्कूल खोले जाएं। इससे आने वाले समाज में, पैरामिलिट्री फोर्सेस, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में हमारी बेटियों का भविष्य बुलंद हो सकेगा। इसके लिए मैं सरकार के सामने और इस सदन में इस इश्यू को रखता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : जो भी माननीय सदस्य अपने को एसोसिएट करना चाहते हैं, वह टेबल पर लिखकर दे दिया करें।

श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री रितेश पाण्डेय, श्री अनुभव मोहंती और श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ को श्री तापिर गाव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Respected Speaker Sir, thank you very much for giving me an opportunity to bring to the notice of the House as well as the Government, a matter of urgent public importance, connected with three Parliamentary Constituencies in Kerala.

Sir, National Highway 85, that is, from Kochi-Dhanushkodi passes through the Parliamentary Constituencies of Kottayam, Ernakulum and Chalakudy. The stretch of this National Highway from Mattakuzhy to Thrippunithura has regular traffic jams every day for hours. Hundreds of vehicles are held up for hours, and thousands of passengers are affected. This part of this road is very narrow and has several curves. There are hundreds of residential and commercial buildings. There is no scope for widening the existing road. Hence, a proposal for a Bye-Pass of a total length of 8.23 kilometres is pending for more than 35 years, that is, more than three decades. Land acquisition is partially complete. A proposal for an estimated cost of Rs. 552 crore was submitted to the Government of India, but it has not yet been sanctioned.

Sir, NH-85 is included in the Bharatmala Scheme of the Government of India but the Thrippunithura Bye-Pass which is a Bye-Pass to NH-85 is not included in it.

Therefore, through the medium of this august House, I request the Ministry of Road, Transport and Highways, Government of India to also include Thrippunithura Bye-Pass under the Bharatmala Scheme of the Government for the redressal of the grievances of thousands of people at the earliest. Thank you very much.

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Thank you, hon. Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak on a very important subject, that is, establishment of food processing units in rural areas, especially in my constituency, Anakapalle.

Sir, so many things like turmeric, jaggery, spices and *Pippal Mool Modi*, that is specially from Madugula constituency, are being brought from agency areas. If you would establish food processing units, especially for turmeric, jaggery, spices and *Pippal Mool Modi*, a lot of opportunities will be created for the rural women and also for the youth, to start small scale industries. They are very much interested in it.

So, through you, my request to the Ministry of Food Processing Industries is to establish food processing units in my Anakapalle constituency, especially in Vaddadi-Madugula which is very near to Araku Parliamentary constituency, so that we can import all these things. Thank you very much.

माननीय सदस्य : माननीय सदस्यगण, अब समय बहुत कम बचा है और मैं चाहता हूं कि यह सूची पूरी हो जाए। इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि एक मिनट में अपने विषय को रख दें। अगर बहुत लम्बा विषय है तो आप लोग मुझे अलग से नोटिस दे दें। मैं उस पर अलग से विचार कर लूंगा। इसलिए आप एक मिनट में अपनी बात कह दें। श्री अनुभव मोहंती।

(1555/SJN/KKD)

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Sir, thank you so much for giving me this opportunity to speak during *Zero Hour*. I must salute you for the patience that you are having, and there is so much to learn from you, as a young parliamentarian.

India recently celebrated its 72nd Independence Day with great fanfare, but unfortunately the people of Kendrapara, Odisha, which is my Parliamentary Constituency, have not seen a railway line or a *railgari* till now in Kendrapara in their lifetime. But now that dream is going to be fulfilled by the efforts of our beloved Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, Sir, and with the cooperation of the hon. Railway Minister, Shri Piyush Goyal-ji. The railway line will be commissioned in Kendrapara by February, 2020 of which the Railway Minister and the senior officials had assured me during my informal meeting with them just a few days back.

Sir, I must thank our hon. Chief Minister and the hon. Railway Minister for this. But there is a small request at the same time, and it is very polite, earnest and humble, that if possible, instead of the goods train being commissioned, a passenger train may be commissioned, and thereafter, the goods train can also be commissioned simultaneously. Otherwise, once the goods train is commissioned, the required formalities for starting a passenger train may be completed as soon as possible and the passenger train can also be commissioned.

Sir, I can assure you that once the passenger train is commissioned taking Kendrapara, which is my Constituency, in the loop, the tourism of Kendrapara is going to progress by leaps and bounds because of its heritage, National Crocodile Park, the sea coasts and other places in Kendrapara, which are really so much attractive. Employment shall also be generated and new industries will come up.

So, through you, Sir, it is my earnest appeal to the hon. Railway Minister to kindly consider my request. महोदय, 72 सालों के बाद केन्द्रपाड़ा के लोग जल्दी से जल्दी रेलगाड़ी को देख सकें और उसकी सुविधाएं पा सकें। That is my sincere request as their representative. Thank you so much.

माननीय अध्यक्ष : श्री रितेश पाण्डेय। पहले एक मिनट वाले बोल लें और उसके बाद पांच मिनट वाले बोलिएगा।

…(व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यहां पर अम्बेडकर नगर के नौजवानों के लिए खड़ा हुआ हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मेरे संसदीय क्षेत्र अम्बेडकर नगर में उच्च शिक्षा के संस्थान बद से बदतर स्थिति में पहुंचते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन और देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन पहुंचाने का सपना दिखाने वाली यह सरकार बिना उच्च शिक्षा को सुदृढ़ किए हुए वहां तक नहीं पहुंच सकती है। महामाया कालेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में डीन और प्रोफेसरों के पद खाली पड़े हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा में हाल ही में 85वें दीक्षांत समारोह में बिना रिज़ल्ट डिक्लेयर किए और बिना मार्कशीट्स दिए डिग्रियां बांट दी गई हैं। नौ मेडिकल कालेजों में 395 पद खाली पड़े हुए हैं। गोरखपुर, आज़मगढ़, मेरठ और झांसी के मेडिकल कालेजों में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं।

मान्यवर, इस देश को आगे पहुंचाने और इस देश के भविष्य को सुधारने के लिए हम बिना उच्च शिक्षा को सुदृढ़ किए हुए ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए, इस देश के नौजवानों को आगे पहुंचाने के लिए मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि हम अपने देश की उच्च शिक्षा के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारें और टीचरों के पदों पर तुरंत नियुक्ति देकर हमारे नौजवानों के भविष्य को सुधारने का काम करें।

श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल (लद्दाख) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यूनियन टेरिटोरी ऑफ लद्दाख की उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था ठीक न होने के कारण हमारे यहां के लगभग 50,000 स्टूडेंट्स बाहर के शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं। इसकी वजह से financial burden, cultural degradation, as well as mental stress होता है।…(व्यवधान) इन सबको देखते हुए इसी मोदी सरकार ने लद्दाख में यूनिवर्सिटीज़ घोषित की हैं। दो डिग्री कालेजेज़ घोषित किए गए हैं और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई है। इसके साथ ही साथ मेडिकल कालेजेज़ भी घोषित किए गए हैं। मैं इन सबके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। अभी जम्मू-कश्मीर से लद्दाख के अलग होने के बाद लद्दाख में जो अर्स्टाइल अंडर रूसा के तहत यूनिवर्सिटी घोषित हुई है, उसको सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए।

दूसरा, लद्दाख में जो डिग्री कालेजज़ मौजूद हैं, उनमें जम्मू-कश्मीर सरकार ने हमें जो विषय नहीं दिए थे, उन सभी विषयों को इंट्रोड्यूज़ किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को कालेज एजूकेशन के लिए बाहर न जाना पड़े। मैं जल्दी-जल्दी बोल रहा हूं। तीसरा, जो मेडिकल कालेज अनाउंस हुआ है, उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर बनने में थोड़ा टाईम लगेगा, लेकिन तब तक वहां के मौजूदा जिला अस्पतालों में मेडिकल की क्लासें चलाई जाएं। चौथा, जिस सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, मैं उसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वीसी की पोस्ट को भी क्रिएट किया गया है, जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट की थी। अब उस सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ

बुद्धिस्ट स्टडीज़ को यूजीसी के अंतर्गत लाया गया है और यूजीसी के जो बेनिफिट्स हैं, वे वहां के अध्यापकों और छात्रों को मिल रहे हैं। इसी तरह से लद्दाख की उच्च शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से चल सके, मैं ऐसा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं।

(1600/GG/RP)

सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): महोदय, मैं त्रिपुरा राज्य से आती हूं। वहां पर तीन दिशाओं में बांग्लादेश की सीमा है। मेरा विषय किसान के बारे में है। किसान के रोजगार को दोगुना करने के लिए केन्द्र सरकार भी काम कर रही है और हमारी राज्य सरकार भी काम कर रही है। इसी दिशा में बॉर्डर पर जो फेंसिंग है, करीब-करीब 900 किलोमीटर की बॉर्डर फेन्सिंग हमारे राज्य में है, थोड़ी बहुत अभी रह गई है। बॉर्डर फेंसिंग के कारण वहां पर फ्लड लाइड की व्यवस्था है। जो किसान धान की फसल लगाते हैं, दिन में भी सनलाइट है और रात में भी फ्लड लाइट के कारण लाइट है, इसी कारण से फोटोसेंथिसिस नहीं हो पाता है। इससे किसान का बहुत नुकसान होता है। मैं आपके माध्यम से संबंधित विभाग से रिक्वेस्ट करती हूं कि साल में दो बार उसकी समीक्षा कर के किसानों को कुछ मुआवजा दिया जाए।

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Hon. Speaker, Sir, I rise to register my views on the need for enhancing the reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The present level of reservation is at 15 per cent for the Scheduled Castes and 7.5 per cent for the Scheduled Tribes. This is based on the 1971 Census but, now, the population has gone up. The present level of Scheduled Castes in India's population is 16.6 per cent and that of the Scheduled Tribes is 8.8 per cent. Therefore, a proportional representation is to be given. This is one part.

The second part is that the Government is mindlessly going on selling the public sector undertakings. The public sector undertakings provide reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. It has not made any arrangement to compensate the loss of employment opportunities for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

In 1947, when we got Independence, when India got Independence, the Muslims got Pakistan and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes got reservations. It is a solemn agreement to be maintained.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. के. जयकुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली-सहारनपुर रेलवे लाइन दुनिया में छठीं सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ वाली रेलवे लाइन है। दिल्ली के चारों तरफ चाहे गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरूग्राम हो, सब तरफ मैट्रो गई है। केवल बागपत से पिछली सरकारों को इतना प्यार रहा है कि उन्होंने कभी इस क्षेत्र के बारे में ध्यान नहीं दिया। रोज़ाना 50 से 60 हज़ार लोग दिल्ली आते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि दिल्ली से समीप हमारा बागपत-बड़ौत का जो क्षेत्र है, वहां पर शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से जल्दी से जल्दी मैट्रो ट्रेन की मंजूरी दी जाए।

श्री मोहम्मद अकबर लोन (बारामूला): स्पीकर सर, मेरे हल्का-ए-इंतिखाब में बांदीपुरा, गुरेज, कुपवाड़ा, तंगधार, ऐसे इलाके हैं, जो बड़े हिली एरियाज़ हैं। इन हिली एरियाज़ में हरेक को एक-दूसरे से मिलने के लिए सौ किलोमीटर से ऊपर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है। अगर इसकी बजाय इन जगहों पर, जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज़ किया है, इन जगहों पर एक टनल बनाई जाए। पहली टनल बांदीपुरा में बनाई जाए। दूसरी टनल गुरेज में बनाई जाए। तीसरी टनल तंगधार में बनाई जाए और साधना टनल को भी बनाया जाएगा। ये तीन-चार टनल्स बन जाने से लोगों के आने-जाने का जो रास्ता है, वह कम हो जाएगा और लोग आसानी से एक-दूसरे के इलाके में आ-जा सकते हैं। मेरी आपकी ओर से मुतलका ऑनरेबल मिनिस्टर से यही गुजारिश है कि इन टनल्स को बनाने का बहुत वक्त से वादा है। इस वादे को निभाने के लिए ये टनल कायम किए जाएं।

جناب محمد اکبر لون (بارا مولہ): جناب اسپیکرسر، میرے حلقۂ انتخاب میں باندی پورا، گُریز، کُپواڑہ، تنگدھار، ایسے علاقے ہیں، جو بڑے بِلی ایریاز ہیں۔ ان ایریاز میں ہر ایک کو ایک دوسرے سے ملنے کے لئے سو کلو میٹر سے اوپر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس کی بجائے ان جگہوں پر، جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے، ان جگہوں پر ایک ٹنل بنائی جائے۔ پہلی ٹنل باندی پورا میں بنائی جائے۔ دوسری ٹنل گُریز میں بنائی جائے۔ تیسری ٹنل تنگدھار میں بنائی جائے اور سادھنا ٹنل کو بھی بنایا جائے۔ یہ تین۔چار ٹنلس بن جانے سے لوگوں کے آنے جانے کا جو راستہ ہے وہ کم ہو جائےگا اور لوگ آسانی سے ایک دوسرے کے علاقوں میں آ جا سکتے ہیں۔ میری آپ کے ذریعہ متعلقہ آنریبل منسٹر صاحب سے یہی گُزارش ہے کہ ان ٹنلس کو بنانے کا بہت پہلے سے جو وعدہ ہے اس وعدے کو نبھانے کے لئے یہ ٹنلس قائم کی جائیں۔ شکریہ

श्री रमेश चन्द्र माझी (नबरंगपुर): स्पीकर सर, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट – 2006 में आदिवासी जनजाति फॉरेस्ट लैण्ड पट्टा मिलता है। मगर वहां भी, जंगल में भी एस.सी., ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल्स रहते हैं। इसीलिए ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है कि इसमें फिर से अमेंडमेंट किया जाए। जहां ओबीसी, माइनॉरिटीज़, एस.सी. और जनरल कास्ट्स के लोग होते हैं, वहां फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की तरह उनको जमीन नहीं मिल रही है। प्रधान मंत्री आवास योजना हो या बीजू पक्का घर योजना में शामिल होते हैं, मगर उनके पास कोई जमीन नहीं होती है, इसीलिए वे नहीं पाते हैं। मेरी गुजारिश है कि इस बारे में फिर से सोचा जाए। धन्यवाद।

(1605/KN/RCP)

माननीय अध्यक्ष : श्री पी. पी. चौधरी।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): आज कल आप सीनियर एडवोकेट नहीं कह रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : सीनियर एडवोकेट श्री पी. पी. चौधरी।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): अध्यक्ष महोदय, जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैंने 27 तारीख को सप्लीमेंट्री मांगी थी, I think, due to paucity of time, I could not be given time at that time. मेरा कोल आउटपुट के बारे में सवाल है। आज देश में करीब 1,71,000 करोड़ रुपये का कोल हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। देश में कोल खादानों की कोई कमी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि कोल जो अभी डिक्लाइन हुआ है, उसका आउटपुट जो डिक्लाइन हुआ है, वह हुआ ही है, वह इनक्रीज नहीं हो रहा है। इनक्रीज करने के जो कारण हैं, उसका समाधान भी हमारे पास है। मुझे लगता है कि कोल ब्लॉक का डिजाइन और माइनिंग प्लान छोटी-छोटी खादानों के बने हुए हैं। उसमें जो इक्वीपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, वे कन्वेंशनल इक्वीपमेंट्स हैं। जैसे 35 टन के डम्पर हैं या 45 टन के ऐक्सकेवेटर्स हैं, जबकि 27 तारीख को मंत्री जी का जो जवाब था, उसमें उन्होंने कहा कि हम हेवी अर्थ मूविंग मशीन यूज करेंगे, जिसके साथ 240 टन के डम्पर लगे हुए हैं। मेरा मानना है कि जो कोल ब्लॉक्स हैं, उनकी डिजाइन और माइनिंग प्लान जब तक हेवी अर्थ मूविंग के अनुसार नहीं करेंगे, तब तक हेवी अर्थ मूविंग मशीन छोटी माइन्स में काम नहीं कर सकती। यही कारण है कि उसका आउटपुट इनक्रीज नहीं हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हम और भी ज्यादा कोल ब्लॉक्स अलॉट करेंगे। सवाल अलॉट करने का नहीं है। सवाल यह है कि एग्जिस्टिंग माइन्स जो हैं, उसकी साइज जब तक हम बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो मशीन्स आई हैं, वे बड़ी-बड़ी आई हैं। वे मशीन्स बड़े पिट में ही काम कर सकती है, छोटे ब्लॉक में काम नहीं

कर सकती। उसके कारण नुकसान हो रहा है। कोल प्रोडक्शन आउटपुट कम हो रहा है और इम्पोर्ट 1,71,000 करोड़ रुपये का कम हो सकता है। जो कोल माइन्स हैं, उसका डिजाइन वगैरह बढ़िया रखें। एफडीआई जो है, जो फॉरनर्स हैं, वह एफडीआई डायरेक्ट इसलिए नहीं ला रहे हैं, क्योंकि पिट्स जो हैं, वे छोटे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ती है, सेफ्टी भी कम रहती है और पॉल्यूशन का भी कारण बनता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): अध्यक्ष महोदय, मुझे लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य का लाभ मिले, इसके लिए उन्होंने पूरे देश की चिंता की, मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को भी साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, मैं अररिया लोक सभा क्षेत्र से जीत कर आया हूँ। प्रधान मंत्री जी ने देश को 75 मेडिकल कॉलेजेज दिए हैं। हमारे यहाँ भी एक मेडिकल कॉलेज की चिट्ठी गई है। हम लोगों ने बिहार सरकार के माध्यम से जमीन की व्यवस्था करवा दी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अररिया जिला चौथे नम्बर पर पिछड़ा है और बिहार में नम्बर वन पर पिछड़ा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जल्द ही कार्रवाई करके इसकी निविदा निकालें। मेडिकल कॉलेज का काम जल्दी शुरू हो ताकि हम लोगों के कार्यकाल में ही मेडिकल कॉलेज शुरू हो और जल्दी पढ़ाई हो। आम जनता को इसका लाभ मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए हैं। मैं अपने जिले की तरफ से केन्द्र सरकार और प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करूँगा कि सन् 1998 में तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेरे लोक सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ में यह घोषणा की थी कि गजसिंहपुर, पदमपुर, हनुमानगढ़, रावतसर और सरदारशहर के बीच में नई रेल लाइन बिछाई जाएगी।

(1610/CS/SMN)

जिसकी आज तक कोई प्रगति नहीं हुई है। सिर्फ हर साल सर्वे होता है और सर्वे होने के बाद कोई नई बात उसमें नहीं आ पाती है। वह काम आज भी अधूरा है। वर्ष 1998 में तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा की थी, लेकिन वह काम अभी भी अूधरा है। इसके साथ-साथ मेरे लोक सभा क्षेत्र के नौ हाल्ट रेलवे स्टेशंस और पाँच रेलवे स्टेशंस, एक पीलीबंगा का रेलवे स्टेशन है, इसकी विभाग ने डीपीआर बनाकर सरकार को भेज दी है, सरकार ने उसे मंजूर कर दिया है, उसके टेंडर भी हो गए हैं, लेकिन वह काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि जिस रेल लाइन की घोषणा अटल जी ने की थी, उसको और मेरे लोक सभा क्षेत्र के नौ हाल्ट रेलवे स्टेशंस और पाँच रेलवे स्टेशंस पीलीबंगा सहित को सरकार पूरा करने का आदेश दे। मैं आपसे यही आग्रह करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब स्पीकर साहब, मैं मुख्तसर दो मिनट में अपनी बात कम्पलीट करूँगा।

पहला, नेशनल हाइवे जम्मू-श्रीनगर का जो स्टेट्स है, उसके खस्ता-हाल पर सरकार की तवज्जो मफजूल कराना चाहता हूँ। इस नेशनल हाइवे पर साल में तकरीबन 100 से 150 दिन तक ब्लॉकेज रहती है। एयर ट्रैफिक भी इंटरप्ट रहता है और एयर फेयर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। मेरी गुजारिश है कि बनिहाल काजीगुंड टनल, जो 5 साल से बन रही है, उस पर काम में तेजी लाई जाए।

दूसरी बात यह है कि एनआईटी, श्रीनगर में ऑन कैम्पस रिक्रूटमेंट इस साल अभी तक नहीं हुआ है। मैं यह बात मिनिस्टर साहब के नोटिस में भी लाया हूँ। वहाँ ऑन कैम्पस रिक्रूटमेंट के लिए इंतजाम किए जाएं।

तीसरी बात यह है कि वहाँ एक लाख के करीब बच्चे प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम से महरूम होने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी इंटरनेट की सुविधा नहीं है। मेरी गुजारिश है कि उसकी जो आउटर डेट है, उसमें एक्स्टेंशन किया जाए ताकि वहाँ के लाखों शैडयूल्ड बच्चे इससे डिप्राइव न हों। ऐसा होने से उन्हें इसका लाभ मयस्सर होगा और वे इस चीज से डिप्राइव नहीं होंगे।

*SHRI P VELUSAMY (DINDIGUL): Hon. Speaker Sir, Vanakkam. Due to human-animal conflict, particularly of the attack by wild elephants, the livelihood of the people of Pachalur, Periyur, Kamanur, Vadakavunji, Kookkaal, Panchayat Union areas around Kodaikkanal hill is affected very much. During the last two months within a span of 15 days three women namely Rajakkani, Mariammal and Jayalakshmi have been killed due to attack by wild elephants. I request you that Union and State Governments should provide priority in Government jobs to the family members of those killed by wild animals. Gloriosa Superba is a flower having medicinal value is grown in more than 10000 hectares the Dindigul, Karur, Tiruppur, Namakkal, Tiruchy, Permabalur, Ariyalur, Nagappatinam, and Salem districts of Tamil Nadu. Some companies procure them and export them to foreign countries. Mainly the middle men procure the seeds of this flower. Farmers do not know the market value of the seeds of this flower. Last year the seeds of Gloriosa Superba were procured from these companies at Rs3500/- per kg. This year the price was Rs.1500. As a result, farmers did not get remunerative price. I therefore urge upon the Union Minister of Agriculture to take necessary steps to directly procure the seeds of Gloriosa Superba by the Union Government so that the farmers may get remunerative price for their produce. Thank you.

* Original in Tamil

*SHRI K SHANMUGA SUNDARAM (POLLACHI) : In my Pollachi parliamentary constituency and also in the 13 districts of Tamil Nadu such as Coimbatore, Tiruppur, Erode, Namakkal, Salem, Dharmapuri, Krishnagiri, Vellore, Thiruvannamalai, Villupuram, Tiruchy, Karur and Dindugul, Tamil Nadu generation and Distribution Corporation and Power Grid Corporation of Union Government have been implementing projects for setting up of 14 High voltage transmission towers over farm land. The farmers and farmers' unions affected due to the installation of such high voltage towers have set up a Federation of Farmers' Organisations and are spearheading a non-co-operation movement in the footsteps of the father of our nation Mahatma Gandhi. Their primary demand is that the high voltage lines should be set up by way of underground cabling along the roads instead of setting up high voltage transmission towers over farm lands. If the underground cabling work has been made possible in the areas around Chennai, several towns and cities of Tamil Nadu, Kerala, from Madurai to Sri Lanka, Cochin and from Porbandar to African country Djibouti, it is gross injustice to set up high voltage transmission lines along the farm lands of the State of Tamil Nadu thereby affecting the livelihood of our farmers. After all the demands have been rejected, the Federation of Farmers Organisation had put forth another demand of providing monthly rent as regards the areas occupied by such transmission towers as per the rules of Union Government which came into force from 2006. But that demand was also rejected. While replying to the Calling Attention Motion moved by the Leader of Opposition and the DMK leader in the Tamil Nadu State Assembly on 4 January 2019 about the issue of high voltage transmission towers, Hon'ble Minister for Power Shri Thangamani had assured that each of the affected farmers will be provided Rs. 4 Crore per 1 km of occupied area. But that is not implemented as well so far. It is gross injustice to the farmers. In the States like Telangana and Uttar Pradesh a compensation of Rs. 4 lakh to Rs. 6 lakh has been provided for the land space occupied by the tower base and Rs. 2 lakh to Rs. 4 lakh for an acre area covered by passing power transmission line. In Maharashtra, the compensation amount provided is Rs. 7.5 lakh to Rs. 9 lakhs for land space occupied by tower base and Rs. 3 to Rs. 4 lakh for an area of one acre covered by passing power transmission line. These are the States where land value is less as compared to Tamil Nadu. In such a scenario, the demand for providing a compensation of at least Rs. 20 lakh for the land occupied by tower base and Rs. 10 lakh for an area of one acre covered by the passing power transmission line is still pending. This demand should be fulfilled. On 30.10.2019 as per G.O. No 86 of Tamil Nadu Government, an amount of at least Rs. 50,000/- is fixed as compensation for the land occupied by high voltage tower by the State Government of Tamil Nadu. This amount should be increased an at least Rs. 20 lakh should be provided for the land occupied by tower base and Rs. 10 lakh for an area of one acre covered by the passing power transmission line. But crop compensation was also not fixed. It should also be fixed. I therefore request the Union Government to ensure that the farmers get their due land and crop compensation for the areas occupied by high voltage transmission lines and the 46 false cases filed against the agitating farmers and the federation of farmers by the State Government during the last 3 years should be withdrawn besides protecting the livelihood of the farmers of 13 districts of Tamil Nadu. Thank you.

* Original in Tamil

(1615/RV/MMN)

श्री सोयम बापू राव (आदिलाबाद): अध्यक्ष जी, ज़ीरो आवर में आपने मुझे बात करने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे क्षेत्र आदिलाबाद, तेलंगाना में 1979 में एक सीमेन्ट फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसे 1999 में उसे बंद कर दिया गया। इससे वहां के दस हजार लोगों की बेनेफिट्स रुक गई। इसलिए उस फैक्ट्री को फिर से चालू कराएं, यह हम सरकार से विनती कर रहे हैं।

भारत में सीमेन्ट की चार फैक्ट्रियां थीं। उनमें से तीन फैक्ट्रियां अभी चालू हैं। केवल आदिलाबाद की फैक्ट्री बंद है। यह फैक्ट्री भी 1993 तक बेनेफिट में थी। अगर इस फैक्ट्री को चालू करें तो हमारे यहां के दस हजार लोगों का डायरेक्ट बेनेफिट होगा। इस फैक्ट्री को शुरू करने की आपके माध्यम से सरकार से मेरी विनती है।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि पिछले कार्यकाल में डी.एम.एफ. फण्ड का निर्माण हुआ। जिस जिले में जो खनन कार्य हो रहा है, जो खनिज निकाले जा रहे हैं, उसका कुछ परसेंटेज उस जिले के विकास के लिए एक ट्रस्ट के माध्यम से वह सरकारी फण्ड बना। मेरे भीलवाड़ा जिले में खनन का बहुत बड़ा व्यवसाय है और बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहां काफी मात्रा में रॉयल्टी मिलती है। भीलवाड़ा के डी.एम.एफ. फण्ड में लगभग 400 करोड़ रुपये अभी जमा है, लेकिन वहां की राज्य सरकार उसे खर्च नहीं कर रही है। उसमें कुछ परसेंटेज तय है कि उसका 40 प्रतिशत शिक्षा के लिए, 40 प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए, कुछ पीने के पानी के लिए खर्च होगा, लेकिन सरकार उसे खर्च नहीं कर रही है। वे फण्ड वैसे ही पड़े हुए हैं। विद्यालयों की हालत यह है कि प्राइमरी स्कूल में पाँच क्लासेज हैं, मगर उनका कमरा एक ही है। मिडिल स्कूल में आठ क्लासेज हैं, मगर उनके लिए कमरे मात्र एक या दो ही हैं। आपके क्षेत्र में भी वही हाल है। मेरा यह मानना है कि इस मामले में निर्देशित किया जाए कि डी.एम.एफ. फण्ड जिस साल इकट्ठा हो, उसे एक या दो साल के भीतर खर्च किया जाए। ऐसा कोई प्रावधान इसमें किया जाए।

श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी (कटिहार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अति लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की गई एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश के निजी अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों की तुलना में सात से आठ गुणा अधिक पैसे खर्च होते हैं।

(1620/MY/VR)

जैसा कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार एक परिवार का सरकारी अस्पताल में इलाज कराने का औसत खर्च 4,452 रुपये आता है और दूसरी ओर निजी अस्पताल में यही खर्च 31,845 रुपये आता है। अभी 55 परसेंट लोग निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए विवश हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए और एक मानदंड तैयार हो, जिससे निजी अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोग भी अपना इलाज करा सकें।

श्री दुर्गा दास (डी.डी) उईके (बैतूल): माननीय अध्यक्ष जी, लोक हित के मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र बैतूल, हरदा, हरसूद (मध्य प्रदेश) में पाकिस्तान-बांग्लादेश विभाजन के वक्त बर्मा तथा बांग्लादेश से हजारों बंगाली परिवारों ने शरण ली थी। भारत सरकार ने वर्ष 1964 से वर्ष 1988 तक हमारे आदिवासी क्षेत्र के विधान सभा घोड़ा डोंगरी के चोपना क्षेत्र में रहने के लिए उनको जमीन दी थी। वहां सैकड़ों परिवार जमीन, पट्टे और अपने जाति के निर्धारण के लिए 50 वर्षों से सतत संघर्ष कर रहे हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख निर्वासित तथा विस्थापित बंगाली भाई-बहनों की समस्या का समाधान बहुप्रतीक्षित है। हम निरंतर पत्राचार, ज्ञापनों और विविध प्रकार से शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास अनेक वर्षों से कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के बंगाली भाई-बहनों की तकलीफों को संज्ञान में ले तथा त्वरित निराकरण की दिशा में ठोस पहल करे। धन्यवाद – जय हिंद।

DR. MAHENDRABHAI KALUBHAI MUNJAPARA (SURENDRANAGAR): Thank you, hon. Speaker, Sir. My constituency consists of many villages from where a number of players have participated in a variety of games at national level. Unfortunately, the talent of many other sportsmen from our urban and rural areas has been neglected for certain reasons.

Sir, I feel very proud to inform the House that I have also been a good sportsman and participated in many sports events like Khel Mahakumbh of Gujarat. Therefore, I can very well understand the feelings of the neglected sportsmen and coaches of my region.

Through you, hon. Speaker, Sir, I would request the hon. Sports Minister to build another district level sports complex near Wadhwan and Surendranagar so that students and sportsmen of that regions can participate in Khelo India Mission started by our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Thank you, Sir.

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र गोपालगंज है, जिसकी आबादी लगभग 26 लाख है। मेरे संसदीय क्षेत्र में ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर तथा एन.एच. 28 है, जो दिल्ली से चल कर असम तक जाती है और गोपालगंज शहर के बीचोंबीच गुजरती है। गोपालगंज शहर के बंजारी मोड़ से हजियापुर तक मंत्रालय द्वारा एलिवेटेड कॉरिडोर की स्वीकृति दी गई थी और इसे 36 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव मंजूर था। जवाब मिलने के छह महीने बाद भी अधूरे कार्य को अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है। इससे शहर में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। मरीजों, स्कूली छात्रों और कार्यालय कर्मियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

महोदय, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मंत्रालय द्वारा इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। धन्यवाद।

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा जो संसदीय क्षेत्र बालूरघाट है, वह तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हमने बचपन से ही देखा है कि वहां बांग्लादेश से कैसे तस्करी होती रही है। वहां मूल रूप से गाय की तस्करी होती है। आज बहुत जगहों पर फेन्सिंग हो गई है, लेकिन मेरे इलाके में कुछ जगह विवादित है, वह बॉर्डर एरिया में है और वहां पर फेन्सिंग नहीं है। इसके कारण वहां गाय की तस्करी चलती रहती है। इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। दो दिन पहले वहां एक घटना घटी, उसमें तस्कर किसानों के खेतों के बीच में से गायों को लेकर जा रहे थे। जब किसानों ने उसका विरोध किया, तो वे लोग दूसरे दिन सुबह आकर एक किसान का कान काट कर चले गए। वहां ऐसी हालत हो रही है। पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, उसको इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। सीमा के 10 किलोमीटर तक बीएसएफ का दायरा रहता है, लेकिन उसके बाहर जो एरिया है, वह एरिया स्टेट गवर्नमेंट का है। वहां स्टेट गवर्नमेंट की जो ड्यूटी है, वह खुद अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही है।

(1625/CP/SAN)

इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा अनुरोध है कि वह बीएसएफ को कुछ और प्रावधान दें, ताकि वह इंटरफेयर कर सकें और इस तस्करी को बंद किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उरई, चुरखी और पालसरेनी होते हुए कानपुर देहात को जोड़ने वाला यमुना नदी पर पुल बना हुआ है। वह पुल 90 पर्सेंट बनकर तैयार हो गया है। यह पुल करीब 10 साल से बनाया जा रहा है। वहां आवागमन के लिए यह सुगम हो जाता, अगर पुल का रुका हुआ काम शीघ्र पूरा कर दिया जाता। हमारे लोक सभा क्षेत्र जालौन से होते हुए यह रोड सीधा कानपुर देहात, कानपुर देहात से होते हुए लखनऊ के लिए खुल सकती थी। पूरा पुल बन कर तैयार हो गया है। उसमें मात्र कुछ दर बाकी रह गई हैं, जिसकी वजह से यह पुल रुका हुआ है।

मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि मेरे जनपद जालौन को जोड़ने वाला, कानपुर देहात को जोड़ने वाला, पालसरेनी पर बना हुआ जो पुल है, उसे शीघ्र बनवाया जाए।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं, जो कि जीरो ऑवर मैं बैठते हैं, पहली बार मैं किसी स्पीकर को देखता हूं। …(व्यवधान) अध्यक्ष जी की अनुमति से कहीं से भी बोल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं जिस राज्य झारखंड से आता हूं, वह एक बड़ी समस्या से ग्रसित है। मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी, जिसको नोबल पुरस्कार दिया गया, मदर टेरेसा का हम सभी लोग सम्मान करते हैं। उसकी जो संस्थायें झारखंड में हैं, वे धर्मांतरण में लगी हुई हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, यह तक नहीं पता चलता है। स्पीकर महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बच्चे की मां

कौन है, पिता कौन है और उसके बाद मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी उन बच्चों को गोद लेकर बाहर भेजती है। बाहर एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। यह रैकेट केवल मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी ही नहीं चला रही है, और भी कई सारी संस्थायें चला रही हैं। उनको एफसीआरए के अंतर्गत बाहर से फंडिंग आती है। वे सामने तो दिखाते हैं कि हम स्वास्थ्य के बारे में काम कर रहे हैं, शिक्षा के बारे में काम कर रहे हैं। स्पीकर महोदय, आपको पता है कि सबसे ज्यादा 40 से 50 पर्सेंट माइंस और मिनरल्स इस देश में यदि कहीं हैं, तो वह झारखंड में है। कहां प्लांट नहीं लगना है, कहां पॉवर प्लांट नहीं लगना है, कहां माइनिंग नहीं होनी है, इस तरह की सारी समस्याओं से झारखंड ग्रसित है। हम पलायन और विस्थापन के शिकार हैं। झारखंड के 70 पर्सेंट बच्चे कुपोषित हैं, 80 पर्सेंट महिलाएं एनीमिक हैं। वहां के स्थानीय लोगों को 10-15 पर्सेंट रोजगार मिलता है, क्योंकि डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो रहा है।

स्पीकर महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जितनी भी संस्थायें एफसीआरए से रजिस्टर्ड हैं, खासकर मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी जैसी जो संस्था है, उसके बारे में सीबीआई इंक्वायरी हो, उसकी जांच हो और इसके ऊपर कार्रवाई करके झारखंड की रक्षा हो। धर्मांतरण जो इनका एक बड़ा मुद्दा है, उस धर्मांतरण से मुक्ति मिले और हमारे विकास में यह सहायक हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): Hon. Speaker, I thank you for allowing me to raise an important matter relating to my parliamentary constituency, Eluru.

For a long time, there has been a request for a railway line from Bhadrachalam to Kovvur which would pass through four SC and two ST segments. It is a totally backward area. There is agency area also. We have been requesting for a railway line, for which the DPR has been done, but the Railways Ministry does not want to take it up, citing reason of the State Government not contributing for it.

My State is a recently bifurcated new State which really lacks financial resources. I would request the Railways Ministry to consider this as a special case. This area was earlier a naxal-infested area also. The Central Government earlier, in order to develop backward areas or naxal-infested areas, were opening up new transportation lines.

Taking all this into consideration, I would request the Railways Ministry to take this issue seriously and immediately establish a railway line between Kovvur and Bhadrachalam.

Thank you.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं देश के करोड़ों लोगों की समस्या इस सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं।

(1630/NK/RBN)

हमारी सरकार दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए लाए हैं। एक मिनट सुन लेते तो अच्छा होता।

माननीय अध्यक्ष: आपको फिर मंत्री जी का जवाब भी सुनना पड़ेगा।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल सुनूंगा, जब तक आप कहेंगे तब तक बैठूंगा। 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत गरीब लोगों को चिकित्सा के लिए पांच लाख रुपये तक की सहायता भारत सरकार की ओर से दी जाती है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं, जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, वह उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, लेकिन सर्वे की सूची में किसी कारण एसईसीसी में उनका नाम नहीं आया है। इसके चलते वह उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, गोल्डन कार्ड नहीं बन पाता। अधिकारी कहते हैं कि जब तक एसईसीसी में नाम नहीं होगा तब तक गोल्डन कार्ड नहीं बनेगा, तब तक चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। देश में ऐसे करोड़ों गरीब लोग हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी गरीबों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना देश में लाये हैं।

हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे कि फिर से एक बार जल्दी से सर्वे कराया जाए। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वे जानते हैं कि यह गरीब है और उस सूची में आ रहा है लेकिन उसको सहायता नहीं मिल रही हैं। हम लोगों की अनुशंसा पांच प्रतिशत भी मान लें, हम जिसे प्रमाणित करें कि यह सच में गरीब है, उसको लाभ मिलना चाहिए। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि गरीबों को लाभ मिल सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं। आपके संरक्षण में मुझे कई बार अपने पिछड़े क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं।

कानपुर से सागर राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसमें हमीरपुर- भरुआ सुमेरपुर, मौदाहा, कबरई, महोबा आता है। मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी से प्रश्न पूछा था, उसके जवाब आया है। भरुआ सुमेरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग दो लेन का है, फोर लेन नहीं बनाया जा रहा है, उसके बावजूद वहां चौड़ीकरण के नाम पर शहर में तोड़फोड़ के लिए मार्किंग की गई है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है, मैं बहुत लंबे समय से यह मांग कर रहा हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र भरुआ सुमेरपुर कबरई और पुलपहाड़ नगर में केवल राष्ट्रीय राजमार्ग में बाइपास का निर्माण किया जाए ताकि वहां के रहने वाले निवासी और व्यापारीगण को सुविधा मिल सके। किसी को कोई दिक्कत न हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गुमान सिंह दामोर (रतलाम): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। अभी दो-दिन पहले की घटना है। रांची में लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ बारह दरिंदों ने दरिंदगी की। हमारे यहां बहुत सारे नियम लागू हुए लेकिन फिर भी बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि बच्चों और महिलाओं के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड हैल्प लाइन होनी चाहिए। एक सेंटर होना चाहिए जिस पर यही शिकायत दर्ज हो। दूसरा, बच्चों और महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं, उसकी जांच के लिए एक सेल रहे। हर थाना में एक सेल रहे, जिसकी हेड लेडी ऑफिसर हो, चाहे वह सब-इंसपेक्टर की रैंक की हो।

तीसरा, एफआईआर दर्ज कराने की स्थिति है। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो मैंने एसपी को फोन किया तब जाकर उसकी एफआईआर दर्ज हुई।

मेरा इस मामले में निवेदन है कि ऐसा सेल गठित हो जिसमें आप फोन लगाएं तो सीधे एफआईआर दर्ज होने जैसी स्थिति बने। मेडिकल की स्थिति भी बहुत खराब है। एक-दो दिन लगे रहते हैं। मेडिकल कराने के लिए वहां लेडी डॉक्टर हो वरना जो विक्टिम होती हैं उनके साथ यह भी एक बहुत बड़ा टार्चर होता है।

माननीय अध्यक्ष: सभी मांग एक दिन ही रख लोगे, फिर कब मौका मिलेगा।

श्री गुमान सिंह दामोर (रतलाम): अध्यक्ष महोदय, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिनको फांसी की सजा दी गई है वे चार-चार साल से बैठे हुए हैं। इस बारे में विचार करना चाहिए। आपने मुझे अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री गुमान सिंह दामोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1635/SK/SM)

बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और छुट्टा गोवंश की समस्या को दूर करने के लिए केन-बेतवा नदी सम्पर्क परियोजना द्वारा नहरों के निर्माण के संबंध में संकल्प – जारी

माननीय अध्यक्ष: अब मद संख्या 12, गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जाता है।

श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा 21 जून, 2019 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा :-

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदलेखंड क्षेत्र में जल संकट और पशुओं के चारे की अनुपलब्धता के कारण, क्षेत्र के लोग अपनी गायों को खुले में चरने के लिए छोड़ने पर विवश हैं, जो आम तौर पर 'अन्न प्रथा' के नाम से जानी जाती है, और जो खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, यह सभा सरकार से क्षेत्र में जल संकट की समस्या और अन्न प्रथा की परम्परा को दूर करने के लिए बांधों और तालाबों के अंतर्संयोजन तथा पुनर्भरण करने के लिए प्रस्तावित केन-बेतवा नदी सम्पर्क परियोजना से नहरों का संजाल निर्मित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह करती है।"

श्री नायब सिंह: उपस्थित नहीं।

श्री दुष्यंत सिंह।

1635 बजे

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सीट से बोलने की अनुमति चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: आपको अनुमति दी जाती है।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): माननीय अध्यक्ष जी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जो रिजोल्युशन लेकर आए हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं। कुंवर साहब, हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने बुंदेलखंड की बात रखी है। बुंदेलखंड से मेरा पैतृक और पारिवारिक रिश्ता रहा है और हमेशा रहेगा।

1635 बजे (श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

हमारे बुंदेलखंड के झांसी डिस्ट्रिक्ट में जालौन, उरई, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट से पारिवारिक रिश्ता रहा है। कुंवर साहब यह रिजाल्युशन आदरणीय नाना देशमुख को देखते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए और उनके अच्छे कामों को देखते हुए लेकर आए हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। उन्होंने केन-बेतवा इंटरलिंकिंग रिवर की बात कही है। जब हम बुंदेलखंड की बात कहते हैं तो गैरोठा, समथर की बात भी रखनी होगी, भसने डैम तक पानी पहुंचना चाहिए। केन-बेतवा में उर्मिल डैम, मज़गांव डैम और बेला तल डैम तक पानी पहुंचे, इसके लिए हमें अपनी बात रखनी है।

मेरा संसदीय क्षेत्र राजस्थान में है, मुझे पार्टी ने मौका दिया है। राजस्थान बड़ा प्रांत है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारे राज्य के सांसद आदरणीय गजेन्द्र शेखावत जी को जल शक्ति मंत्री बनाया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि पानी का मंत्रालय राजस्थान के सांसद को दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बड़े भाई आदरणीय शेखावत जी इस डिपार्टमेंट में मंत्री हैं।

राजस्थान में लगभग 3,42,000 हजार और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जमीन की लंबाई और चौड़ाई है। यहां का तापमान गर्मी में बढ़ता है और सर्दी में घटता है। यहां पानी दूरदराज़ क्षेत्रों से लाना पड़ता है। यहां कभी-कभी पानी का लैवल इतना कम हो जाता है कि फ्लोराइड, आर्सेनिक वाला पानी लोगों को पीना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने नई नीति बनाई है। मैं चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी उत्तर दें तो इसके बारे में बताएं।

मेरा संसदीय क्षेत्र झालावाड़-बारां है, मैं राजस्थान की पूर्व सरकारों, एनडीए सरकार, आदरणीय भैरों सिंह शेखावत और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री साहिबा को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि सबने झालावाड़-बारां को चेरापूंजी का क्षेत्र बना दिया है। एनीकट बनाने के बाद यहां रेन फॉल होती है। यहां कहीं-कहीं सूखा क्षेत्र है, लेकिन हमारे क्षेत्र में हरियाली है और पानी का लैवल बहुत नीचे नहीं है। हमारे क्षेत्र में सोयाबीन, मक्का, धनिया की फसलें होती हैं।

अब ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। सदन में इस पर पिछले हफ्ते चर्चा हुई थी। इसके कारण कहीं ज्यादा वर्षा हो रही है और कहीं कम हो रही है। मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूं, 1 जून से 19 जून तक राजस्थान में 546 मिलीमीटर वर्षा हुई यानी 55 परसेंट ज्यादा हुई, 8 अगस्त से 14 अगस्त के बीच 400-500 मिलीमीटर ज्यादा वर्षा हुई, जिससे पूरी खेती नष्ट हो गई।

(1640/MK/AK)

आज हम लोग इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के बारे में बात कर रहे हैं। देश के पूर्व प्रधान मंत्री जी, आज हमें स्मरण होता है, आदरणीय पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह बात रखी थी। उन्होंने आदरणीय मंत्री श्री प्रभु जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की बात रखी थी। इसके लगभग 17-18 वर्ष हो गए। 10 सालों तक, पूर्व में वर्ष 2004 से जब कांग्रेस की सरकार थी, इसमें कुछ काम नहीं हुआ। आदरणीय मोदी जी आए और उन्होंने इसके बारे में सोचा। पहले तो उन्होंने स्वच्छता की बात रखी। हमें गंगा को साफ करना चाहिए, हमें देश को साफ रखना चाहिए, इसके लिए उन्होंने मंत्रालय बनाकर एक अच्छा काम शुरू किया है। मैं आदरणीय मोदी जी को और पूरी सरकार को धन्यवाद देता हूं।

मुझे आज स्मरण हो रहा है कि जिस प्रांत से मैं आता हूं, वहां एमजेएसए, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन स्कीम का काम हुआ है। यह अभियान 27 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। अंडर द वाटर स्कीम, अंडर द एमजेएसए स्कीम, जो ग्राउंड का वाटर लेवल है, वह 21 डिस्ट्रिक्ट्स में 4.66 परसेंट बढ़ा है। इसके बारे में हमारे माननीय मंत्री जी को पता है। उसको देखते हुए हम चाहेंगे कि एमजेएसए स्कीम, जिसको भाजपा सरकार ने वर्ष 2016 में शुरू किया था, इसको अन्य प्रांत भी यूज करें। जब इसको यूज करेंगे और इसको मनरेगा से डवटेल करे लेंगे तो इसके लिए राशि मिलेगी और राशि मिलने से हमारे क्षेत्र में पानी का क्षेत्र बढ़ेगा।

चेयरमैन साहब, जब आपके मेरठ क्षेत्र में पानी की कमी होती है या कोई और क्षेत्र में पानी की कमी होती है तो आप टैंकर यूज करते हैं। जब टैंकर यूज करते हैं तो टैंकर का भाड़ा भी देना पड़ता है। राजस्थान में एमजेएसए आने के बाद टैंकर के भाड़े में लगभग 56 परसेंट का रिडक्शन हुआ है। इसके साथ-साथ वाटर रिजुवेनेशन हुआ है। हैंड पंप की संख्या बढ़ी है। यह काम लगभग 44409 हेक्टेयर्स पहले फेज में हुआ है और आखिर में आते-आते हमने लगभग 352760 हेक्टेयर्स को पानी देने का काम किया है तथा इससे 21 डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने का काम किया है। केंद्र सरकार को यह देखकर अच्छा लगा। केंद्र सरकार ने राजस्थान से इस योजना को अपनाया। मैं राजस्थान की पूर्व सरकार को धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी राजस्थान से हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह योजना, जो पूर्व सरकार की थी, उसमें और अच्छा काम करेंगे। आदरणीय मोदी जी ने 'नल से जल,

हर घर तक 2024' की बात रखी है। इससे हमें पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा, सिंचाई की व्यवस्था होगी, जैसे मैंने पहले कहा था कि कई ऐसी डिजीज हैं जो वाटर बॉर्न होती हैं। हम गर्मी के मौसम में देखते हैं कि लोग पानी पीते हैं। वे जब उस पानी को पीते हैं तो उनको कभी कभी बीमारी हो जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गजेन्द्र शेखावत जी के नेतृत्व में वर्ष 2024 के पहले देश मे हर घर को स्वच्छ जल पीने को मिलेगा।

हम पानी और क्षेत्र को जोड़ने की बात करते हैं तो दिलों को जोड़ने की बात भी होती है। जब हम केन-बेतवा को जोड़ते हैं तो हम इसके द्वारा लॉजिस्टिक्स का काम कर सकते हैं, क्या हम लॉजिस्टिक पार्क के द्वारा, लॉजिस्टिक कंपनीज के द्वारा इसमें जा सकते हैं? आप विदेश में देखें, आप चाइना में देखें तो आपके 44 परसेंट माल पानी से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है।

(1645/RPS/SPR)

अगर आप यूरापियन यूनियन में देखें तो वहां 47 प्रतिशत माल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है, लेकिन हमारे यहां केवल तीन प्रतिशत सामान ही यहां से वहां जाता है। जब यह सिस्टम सेट होगा, तब माननीय मंत्री जी को एक राशि मिलेगी। लॉजिस्टिक्स पार्क के द्वारा भी इनको पैसे मिलेंगे और हर घर तक जल पहुंचाने के लिए भी इनको लॉजिस्टिक्स पार्क से राशि मिलेगी, जिससे यह काम अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएगा। इसलिए इसे हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में हम सभी लोग बोल रहे हैं। आदरणीय नितिन गडकरी जी भी एक-दो दिन पहले बोल रहे थे कि हम अपना एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ाएंगे और कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे। इस एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ाने का काम भी हम पानी के माध्यम से कर पाएंगे। जब हम गुजरात को देखते हैं तो हम साबरमती रिवर फ्रंट को भी देखते हैं, वहां हम देखते हैं कि पर्यटन का काम हो रहा है। मैं राजस्थान से आता हूं, पूर्व में यहां जो चिड़िया आती हैं, हमें उनके बारे में भी चिन्ता करनी चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में वहां एक एपिडेमिक आया है, जिसके द्वारा बहुत-सी चिड़ियां मरी भी हैं। टूरिज्म को बढ़ाने के साथ-साथ, बोटिंग के साथ, लोगों को काम-धन्धा देने के लिए जैसे सरदार सरोवर डैम में गुजरात सरकार ने बहुत अच्छा काम किए हैं, उनको देखते हुए, हमें यह काम करने की जरूरत है।

मैं झालावाड़-बारां से आता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक तरफ चम्बल है, दूसरी तरफ काली सिन्ध और पार्वती नदियां हैं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): श्री दुष्यंत सिंह जी, आप एक मिनट रुकिए।

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि इस संकल्प पर चर्चा में पहले ही छ: घण्टे लिए जा चुके हैं। इस पर विचार करने के लिए आबंटित समय लगभग समाप्त हो चुका है। चूंकि संकल्प पर चर्चा करने हेतु सात अन्य सदस्यों को भाग लेना है, यह संख्या बढ़ भी सकती है, इसलिए सभा को इस संकल्प पर आगे चर्चा करने हेतु समय बढ़ाना है।

यदि आप सभी सहमत हों तो इसका समय दो घण्टे और बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

माननीय सभापति: फिलहाल दो घण्टे समय बढ़ाते हैं, फिर जैसी आवश्यकता होगी, देखेंगे। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी संख्या में माननीय सदस्य इस पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): आदरणीय चेयरमैन साहब, जो आपने बोला है, पूरा सदन आपकी बात से सहमत है और आपके साथ चलने के लिए तैयार है। पानी के लिए पूरा देश आपके साथ है।

मैं यह कह रहा था कि वर्तमान राज्य सरकार के पास दायित्व है कि पानी और इरीगेशन के पानी को जोड़कर काम करें। मेरे लोक सभा क्षेत्र में परबन डैम, जिसकी कैपेसिटी 490 मिलियन क्यूबिक मीटर है, की बात रखी गई है। इसमें 317 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी इरीगेशन के लिए देने की बात है। लगभग 50 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी गांवों-ढाणियों को देना है। इससे स्पीकर साहब के लोक सभा क्षेत्र कोटा, बून्दी, मेरे लोक सभा क्षेत्र झालावाड़, बारां और हड़ौती क्षेत्र में 1821 गांवों को पानी देने की बात है। इसके साथ-साथ, 2970 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की बात इसमें रखी गई है। इसमें हमने तब 7,000 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया था। इसे पूर्व में, 25 नवम्बर, 2011 को एक एप्रूवल मिला था, लेकिन उसमें कोई फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं था। यह फाइनेशियल सैंक्शन, एनजीटी की सैंक्शन और पूरे सैंक्शन्स पूर्व भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही दी थी। जब उस समय के कांग्रेस उपाध्यक्ष जी हमारे संसदीय क्षेत्र में आए, उस समय वर्तमान मुख्य मंत्री जी वहां आकर, एक पत्थर लगाकर चले गए थे।

(1650/IND/KMR)

इस योजना के लिए कोई फाइनेंशियल ऐड सैंक्शन नहीं हुई थी और बाद में जो भी फाइनेंशियल ऐड सैंक्शन हुई, वह दिसम्बर, 2017 में हुई और काम चल रहा था। दिसम्बर, 2018 में सरकार परिवर्तन के बाद इसके लिए राशि देनी बंद कर दी गई। जब सब कुछ बंद कर दिया तो हमारे किसानों, हमारे कामगारों, हमारे किसानों का उत्पादन बढ़ाने और लोगों तक पानी पहुंचाने के सारे काम बंद हो गए। मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि केंद्र सरकार भी इसमें राशि दे और राज्य सरकार को उनका दायित्व बताए कि यह काम जल्दी होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बड़े भाई गजेन्द्र शेखावत जी इसमें पूरा योगदान और मदद करेंगे जिससे हाड़ौती एक क्रांतिकारी क्षेत्र बन सके और हरित प्रदेश बनकर उभरे। यह स्पीकर साहब का क्षेत्र है और हमारा भी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सोना उपजे और पूरे क्षेत्र को खुशहाली होने का मौका मिले।

सभापति जी, मैं एक बार फिर मैं अपने बड़े भाई कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को धन्यवाद देता हूं और हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि बुंदेलखंड के क्षेत्र को भी एक विशेष पैकेज मिलना चाहिए। बुंदेलखंड से लोग दूसरी जगह जा रहे हैं और इसके लिए कुछ न कुछ जरूर करने की बात है। अगर बुंदेलखंड में अच्छा काम हो जाएगा तो फ्लोरा एंड फोउना की स्थिति भी बदलेगी और यहां की प्रगति हम सभी पर निर्भर है। हम चाहते हैं कि आप सभी बुंदेलखंड पर निगाह रखें और राजस्थान पर भी निगाह रखें तथा पूर्व सरकार ने एमजीएसए के अच्छे काम किए हैं, हम चाहेंगे कि क्षेत्र का विकास हो। यह तभी होगा, जब आदरणीय मोदी साहब और आप तथा सभी लोग मिलकर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।

(इति)

1653 बजे

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): सभापति जी, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने की परमिशन दी है। मैं माननीय सांसद कुंवर पुष्पेन्द्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह रेजोल्यूशन मूव किया है - "Construction of canals through Ken-Betwa river linking-project to overcome the problems of water scarcity and stray cattle in the Bundelkhand region". जहां तक वॉटर स्कॉरसिटी की बात है, मैं एक कोट आपके सामने रखना चाहता हूं - India is not new to droughts. Between 1801 and 2002, the country experienced 42 severe droughts, one almost every five years. Between 1900 and 2006, nearly 161 million people were affected and 4.25 million people lost their lives. With almost 68 per cent of the cultivated land susceptible to drought, it is time to cut losses. Being prepared, capturing available rain, sound land and water management practices hold the key. आज हमें यह जानने की जरूरत है कि हम कैसे पानी का उपयोग करें। मैं हमारे प्रधान मंत्री जी का इस बात के लिए आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। यह उनका विजनरी स्टेप है। उनका अपना एक विजन है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक लम्बे समय से देश आजाद होने के बाद और पहले भी हम पानी की कमी से जूझते रहे हैं।

(1655/ASA/SNT)

चाहे पीने के पानी की समस्या हो या सिंचाई के लिए पानी की समस्या हो, हम हमेशा पानी की समस्या से जूंझते रहे हैं। हम देखेंगे कि देश में पानी की उपलब्धता की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसको मैनेज करना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है।

हम देखते हैं कि जगह-जगह बाढ़ आ जाती है। एक तरफ बाढ़ की स्थिति है और दूसरी तरफ पानी की कमी की स्थिति है। इस बात को हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने विजुएलाइज करके क्योंकि पानी हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसीलिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया जिससे वर्ष 2024 तक हर घर को टैप वॉटर मिल सके, ऐसी उनकी सोच है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम नदियों से नदियों को जोड़ने के बारे में सोचेंगे।

मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ-साथ हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सोच थी कि जब तक देश में हम नदियों से नदियों को जोड़ने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम किसानों को चाहे वह पीने का पानी हो या सिंचाई का पानी हो, हम नहीं पहुंचा पाएंगे। जिन नदियों में बाढ़ आती है, उनके पानी को कैनेलाइज करके, दूसरी तरफ डाइवर्ट करके, किस हिसाब से पानी का उपयोग करें, यह आज के समय की बहुत बड़ी मांग है। जिस हिसाब से हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुरेश प्रभु कमेटी का गठन किया और नदियों से नदियों को जोड़ने की जो परियोजना है, जब कमेटी ने अपनी सिफारिशें दीं तो उस समय की बात मैं बता रहा हूं कि करीब 6, 50,000 करोड़ रु. की एक योजना बनाई गई थी जिसमें कहा गया कि पूरे देश में नदियों से नदियों को जोड़ने का काम हम कर सकते हैं। उससे हर खेत को पानी

मिल सकता है, हर हाथ को काम मिल सकता है। इससे हमारी पूरी रूरल इकोनॉमी जो कृषि पर आधारित है, उसको काम मिल सकता है। इससे इंसानों के साथ-साथ हमारे मवेशियों को भी पानी मिल सकता है तथा पशु-पक्षियों को भी मिल सकता है। इससे सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण को है।

एक तरफ हमें पर्यावरण की समस्याओं से भी जूझना पड़ता है क्योंकि पानी से पेड़-पौधे भी होंगे, इससे पर्यावरण की समस्या का निदान भी होगा। इस काम को आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। अभी हमारे माननीय मंत्री शेखावत साहब इस बात को बताएंगे कि जिस हिसाब से मोदी जी के इस कार्यकाल में नदियों से नदियों को जोड़ने का और पिछले कार्यकाल में नदियों से नदियों को जोड़ने का काम शुरु हुआ है, जिस हिसाब से उसका रोड मैप बनाया गया है, उसमें कुछ में काम हुआ है और कुछ में होने वाला है। यह काम होने पर मेरा यह मानना है कि जहां बाढ़ आती है, वहां बाढ़ से निजात मिलेगी और जहां पीने के पानी की समस्या है, वह समस्या खत्म होगी क्योंकि हर क्षेत्र से किसी न किसी रूप में यह बात होती है कि पीने के पानी की बहुत विकट समस्या है।

मैं खासकर यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जिस प्रकार से सूखा पड़ता रहता है और पीने के पानी की समस्या इतनी जबर्दस्त होती है कि कई बार बड़े-बड़े शहरों को पानी ट्रेन से सप्लाई किया जाता है। देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, लेकिन देश में पीने के पानी की समस्या के निदान की दिशा में आज तक किसी ने नहीं सोचा लेकिन पहली बार हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सोचा कि इस तरह से ट्रेन से पानी नहीं जाना चाहिए, पाइप से पानी हर घर तक पहुंचना चाहिए क्योंकि पूरे देश में यह बात फैलती है कि ट्रेन से पानी पहुंचाया जा रहा है।

मैं जोधपुर की भी बात करना चाहता हूं कि एक समय था कि जब जोधपुर में भी ट्रेन से पानी आता था। पाली जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहां जोधपुर से ट्रेन से पानी पहुंचता है क्योंकि पानी की बहुत कमी है। जहां तक अंडरग्राउंड वॉटर का सवाल है, पूरे एरिया में खासकर राजस्थान के बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर सेलाइन वॉटर है, वह पीने के लायक नहीं है, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां पर पानी का उपयोग किया जा सकता है, वे ब्लॉक खत्म हो चुके हैं। इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए और जहां तक मैं पाली संसदीय क्षेत्र की बात करूं, तो पाली लोक सभा क्षेत्र में 1947 में इस समस्या का निदान करने के लिए क्योंकि उस समय जवई बांध जो 1947 में हमारे पूर्व महाराजा ने बनाया था, उस जवई बांध से जोधपुर को नहर के द्वारा और कुछ पाइपलाइन यूज करके पानी सप्लाई होता था।

(1700/VB/GM)

जब जोधपुर को राजस्थान कैनाल का पानी मिलने लगा, तो जवाई बांध से जालौर और सिरोही जिले में इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा दी जाने जाने लगी। मैं पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जवाई बांध से पाली लोक सभा क्षेत्र में पानी के लिए एक योजना बनाई। पूरे पाली जिले के लिए योजना बनाई। लेकिन जब कांग्रेस का राज आया, तो उसने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया और पाँच साल तक लोगों को उस बांध से पीने का पानी नहीं मिल पाया। लेकिन पिछले सरकार के कार्यकाल में उसको पुन: शुरू किया गया। लगभग पूरे पाली जिले में इरिगेशन और पानी पीने के लिए पाइपलाइन के द्वारा पीने का पानी पहुँचाया गया।

मैं बताना चाहूँगा कि जवाई बांध की कपैसिटी 7,300 एमसीएफटी है। इतनी कपैसिटी होते हुए, वह वर्ष 1947 से आज तक सिर्फ छह बार ओवर-फ्लो हुआ है। छह बार उसका भराव सतह तक पहुँचा है। सवाल यह है कि जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का रिजोल्यूशन पेश किया गया है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से हम जवाई बांध का पुनर्भरण कर सकते हैं। जवाई बांध के पुनर्भरण के लिए बहुत लम्बे समय से माँग चलती आ रही है।

सभापति जी, मैं बताना चाहूँगा कि साबरमती बेसिन का जो सरप्लस रन ऑफ वाटर है, साबरमती बेसिन का जो फालतू पानी है, जो आगे समुद्र में जाता है, उस पानी के लिए गुजरात सरकार से भी एग्रीमेंट बहुत पहले हो चुका था। वह पानी जवाई बांध को मिलना चाहिए। साबरमती बेसिन का 3700 एमसीएफटी पानी जवाई बांध में उपयोग किया जा सकता है।

इसके लिए पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा जी ने एक डीपीआर बनाने का आदेश दिया था। वर्ष 2016 में उसकी एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट वैपकॉस लिमिटेड के द्वारा बनाई गई, जो भारत सरकार की एक अंडरटेकिंग कम्पनी है। वैपकॉस ने अपनी रिपोर्ट बनाकर 7 मार्च, 2018 को सेन्ट्रल वाटर कमीशन को दी। लेकिन सेन्ट्रल वाटर कमीशन के कुछ ऑब्जेक्शंस थे। उनके बेस पर वैपकॉस ने रिवाइज्ड डीपीआर बनाई। उसमें डायवर्जन ऑफ सरप्लस वाटर ऑफ साबरमती बेसिन फॉर फीलिंग ऑफ जवाई डैम सब्जेक्ट क्वोट करते हुए, रिवाइज्ड डीपीआर 16 सितम्बर, 2019 को सब्मिट की गई। इसके लिए करीब 6,521 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह दो फेजेज में है। लेकिन यह रिवर लिंकिंग से संबंधित है, क्योंकि इस तरह की रिवर लिंकिंग बहुत जरूरी है। अगर यह जवाई बांध नहीं भरता है, तो पूरा-का-पूरा पाली जिला और उसके साथ-साथ जालौर-सिरोही जिले को जो पानी सप्लाई होती है, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अभी यह रिपोर्ट सेन्ट्रल वाटर कमीशन के पास है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जवाई बांध के पुनर्भरण के लिए साबरमती बेसिन की जो डीपीआर तैयार की गई है, उसको शीघ्र-से-शीघ्र सैंक्शन कर दें ताकि जवाई बांध का पुनर्भरण हो सके, जिससे पाली जिले के किसानों को इरिगेशन के लिए पानी मिल सके, पाली जिले के आम नागरिकों को पीने के लिए पानी मिल सके।

हमारे प्रधान मंत्री जी का विज़न है कि वर्ष 2024 तक हर घर को नल का पानी मिले और इसके लिए एक सर्टेनटिटी बन सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ।

(इति)

1704 बजे

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, श्री चन्देल साहब यह संकल्प लेकर आए हैं, जो नदियों को नदियों से जोड़ने का है। हमारे प्रदेश और पूरे देश के लिए इससे बड़ा और महत्त्वपूर्ण कोई बिल नहीं है। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

आदरणीय अटल बिहारी बाजपेयी जी जब प्रधान मंत्री बने थे, तो उन्होंने तीन योजनाएँ बनाई थीं, तीन बहुत बड़े सपने संजोए थे ताकि यह देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो सके।

उनका पहला सपना था, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो हर गाँव-ढाणी की गलियाँ शहर की पक्की सड़क से जुड़ सके। मोटा-मोटी वह सपना पूरा हुआ।

(1705/PC/RSG)

उनका दूसरा सपना था – 'सर्व शिक्षा', सबको शिक्षा मिले और हर गांव, ढाणी और शहर, गली के अंदर सरकारी विद्यालय खुले। उनका तीसरा सपना था, जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। आज यदि अटल जी का वह सपना पूरा हो जाता और इस देश की नदियां जुड़ जातीं तो आज यह देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो जाता।

सभापति महोदय, हमें खुशी है कि जो अटल जी के सपने को पूरा करने वाले हैं, वे हमारे सिद्धपुरुष हैं। मैं कहूंगा कि कई लोग प्रधान मंत्री मोदी जी को मानते हैं कि वे कोई साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि वे असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं और एक सिद्धपुरुष हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का जो अन्य महत्वपूर्ण सपना था, जो एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, वह थी कि देश की नदियां जुड़नी चाहिए।

मैं एक किसान का बेटा हूं। मुझे पता है कि आज इस देश में लाखों हैक्टेयर जमीन पर किसानों की खड़ी फसल बाढ़ से नष्ट हो जाती है। आखिर में वह किसान देखता रह जाता है, हताश हो जाता है, लेकिन आखिर वह क्या करे? प्रकृति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक तरफ जो लाखों हैक्टेयर जमीन है, जिस पर फसल बोई जाती है, वह सूख जाती है। मैं विशेष रूप से जिस प्रदेश से आता हूं, वह राजस्थान है। हमारे जल शिक्ति मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं। …(व्यवधान) हनुमान जी, मैं जल शक्ति मंत्री जी का ध्यान चाहूंगा। …(व्यवधान) आज इस देश के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यही सच्चाई है। अगर अटल जी का सपना पूरा हो जाता तो यह देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो जाता।

मैं राजस्थान के बारे में कह रहा हूं। इस देश का दस प्रतिशत भूभाग राजस्थान में है और इस देश का एक प्रतिशत पानी राजस्थान में है। राजस्थान इतनी उपजाऊ जमीन है कि उसे पानी मिल जाए तो वह सोना उगले। देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में राजस्थान समृद्ध प्रदेश बन जाए, लेकिन दुर्भाग्य रहा। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को जोड़ने के लिए धन भी संग्रह कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्य था कि एक वोट से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। मुझे दु:ख है कि वह एक सीट भी हमारे आदरणीय रासा सिंह रावत साहब पांच बार लगातार सांसद चुनकर आ रहे थे, लेकिन मामूली वोटों के अंतर से वे चुनाव हार गए थे और एक वोट से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी। उस सरकार के जाने से इस देश को

इतना बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी आने वाली सदियों तक भरपाई करने की स्थिति नहीं थी। हमें खुशी है कि आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदी जी प्रधान मंत्री बने हैं। …(व्यवधान)

हनुमान जी, आप इसे मजाक में मत लो। …(व्यवधान) यह किसानों की आन, बान, शान का सवाल है। …(व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): आप यह कह रहे हैं कि मंत्री जी को डिस्टर्ब मत करो। …(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): हां, मैं उनका ध्यान चाहता हूं। …(व्यवधान)

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): भागीरथ जी, हनुमान जी इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहे थे कि भागीरथ जी शायद भूल गए हैं कि वर्ष 2004 में जब अटल जी की सरकार गई थी, तब एक वोट से नहीं गई थी। वह तो वर्ष 1999 में एक वोट से गई थी। वर्ष 2004 में जब सरकार गई थी, तब तो हमारी सरकार बहुत सारे वोट्स, सीटों के डिफरेंस से गई थी। इस ओर वे ध्यान दिला रहे थे।

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): सरकार अगर एक वोट से नहीं जाती तो वह लगातार रहती। …(व्यवधान) उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि फिर यूपीए की सरकार आ गई।

सभापति महोदय, आप आसन पर विराजे हैं, इसलिए मुझे खुशी है कि मैं कुछ ज्यादा बोल लूंगा। मैं एक किसान हूं और किसान की पीड़ा समझता हूं। यदि आज नदियां जुड़ जाएंगी तो बाढ़ से जिन किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, वह नष्ट होने से बच जाएगी। राजस्थान जैसे और भी प्रदेश हैं, जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है। यदि वर्षा हो जाएगी तो वहां सोना उगलेगा। मेरा यह कहने का मतलब है कि मोदी जी का सपना है कि हर घर में नल हो और हर नल में जल हो।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा जल शक्ति मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे जल शक्ति मंत्री राजस्थान से हैं। मोदी जी ही इस काम को पूरा कर सकते हैं, बाकी कोई दूसरा कभी इस काम को पूरा नहीं कर सकता है। यदि हर खेत को पानी मिल गया तो हर हाथ को काम मिल जाएगा।

(1710/KDS/RK)

गांव में खुशहाली आ जाएगी, किसान के घर में समृद्धि आ जाएगी। बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। हमारे देश की धरती सोना उगलेगी। मैं अपने अजमेर लोक सभा क्षेत्र की बात करता हूं। यदि वहां के हर खेत तक पानी पहुंच जाए, तो हमें और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जल शक्ति मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैंने चुनाव में एक ही वादा किया था कि- 'यदि आप मुझे जिताएंगे तो हमारे सिद्ध पुरुष नरेन्द्र भाई मोदी जी पुन: प्रधान मंत्री बनेंगे और यदि वह प्रधान मंत्री बनेंगे तो ये नदियां जुडेंगी।'

महोदय, अब आम जनता बहुत आशाएं लेकर बैठी है। आपको पता ही है कि हम सोच ही नहीं रहे थे कि हम इतने मतों से जीतेंगे, लेकिन चौगुने मतों से जीतकर हम आए। यह इसी का कमाल था। नदियां जोड़ने का काम नरेन्द्र मोदी जी और जल शक्ति मंत्री जी कर सकते हैं। अत: मेरा निवेदन है कि इन नदियों को जोड़ने का जो काम है, वह इस देश के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत बड़ा काम है। यदि नदियां जुड़ जाएंगी तो राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश में खुशहाली आ जाएगी।

आपके यूपी में भी सभी नदियां जुडेंगी। आपके यहां काफी पानी व्यर्थ चला जाता है। हमारे राजस्थान में 5 साल में एक साल तो खूब वर्षा होती है, लेकिन 4 साल अकाल पड़ता है। इस बार तो इतनी वर्षा हुई कि हमारे बिसलपुर के गेट 64 दिनों तक खुले रहे और वह पानी चंबल नदी में जाकर बंगाल की खाड़ी में चला गया। अभी चौधरी साहब बोल रहे थे, कि वह पानी वहां से होते-होते पाकिस्तान चला गया। अत: इस पानी का संचय करना बहुत जरूरी है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है।

महोदय, मेरा यह निवेदन है कि नदियों को जोड़ना जरूरी है। मैं अपने लोक सभा क्षेत्र की बात करता हूं। जल शक्ति मंत्री जी, आज पूरे अजमेर लोक सभा क्षेत्र में पीने के पानी का जो एकमात्र स्रोत है, वह है बिसलपुर बांध। यदि यह न हो तो हमारा सारा क्षेत्र खाली हो जाएगा, क्योंकि नीचे फ्लोराइड युक्त पानी है। 180 एमएलडी पानी पूरे अजमेर लोक सभा क्षेत्र में है, जिसमें 300 से ऊपर ग्राम पंचायतें हैं, केकरी, नसीराबाद, पुष्कर, विजयनगर आदि कई बड़े शहर हैं। 180 एमएलडी पानी में से 100 एमएलडी पानी अजमेर शहर के लिए है। 80 एमएलडी पानी 300 से ऊपर ग्राम पंचायतों और कस्बों के लिए है। दुर्भाग्य यह है कि बिसलपुर की जो योजना बनी थी, वह अजमेर शहर के लिए थी, लेकिन पानी की समस्या हो गई। पानी जयपुर आने लगा। जल शंक्ति मंत्री जी, आज यह हालत है कि जनगणना के आधार पर गांव में 80 एमएलडी पानी स्वीकृत किया गया, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था नहीं की गई।

महोदय, मुझे पता है कि जब वर्ष 2014 में नरेन्द्र भाई मोदी जी प्रधान मंत्री बने थे और लाल किले की प्राचीर से उन्होंने पहला उद्बोधन दिया था, तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे कानों में आज भी उनकी बातें गूंजती हैं। उन्होंने कहा-'मैं छोटा व्यक्ति हूं, इसलिए छोटी बात करता हूं। देश को आजाद हुए 66 वर्ष हो गए हैं, परन्तु आज भी मेरी करोड़ों माताएं-बहनें अंधेरा होने का इंतजार करती हैं कि कब अंधेरा होगा और कब मैं शौच के लिए जंगल में जाऊं।' उन्होंने हमारे पूरे अजमेर जिले को ओडीएफ कर दिया और शौचालय बन गए। अब शौचालय बन गए हैं और 80 एमएलडी पानी है। 300 से ऊपर ग्राम पंचायतें हैं। यह बहुत बड़ा शहर है। प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय बिसलपुर डैम से जल संबंधी सारी योजनाएं बनी थीं।

(1715/MM/PS)

जब सांवर लाल जाट साहब जल मंत्री थे तो उन्होंने हर गांव और ढाणी को बिसलपुर डैम से जोड़ा था। लेकिन अब वे लाइनें पुरानी हो गई हैं और टूट गई हैं। कई गांवों में तो 6-6 महीने तक पानी नहीं जाता है। जमीन के नीचे का पानी फ्लोराइड वाला है। वह इतना खतरनाक है कि आप मनुष्य को तो छोड़िए यदि किसी पेड़ को यह पानी दे दें तो वह पेड़ सूख जाता है।

महोदय, मुझे खुशी है कि मुझे जल संसाधन संबंधी कमेटी का सदस्य बनाया गया है। यहां जल शक्ति मंत्री जी बैठे हैं और मैं चाहता हूं कि हमारे बिसलपुर डैम की ज्यादा नहीं तो एक मीटर तक की ऊंचाई बढ़ाई जाए। आप मोदी जी के पूर्व के कार्यकाल में भी मंत्री थे तो उस समय में उसकी डीपीआर भी बन गई थी। राजस्थान में भी बीजेपी की वसुंधरा जी की सरकार थी। परंतु दुर्भाग्य से प्रदेश में सरकार बदल गई और वह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। मेरा निवेदन है कि बिसलपुर डैम की ऊंचाई को एक मीटर तक बढ़ाया जाए या वहां ईसरदा बांध को बनाकर और चम्बल नदी को

ब्रह्माणी नदी में डालकर लिफ्ट के द्वारा वहां का पानी बिसलपुर में लाया जाता है तो हमारे अजमेर लोक सभा क्षेत्र की पीने के पानी की सबसे ज्वलंत समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा हर खेत को पानी पहुंच जाएगा तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए सभापति जी मेरा निवेदन है कि मेरी बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या अजमेर लोक सभा क्षेत्र की है। मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्री, पहली दफा जल की अगर किसी ने चिंता की है तो मोदी जी ने की है जल शक्ति मंत्री बनाकर और जल संग्रह करके। ईसरदा बांध बन जाए या बिसलपुर डैम की ऊंचाई बढ़ जाए ताकि मेरे लोक सभा क्षेत्र की समस्या हल हो सके। सभापति महोदय जी, आपने मुझ पर कृपा रखी उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1717 बजे

श्री गुमान सिंह दामोर (रतलाम): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने नदियों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है।

महोदय, आप जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में हर साल समाचार पत्रों में एक न्यूज़ छपी रहती है कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा और बात भी सही है। इसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि पानी नहीं होगा तो भुखमरी बढ़ेगी और भुखमरी विश्व युद्ध में बदलेगी। महोदय, मैं सबसे पहले हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री परम सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके पीने के पानी, जल संसाधन विभाग और गंगा सफाई जैसे विभागों को एक मंत्रालय के अधीन कर दिया है। इससे समन्वय बढ़ेगा और काम करने के अवसर भी बढ़ेंगे। मैं इस संकल्प को लाने के लिए हमारे बुंदेलखण्ड के सांसद पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड का पूरा भ्रमण किया है। मैंने पूरा बुंदेलखण्ड देखा है और बुंदेलखण्ड की स्थिति यह है कि हम एक हजार फीट तक भी ट्यूबवैल के लिए खोदते हैं तो पानी नहीं मिलता है। बुंदेलखण्ड में दस साल में से सात साल तक अल्पवर्षा होती है, तालाब नहीं भरते हैं। यह स्थिति बुंदेलखण्ड की है। बुंदेलखण्ड में पीने के पानी का संकट मिटाने के लिए अगर कोई साधन है तो वह है नदियों को आपस में जोड़ना। केन और बेतवा नदी हमारे मध्य प्रदेश की ही नदियां हैं और इन दोनों नदियों को जोड़ने के सिवाय इस क्षेत्र की समस्या को हल करने का दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। मैं चन्देल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्राइवेट मैम्बर्स बिल लेकर आए हैं।

पानी से क्या-क्या हो सकता है? हम कृषि से किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। लेकिन जब तक पानी नहीं होगा, तब तक हम किसानों की आय को दोगुनी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं।

(1720/SJN/RU)

महोदय, कृषि की आय को दोगुना करने के लिए हमें और भी विचार करना पड़ेगा। जैसे कृषि के साथ ही साथ हॉर्टीकल्चर, फिशरीज़, एनीमल हज्बेन्ड्री है, जब इन तीनों को आपस में जोड़ा जाएगा, तब जाकर कृषि की आय दोगुनी होगी। जब कृषि की आय दोगुनी होगी, हम जिस नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, तब हमारा ग्रामीण भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएगा। नए भारत का निर्माण होगा और नया भारत एक शक्तिशाली भारत के रूप में उभरेगा।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित कराना चाहता हूं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनामी की बात करते हैं। जब तक हम कृषि के क्षेत्र को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम कृषि के लिए पानी उपलब्ध नहीं करवाएंगे, तब तक हम 5 ट्रिलियन इकोनामी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री परम आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे जल शक्ति मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में हम 5 ट्रिलियन इकोनामी को जरूर हासिल कर सकेंगे। आज हमारे माननीय मंत्री जी भी सदन में बैठे हैं। इसमें जो आने वाली

अड़चनें हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। नदियों को जोड़ने में जो सबसे बड़ी अड़चन है, वह वन और पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि तीन-तीन और चार-चार सालों तक अनुमति नहीं मिलती है। यही हाल हमारी बेतवा और केन के इंटर्लिंकिंग में हुआ है। हमें ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जहां पर वन और पर्यावरण की अनुमति चाहिए। उस अनुमति के लिए एक समय निर्धारित होना चाहिए। छः माह का समय निर्धारित हो या एक साल का समय निर्धारित हो, लेकिन इसमें बहुत विलंब होता है। दूसरा, यह मामला इंटरस्टेट भी होता है और इसमें दोनों राज्य सरकारों की सहमति भी आवश्यक होती है। इसके लिए नेशनल लेवल पर एक समिति का भी गठन होना चाहिए, जो तत्काल निर्णय ले सके। इसके साथ ही उस समिति को पूरे अधिकार देने चाहिए, ताकि इंटर्लिंकिंग के मामले में जो भी लीगल कॉम्प्लिकेशन्स आएं, उनका तत्काल हल किया जा सके। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश से हूं और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जिसने नदियों को जोड़ने का काम किया है। आपको इस बात की जानकारी होगी कि वर्ष 2016 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। इस कुंभ मेले में जो व्यवस्था की गई थी, वहां नदियों को जोड़ने के कारण ही पानी की व्यवस्था हो पाई थी। वरना जो हमारी क्षिप्रा नदी है, वह तो गर्मियों में सूख जाती है। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्य मंत्री परम आदरणीय शिवराज जी को भी आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छे भविष्यदृष्टा बनकर मध्य प्रदेश में नदियों को जोड़ने का काम शुरू किया था।

महोदय, मुझे अगर सबसे पहले नदियों को जोड़ने का काम देखने को मिला था, तो वह गुजरात में मिला था। हमारे देश के प्रधान मंत्री परम आदरणीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्य मंत्री हुआ करते थे, तब गुजरात में पीने के पानी का संकट सबसे अधिक था। विशेषकर जो कच्छ या रण का एरिया है, वहां पर बहुत बड़ा संकट था। हमारे परम आदरणीय मोदी जी की इच्छाशक्ति के कारण आज गुजरात में वॉटर ग्रिड बन गया है। गांव-गांव में पीने की पानी की व्यवस्था कर दी गई है और तालाबों को नहरों से जोड़ दिया गया है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि आप गर्मी के दिनों में जाकर साबरमती का रिवरफ्रंट तो देखिए, आपको ऐसा आनंद आएगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह वही साबरमती नदी है, जिसमें गर्मी के दिनों में सीवर का पानी भी सूख जाता था। साबरमती नदी की यह हालत थी। आज जो नर्मदा की मेन केनाल - राइट बैंक केनाल है, उस राइट बैंक केनाल को साबरमती से जोड़ दिया गया है। आज साबरमती नदी पूरी गर्मियों में लहलहाती है और पानी से पूरी भरी रहती है। गुजरात के उस क्षेत्र के सभी तालाब पानी से फुल रहते हैं।
(1725/GG/NKL)

वहां पर आज पशुधन की संख्या बढ़ी है, दुग्ध उत्पादन बढ़ा है, मछली पालन का धंधा बढ़ा है और गर्मी के दिनों में तीसरी फसल ले रहे हैं तो किसान क्यों संपन्न नहीं होगा। कोई ताकत उसको संपन्न होने से रोक नहीं सकती है। इसलिए इंटरलिंकिंग हमारे देश की और आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। महोदय, इसलिए मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के रतलाम लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ। मेरे लोक सभा क्षेत्र में ग्राउंड वाटर की बहुत बड़ी समस्या है। पानी के लिए हजार-हजार फीट के ट्यूबवेल खोदते हैं, तब मिलता है। जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या आती है और फ्लोराइड युक्त पानी मिलता है। उस फ्लोराइड युक्त पानी से न तो खेती ढंग से कर सकते हैं, न मवेशियों को पिला सकते हैं, न खुद पी सकते हैं। ऐसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उस क्षेत्र में हमारे पास बड़े-बड़े तालाब नहीं हैं। ऐसी स्थिति में इंटरलिंकिंग रिवर कनैक्शिन के माध्यम से ही हम पानी की समस्या दूर कर सकते हैं। नदियों को जो हमारी कई नदियां जो पहले कल-कल कर के बहती थीं, अब वे सूख चुकी हैं। अगर इन नदियों को भी जीवित करना है तो सबसे बढ़िया अच्छा उपाय है रिवर इंटरकनैक्शन। मैं इस अद्भुत विधेयक प्राइवेट बिल के लिए चन्देल साहब को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे यहां पर ग्राउंड वाटर की पोजिशन यह है कि सभापति महोदय, कि गर्मी के दिनों में हमारे अधिकतर ट्यूबवैल बंद हो जाते हैं। जैसे हमारे एक पूर्व वक्ता ने कहा कि हमको टैंकर के माध्यम से पानी लाना पड़ता है तो यही स्थिति हमारे उस क्षेत्र की भी है। धावा जिले में, अलीराजपुर जिले में, रतलाम जिले में और पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में गर्मी के दिनों में बहुत बड़ी समस्या होती है। इस समस्या को देखते हुए, इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए हमारे प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री परम सम्मानीय शिवराज चौहान जी ने सबसे पहले नर्मदा और क्षिप्रा नदी को जोड़ा। दूसरा, जम्नी नदी को जोड़ा। इस प्रकार से सबसे अच्छा काम अगर मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, तो यह रिवर इंटरलिंकिंग का काम किया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर लाना चाहता हूँ कि हमारा एक लक्ष्य है। लक्ष्य यह है कि 2024 तक जल-जीवन शक्ति मिशन के माध्यम से हर घर को नल से जल। महोदय, अगर जल होगा, तभी तो हम घर में नल से जल दे पाएंगे। नहीं होगा तो देंगे कहां से? आज आवश्यकता इस बात की है कि पहले जल उपलब्ध करवाएं और चूंकि बहुत पास का समय लिया है – सन् 2024 तक का समय लिया है, इसलिए उन नल-जल योजनाओं को जो सर्फेस वाटर सोर्स के आधार पर बनी हैं, उनको अगर हम बना कर वाटर सप्लाई करेंगे, तभी यह मिशन सक्सेस होगा और इस मिशन को सक्सेस करने के लिए रिवर-इंटरकनैक्शन आवश्यक है।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे यहां पर अभी हमारे यहां पर ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन की स्थिति यह है कि रोज आप विज्ञापन देख रहे होंगे, यहां दिल्ली का भी विज्ञापन आ रहा है ग्राउंड वाटर की पोज़िशन बहुत खराब हो गई है। हम जमीन से और ज्यादा पानी नहीं ले सकते हैं। जिंदा रहने के लिए पानी आवश्यक है, इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। हमको सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर नदियों को जोड़ कर हर घर को जल उपलब्ध करवाने का एक अच्छा रोड मैप बने। दूसरा, हमारे मंत्री महोदय आज सदन में उपस्थित हैं, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम कृषि की आय को दोगुनी करना चाहते हैं, परंतु आज तक मेरी जानकारी में नहीं है कि हमने वाटर बजट बनाया हो।

(1730/KN/KKD)

हमको कृषि के लिए कितना पानी चाहिए, हमको पीने के लिए कितना पानी चहिए, हमको उद्योग-धंधे के लिए कितना पानी चाहिए और किस राज्य की कितनी आवश्यकता है, किस जिले की कितनी आवश्यकता है? ऐसा डिटेल्ड वाटर बजट बनाएंगे और उस डिटेल्ड वाटर बजट के आधार पर हमारे पास कितना जल उपलब्ध है और हमें कितने जल की आवश्यकता है? वह जल हम इकोनॉमिकली कहाँ-कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? इस बारे में हमको प्लान बनाने की आवश्यकता है। वाटर बजट हमारी एक अनिवार्य आवश्यकता है और इस अनिवार्य आवश्यकता के संबंध में मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन में बैठे हुए माननीय मंत्री जी कदम उठाएंगे। आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए हमको पानी की आवश्यकता है। बिना पानी के हम कृषि अच्छी कर ही नहीं सकते हैं, कृषि में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमें हर राज्य में कृषि के लिए कितना पानी चाहिए, पूरा वाटर बजट बना कर फिर हम पानी के संग्रहण की व्यवस्था करें। जब हमारे पास तालाब बनाने की स्थिति नहीं हो, डैम बनाने की स्थिति नहीं हो, आप जानते हैं कि डैम बनाने में कितनी परेशानियाँ आती हैं। जब डैम बनाने में जमीन जाती है तो कितने आंदोलन होते हैं, परन्तु एक रिवर इंटर कनेक्शन ऐसा है कि हम कम परेशानी में अच्छा काम कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पुन: आग्रह करूँगा कि पीने के पानी के लिए, कृषि के पानी के लिए, उद्योग-धंधों के पानी के लिए एक बजट बनाया जाए। बजट बना कर हम फिर असेस करें कि हमको किन-किन नदियों को जोड़ना है? यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर होना चाहिए। यह समय की माँग है। आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बुंदेलखंड के सांसद कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे इस सदन में यह महत्वपूर्ण बिल लाए। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1732 बजे

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): सभापति महोदय, धन्यवाद। कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह जी जो संकल्प रखा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण, किसानी और किसानों के जीवन से जुड़ा हुआ है। महोदय, आज पानी का स्वरूप, पानी की प्रकृति बदल चुकी है। पानी को सोखने की क्षमता जो धरती में थी, वह भी कमजोर हुई है। पहले पानी लगातार तीन महीने, चार महीने बरसता था, बूंद-बूंद करके बरसता था। चार-चार, पाँच-पाँच दिन लगातार वर्षा की झड़ी लगी रहती थी। धरती उस जल को सोख कर तृप्त हो जाती थी। तमाम खेतों में बुलबुले उठने लगते थे। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि पानी आया, एक घंटे, डेढ़ घंटे और दो घंटे में बह कर, बड़ी झड़ी करके बाढ़ के रूप में परिवर्तित होकर चला गया। मिट्टी की जल सोखने की क्षमता लगभग 25 प्रतिशत कम हुई है। जिस तरह से हमने उर्वरकों का बेतहाशा इस्तेमाल किया है, कभी ध्यान नहीं दिया कि यह उर्वरक अनाज तो पैदा कर रहे हैं, उपज तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा पत्थर के रूप में हमारी मिट्टी में समाता जा रहा है। इस वजह से आज भूजल में कमी आ रही है। उसका बहुत बड़ा कारण धरती के पानी को सोखने की क्षमता में आई बहुत बड़ी कमी है और वर्षा की प्रकृति के बदलाव के रूप में भी जो परिवर्तन हुए हैं, उसके परिणामस्वरूप आज पूरा देश जल के गम्भीर संकट से गुजर रहा है। हमारे देश में विश्व की 18 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, 17 प्रतिशत पशु धन है और 4 प्रतिशत भूगर्भ जल है। उसमें भी जनंसख्या तो बढ़ेगी, पाँच साल, दस साल के अंदर हम जनसंख्या के मामले में दुनिया के नम्बर एक देश बन जाएँगे। पशु धन कृषि का एक अभिन्न अंग है। अनाज, पशु और फल-सब्जियाँ, इन तीनों को समन्वित रूप से जब विकसित किया जाएगा, तभी जाकर इस देश की कृषि की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। किसान की हालत सुधरेगी।

(1735/CS/RP)

इसलिए पशु हमारे लिए अनिवार्य है और पशु के बिना हम रह नहीं सकते हैं। आज पानी की आवश्यकता अधिक है बनिस्पत जितना पहले था। वर्ष 2001 में 1811 घन मीटर पानी प्रति व्यक्ति के हिस्से में था, वर्ष 2011 में 1545 घन मीटर पानी प्रति व्यक्ति के हिस्से में रह गया, वर्ष 2025 में 1340 घन मीटर पानी प्रति व्यक्ति के हिस्से में रह जायेगा और वर्ष 2015 में 1140 घन मीटर पानी प्रति व्यक्ति के हिस्से में रह जाएगा।

महोदय, 1700 घन मीटर पानी प्रति व्यक्ति को अभावग्रस्त कह सकते हैं। जिस दिन एक हजार घन मीटर पानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से आ जाएगा, उस दिन हम पानी का संकट मान सकते हैं और वह भयावहता करीब-करीब नजदीक है। वह भयावहता बहुत नजदीक आने वाली है। यह आकलन तो अभी लगाया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में हमें 35 करोड़ और लोगों को अनाज देना है। आने वाले समय में 35 करोड़ और लोगों के लिए भोजन की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए कृषि उत्पादन के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।…(व्यवधान) मैं कह रहा हूँ कि अभी 35 करोड़ लोग और बढ़ेंगे। आज तो हम खा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में सुरसा का मुँह फैलाकर जो आबादी बढ़ेगी, उसको खिलाने का चैलेंज हमारे सामने होगा। इस मुल्क के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वर्ष 2050 तक 35 करोड़ लोग जो और टपकेंगे, उनको भोजन कहाँ से

मिलेगा।…(व्यवधान) टपकाये जाएंगे या टपकेंगे, जो भी होगा, बहरहाल ये 35 करोड़ और आने वाले हैं। इनको भोजन कहाँ से मिलेगा, इस देश की सबसे बड़ी चुनौती यह भी है। आज हम इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अनाज तो मिलता ही रहेगा, हम खाते ही रहेंगे, इसकी कमी नहीं आयेगी। आज जो यह मौसम का परिवर्तन हो रहा है, आज जलवायु परिवर्तन के कारण, आज हमारे कृषि वैज्ञानिक वहाँ लैबोरेटरीज में मर रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चिंता है कि हम कैसे कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा गर्मी सहने वाली फसल को तैयार करें और 150-160 करोड़ लोगों को भोजन भी दें। आज हमारे मुल्क के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है। इसे आज गंभीरता से हमारे कृषि वैज्ञानिक और हमारी सरकार ले रही है, लेकिन जनता को लगता है कि यह तो अभयदान है, यह मिलता ही रहेगा। जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ हैं, पानी, सिंचाई के साधनों की समस्या है, वह बहुत भयावह है। मुझे खुशी है कि नरेन्द्र मोदी जी एक वरदान के रूप में आए हैं और उन्होंने पानी की ताकत, चुनौती को और पानी के कारण आने वाले संकटों को बहुत गंभीरता से सोचा है और वे एक दूरदृष्टि नीति-नियंता के रूप में हमारे सामने आए हैं। इस वजह से उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जिस तरह से काम हो रहा है, वह वास्तव में इस बात का संतोष देता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पार हो जाएंगे। पार होने के लिए किसी जादू की छड़ी नहीं, उसके लिए संकल्प शक्ति की आवश्यकता है।

महोदय, जिस तरह से रेल की कनेक्टिविटी अंग्रेजों ने बढ़ाई और बड़े गर्व से कभी-कभी कुछ लोग कह देते हैं कि रेल में जो कुछ किया, वह अंग्रेजों ने किया। रेल में अंग्रजों ने क्या किया- मैनचेस्टर में जितना पैसा उनका पानी के वितरण की व्यवस्था में खर्च होता था, अकेले पानी के वितरण की व्यवस्था में, उतना उस काल में स्वास्थ्य, शिक्षा और जो भी जनकल्याण के कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, इन सबका कुल बजट उतना नहीं था, जितना मैनचेस्टर के पानी के वितरण की व्यवस्था का बजट था। रेल की व्यवस्था तो उन्होंने हमें गुलाम बनाने के लिए की थी। उन्होंने अपने व्यापार के लिए, युद्ध के लिए रेल की व्यवस्था की थी और हमारा खून चूसकर किया। इसी तरह से उन्होंने पानी के मामले में भी सोचा था कि हम नदियों को जोड़कर, नदियों, नहरों के माध्यम से एक और संचार व्यवस्था स्थापित करेंगे।

(1740/RV/RCP)

इसके लिए सबसे पहले काटन नामक अँग्रेज ने एक प्रस्ताव किया था कि इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन दुर्भाग्य रहा, अब दुर्भाग्य ही कहना पड़ रहा है, यह शब्द निकल आया कि दुर्भाग्य रहा कि काटन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल के पहले इस बात को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई। इसके बारे में देश ने कभी प्राथमिकता से सोचा ही नहीं। कभी कोई बातचीत हुई होगी, कभी कोई टेबल-टॉक हुआ होगा, लेकिन जनता के सामने, इस देश के सामने सबसे पहले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो दृष्टि सामने आई, उससे लगा कि यह भी एक कल्याणकारी माध्यम हो सकता है। आज हर जगह, कुछ एनजीओज़ को छोड़ दीजिए, कुछ गिटर-पिटर बोलने वालों को छोड़ दीजिए, तो बाकी सारा देश यह चाहता है। यह आवश्यकता है, नहीं तो जीव-जन्तु सब मर जाएंगे। हमारे यहां पन्ना में किसी मुर्गी ने तीन अंडे दे दिए तो दस सालों तक यह कहा गया कि वे

तीन अंडे किस पक्षी के हैं, उसे ढूँढ़ो। तीन अंडों की वजह से हमारे यहां ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन, जो हमारे क्षेत्र को कुँवर साहब के क्षेत्र से जोड़ती है, उसे उन तीन अंडों ने बारह-तेरह सालों तक रोक कर रखा गया। जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने इन तीन अंडों वाली बात को बहाया और वह रास्ता खुला। हम इन तीन अंडों वाली कहावत को भुगत चुके हैं। हमारे इलाके ने इसे भोगा है, इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ एनजीओज़, कुछ गिटर-पिटर वाले विदेशी एजेंट्स का एक जाल बना हुआ है, जो इस मुल्क के लोगों को जैव-विविधता और इस तरह के तमाम पाठ पढ़ाते रहते हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि यह मुल्क तुम्हारे शोषण के लिए, तुम्हारे फैशन के लिए तभी रहेगा, जब इसे भोजन मिलेगा। तुम तो केक खा लोगे। कल मैं कहीं देख रहा था कि फ्रांस की कोई साम्राज्ञी थी, जिसने कहा था कि रोटी नहीं मिलती है तो केक खाओ। इसलिए एनजीओज़ और जैव-विविधता का प्रसंग छेड़ने वाले तो केक खा लेंगे, लेकिन इसमें हम मरेंगे। वे गरीब मरेंगे। वे लोग मरेंगे, जिनके लिए कृषि वैज्ञानिक चिंतित हैं कि वर्ष 2050 में इन 160 करोड़ लोगों को भोजन कैसे मिलेगा?

महोदय, यहां जल शक्ति मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इन सब चिंताओं को छोड़ दीजिए। ये सभी फैशनेबल चीजें हैं। ये हमारे-आपके लिए नहीं हैं क्योंकि गरीब को रोटी चाहिए। जैव-विविधता बन जाएगी, पर यह जैव-विविधता कैसे बनी? जैव-विविधता तब बनी कि हजारों सालों से कोई नदी बह रही है, वहां जंगल हैं तो वहां तरह-तरह के जीव पैदा होने लगे। इसी तरह से, अगर यह नहर बन जाएगी तो इसके आस-पास जंगल बन जाएंगे तो वहां भी एक नई जैव-विविधता प्रकट हो जाएगी। क्या जैव-विविधता कहीं आकाश से टपकी है? प्रकृति का जो वातावरण रहा, उस वातावरण की दृष्टि से एक प्राकृतिक संतुलन कायम हुआ। मुझे पूरा भरोसा है कि हम जिस तरह की प्रकृति का निर्माण करेंगे, जिस तरह के वातावरण का निर्माण करेंगे, उस आधार पर प्रकृति अपने आप को ढाल लेगी। इसलिए ये सब जो फैशन डिजाइनर्स हैं, इनसे थोड़ा बच कर रहने की जरूरत है।

महोदय, हमारा क्षेत्र और बुंदेलखण्ड कभी एक हुआ करता था। विंध्य प्रदेश के जमाने में हमें बघेलखण्ड कहा जाता था और चन्देल साहब के इलाके से लगे हुए इलाके को बुंदेलखण्ड कहा जाता था। जब हमारे क्षेत्र मर्ज हुए तो हमारा कुछ भाग मध्य प्रदेश में रहा और इनके क्षेत्र का कुछ भाग यू.पी. में चला गया और कुछ एम.पी. में चला गया। लेकिन इसके साथ-साथ इन्होंने जो अन्ना प्रथा की बात कही, हम भी उसी से पीड़ित हैं। हम अपने खेतों को दिन-रात पानी देते हैं, उसमें हल चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं लेकिन रात में जैसे आतंकवादी आकर झपटते थे, उसी तरह से ये आवारा पशु, किसान जाग रहा है, पर वे 100 के झुण्ड में आए और आधे घंटे के अन्दर पूरी फसल को नष्ट करके चले गए, उसे खत्म कर दिया और हमारी साल भर की कमाई, साल भर की मेहनत चली जाती है। किसान टकटकी लगा कर देखता रहता है। इसलिए पानी तो चाहिए। केन-बेतवा जुड़नी चाहिए। सारे देश की जो ये 30 परियोजनाएं हैं, इन्हें पैसा मिले। चाहे जैसे भी हो, चाहे टैक्स लगाकर इसे जुटाना पड़े, पर इन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये जो आवारा पशुओं, अन्ना प्रथा की जो समस्या है, वह हमारे इलाके और इनके इलाके, दोनों इलाके के फसल को खत्म कर रही है, बर्बाद कर रही है। हम तो थोड़ा ठीक हैं कि हमारे यहां अभी पन्द्रह वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। केवल हमारे जिले में ढाई लाख एकड़ तक बाणसागर का पानी गया और ढाई

लाख एकड़ हम पाँच सालों के अन्दर और सींच लेते, लेकिन अब एक कुदाल भी नहीं चल रहा है। हमारे यहां नहरों का सारा काम बंद हो गया है। चन्देल साहब, आपके यहां तो कुछ शुरू हो रहा है, लेकिन हमारे यहां बंद हो रहा है। इससे लगता है कि दोनों बराबर हो जाएंगे।

हमारे यहां जो सरकार आई है, उसने वादा किया था कि हम हर पंचायत में गोशाला खोलेंगे। किसानों ने यह माना कि हर पंचायत में गोशाला खुलने पर आवारा पशुओं से निजात मिलेगी, इसलिए वोट दे दो।

(1745/MY/SMN)

अब कहीं कोई नाम नहीं ले रहा है, कोई गौशाला नहीं खुल रही है और उस सिलसिले में कोई काम नहीं हो रहा है। आज मैं यहां बैठा हूं। आप वहां जाकर देखिए कि एक-एक किसान डंडा लेकर अपने खेत के मेड़ पर खड़ा है। 100 मवेशी इधर भाग रहे हैं, 200 मवेशी उधर भाग रहे हैं। 25 यहां गिर रहे हैं और 50 वहां गिर रहे हैं। वहां लाठियां चल रही हैं और झगड़े हो रहे हैं। अगर इस गांव के मवेशी को उस गांव में भगाया जाता है, तो उस गांव के लोग लठ लेकर खड़े रहते हैं कि हमारी तरफ क्यों आ रहे हो।

महोदय, इतना ही नहीं, इन्होंने जो गौशाला खोलने का आश्वासन दिया था, वह खत्म हो गया। आज मध्य प्रदेश में किसानों को किसान सम्मान निधि का 6000 रुपये नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। आप लोग भाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को मुख्य मंत्री बनाया है। आपके प्रदेश में किसानों को डेढ़ साल का लाभ मिल गया है, लेकिन हमारे यहां किसानों को एक किस्त भी नहीं मिली है। अगर मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को 6000 रुपये दे दे, तो किसान कम से कम उससे बाड़ लगा लेगा।

महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से चन्देल साहब को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े मुद्दे को सदन में चर्चा के लिए एक बिंदु बनाया। जल शक्ति मंत्री जी यहां पधारे हुए है, उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस चर्चा को सुना है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो नदी जोड़ो अभियान है, उसमें हमारी सरकार सफल होगी और इस मुल्क के किसानों का बहुत बड़ा भला होगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

(इति)

1747 बजे

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सभापति महोदय, अगर आप आज्ञा दें, तो मैं यहां से बोलना चाहूंगा।

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): ठीक है।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आदरणीय कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे इस संकल्प को लाए हैं इस विषय पर कई हफ्तों से चर्चा चल रही है। केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से दो नदियों को इंटर लिंक करने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो केन नदी है, उसका सरप्लस वाटर बेतवा नदी में जाएगा। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के जो जिले पूरी तरह से सूखे से ग्रस्त रहते हैं, उनको इस समस्या से निजात मिलेगी। खास तौर पर उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, इस क्षेत्र में झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा और मध्य प्रदेश का टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर जिले आते हैं। इन सभी जिलों को इस प्रोजेक्ट से बहुत फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ वहां तक पीने का पानी पहुंचाया जा सकेगा, बल्कि इस क्षेत्र के 47 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको आगे जरूर बढ़ाना चाहिए।

मान्यवर, किसी भी बड़े निर्णय के दो पहलू होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही किसी बड़े निर्णय के दो पहलू होते हैं। सबसे पहले किसी कार्य को आगे करने के लिए उसके जो एडवांटेजेज़ होते हैं या प्रोएक्टिव एप्रोच होते हैं, उनपर डिसकस करना जरूरी होता है। इस विषय पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ सूखे क्षेत्र के ग्राउंड वाटर को ठीक करेगा, बल्कि वहां जो भूजल समस्या आ रही है, भूमि में पानी की सतह गिरती जा रही है, उसको भी बढ़ाने का काम करेगी। इसके साथ ही जो तमाम लोग सूखे से प्रभावित होते हैं, उन तक पानी पहुंचा कर एक बहुत बड़ी समस्या से निजात दिलाया जा सकेगा। यह हमारे किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी।

मान्यवर, इसके साथ ही आप यह भी देखेंगे कि जब यह प्रोजेक्ट शुरू होगा, तब काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारी आज की जो अर्थव्यवस्था है, उसको सुधारने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसलिए उनके ऊपर भी हम लोगों को इस सदन में जरूर चर्चा करना चाहिए और वह सदन के सामने आना चाहिए। अभी हमारे एक सदस्य ने कहा कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स की संस्तुति मिलने में तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, क्योंकि हमारी जो एन.जी.टी. वगैरह हैं, वे इन प्रोजेक्ट्स को रोकने का काम करती हैं। मैं समझता हूं कि उसका भी कारण है, क्योंकि हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है, उसके साथ हम ऐसा कोई निर्णय न लें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को उसका खमियाजा भुगतना पड़े। हमें उनको संज्ञान में लेना जरूरी होता है और इतने बड़े प्रोजेक्ट में जाने से पहले विचार करना जरूरी रहता है।

(1750/CP/MMN)

इसमें एक बड़ा रिस्क आएगा। सुबह आदरणीय रूडी जी ने बाघों के ऊपर चर्चा की, वे उसके सदस्य भी हैं। अगर आप कभी गए हों, वह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। खास तौर से उत्तर प्रदेश

और मध्य प्रदेश, क्योंकि यह मध्य प्रदेश में है, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक धरोहर है। करीब 10 पर्सेंट जमीन पन्ना टाइगर रिजर्व की जमीन पानी के अंदर चली जाएगी और तमाम एरिया में पेड़ों को काटने का काम करना पड़ेगा। 20 हजार लोग इससे प्रभावित होंगे। 20 हजार लोगों की जमीन इस सरोवर में चली जाएगी, जो यहां बनाया जाएगा। खास तौर से जो धौधान सरोवर बन रहा है, उसके अंदर चली जाएगी। इनमें 15.5 शेड्यूल्ड कास्ट्स और 34.4 शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ बिरादरी के लोग हैं।

मान्यवर, मैं यहां एक चीज और प्रकाश में लाना चाहता हूं। हमारे सबसे दबे-कुचले तबके के ऊपर जब उसके साथ इतना बड़ा अन्याय होता है, जब वह अपनी जमीनों से हटाया जाता है या उसको दरकिनार किया जाता है, तो उसकी आवाज बहुत जल्दी उठ नहीं पाती है। एक तो वह कमजोर है, अशिक्षा भी आड़े आती है और इसकी वजह से संगठित नहीं हो पाते हैं। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और आंदोलन करते रहो। शिक्षा के अभाव में, संगठन के अभाव में अपने आपको एकजुट न करके वे आंदोलित नहीं हो पाते हैं, इसलिए बहुत बड़ी समस्यायें उनके ऊपर आती हैं। ये 20 हजार लोग कहां जाएंगे?

मेरे अपने क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंतर्गत एनटीपीसी टांडा ने विस्तारीकरण किया। उन्होंने जमीनें एक्वायर कीं। जमीन एक्वायर करने के बाद आपने देखा कि पुनर्वास एक्ट के हिसाब से जो जमीन उनको मिलनी चाहिए थी, जिस पर घर बनाकर उनको पुनस्थार्पित करना चाहिए था, वह उन्हें नहीं मिली। इसकी वजह से वे आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। दलितों के घर तोड़े जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है और सर्वसमाज के लोगों को वहां जबरन बाहर निकाला जा रहा है। इस पर हम लोग कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। केन, बेतवा रिवर में 20 लोगों की बात हो रही है। इस पर जरूर चर्चा करने की जरूरत है और इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है।

महोदय, मुझे दो मिनट और दे दिए जाएं, मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे बड़े भाई हनुमान जी बैठे हुए हैं, इनके आशीर्वाद से मुझे यह समय मिला है। चाइना में भी ऐसा काम हुआ है। उन्होंने तमाम नदियों को जोड़ा है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक 3 बड़ी नदियों को जोड़ कर उन्हें बड़ी सफलता भी मिली है। यहां पर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमें अपने लोगों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मैं अपने क्षेत्र अंबेडकर नगर की भी बात करूंगा। अंबेडकर नगर में पानी की स्थिति अत्यन्त ही भयावह है। हर जगह वाटर लेवल गिरता चला रहा है। उसको बढ़ाने के लिए हमें कोई ठोस नीति लेकर आनी होगी। हर जगह इतना कांक्रीट हो गया है कि वर्षा का सारा पानी बहकर नदियों में चला जाता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है। ऐसी नीतियों में हमें इस समय, जब हम नदियों को जोड़ रहे हैं, तो हमें जरूर इस पर सोचना और विचारना चाहिए कि हम अपने ग्राउंड वाटर लेवल को कैसे चार्ज करें?

केन-बेतवा रिवर का जो प्रोजेक्ट हो रहा है, यह भले ही बुंदेलखंड के किसानों के लिए एक अच्छे वरदान के रूप में साबित होगा, लेकिन जो 20 हजार लोग शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ बिरादरी से आते हैं, इनके बारे में जरूर हमें सोचने की जरूरत है। इस सदन में अगर हम

उनको आज निराश करेंगे, उनकी अगर इस सदन में चर्चा नहीं होगी, तो कहीं न कहीं देश की एक बड़ी पॉपुलेशन के साथ हम अन्याय करने का काम करेंगे।

आपने मुझे इस रिजोल्यूशन पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय चंदेल जी को भी मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण विषय को उठाने का काम किया।

(इति)

(1755/NK/VR)

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सभापति महोदय, आपकी मेरी ऊपर बड़ी कृपा रहती है। माननीय सदस्य पुष्पेन्द्र सिंह जी प्राइवेट मेंबर्स बिल पर रिजोल्यूशन लेकर आए हैं, बुंदेलखंड का संकल्प लेकर आए हैं। छूटा गो-वंश की समस्या को दूर करने और केन-बेतवा संपर्क नदी परियोजना द्वारा नहरों के निर्माण से जुड़े संकल्प पत्र का मैं समर्थन करता हूं। इन्होंने इसको बनाने में बहुत मेहनत की है। इन नदियों के जुड़ने से जिनका पुनर्वास होगा, उसमें पुर्नवास की अच्छी व्यवस्था को सुझाव के रूप में ले सकते हैं। इन नदियों को जुड़ने से पचास हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और लाखों लोगों को बहुत फायदा होगा। इन्होंने निश्चित रूप से कड़ी मेहनत की है। नदियों को जोड़ने की योजना थी। हम जब स्कूल-कॉलेज के अंदर पढ़ा करते थे तब सोचा नहीं था कि नदियों को जोड़ने की योजना भी आएगी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी, अब प्रधान मंत्री जी ने उनका सपना पूरा किया है।

भारतमाला परियोजना बार्डर पर जम्मू से कांडला तक बन रही है। उसी तरह नदी-नाले देश के अंदर जुड़ जाएंगे, उस दिन देश बहुत अग्रसर होगा, विकसित भारत होगा। प्रधान मंत्री जी ने भारत का मान वर्ल्ड के अंदर बढ़ाया है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधान मंत्री जी के इंतजार में खड़े रहते हैं। हाउडी मोडी कार्यक्रम ने वर्ल्ड को बता दिया कि भारत कैसा देश है। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल है।

अब प्रधान मंत्री जी से जब हम व्यक्तिगत रूप से मिले। हमारे जल शक्ति मंत्री राजस्थान से आते हैं और हमारे पड़ोसी हैं। मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी कैसे मिले, प्रत्येक खेत के लिए अगर सिंचाई योजना बन गई तो उस दिन बेरोजगारी की समस्या का समाधान 70 प्रतिशत अपने आप हो जाएगा। जो गांव खाली हो रहे हैं, गांवों से लोग पलायन करके दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और अन्य राज्यों की राजधानियों में या जो पड़ोसी शहर हैं, वहां जा रहे हैं। वहां लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी खेती सूख गई है।

हम राजस्थान की बात करें। हमारे राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर और कोटा के कुछ अंचल को छोड़ दें तो सिंचाई कहीं नहीं होती। मेरा विधान सभा और लोक सभा क्षेत्र है, माननीय मंत्री जी का लोक सभा क्षेत्र है, जहां एक हजार-बारह सौ फीट धरती का सीना चीरकर किसान ट्यूबवेल लगा कर काम करते हैं, जब ठंढ के अंदर सरकार ज्यादा पानी देती है, उस ठंढ के अंदर भी परिवार का पेट पालने के लिए अन्न उत्पादन करता है और स्टेट के लिए भी भरपाई करता है।

1758 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

नेपाल में पंचेश्वर शारदा नदी पर हमारा बांध प्रस्तावित है। अगर यह बांध पूरा बन जाए और यमुना से पानी को लाया जाए तो राजस्थान का सीकर, झुंनझुनु और चुरू जिले उसके साथ जुड़ जाएंगे। यमुना से मानसून के समय 1754 क्यूसेक पानी राजस्थान का हिस्सा है, उस योजना के लिए हरियाणा और राजस्थान में समझौता भी हो चुका है। उस परियोजना की डीपीआर सीडब्ल्यूसी को भेजी गई है। उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा कर भेजी है। राजस्थान सरकार के पास बीस हजार करोड़

रूपये की लंबित परियोजना है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस योजना को आप राजस्थान सरकार से जल्दी मगवाएं, इससे राजस्थान में दो लाख एकड़ की सिंचाई नए सिरे से मिलेगी। सीकर, झुंनझुन और चुरू के अलावा नागौर और जोधपुर है।

अध्यक्ष जी जहां से आप आते हैं, पुराने समय में जब अकाल पड़ता था तो बुजुर्ग लोग कोटा अंचल में मारवाड़ के लोग कमा कर खाने के लिए जाते थे। आज भी पशुधन सबसे ज्यादा कहीं से लेकर आते हैं तो वह कोटा, बूंदी और हड़ौती से आते है। हमारे नेताओं की कभी सोच ही नहीं रही कि यहां विकास होना चाहिए। हमारे नेता ऐसे भाषण देकर जीत जाते थे कि बिजली आएगी तो करंट आ जाएगी। लोग उस पर ताली बजाते थे। हमने उन लोगों को जागरूक किया। मैं पुराने नेताओं की बात कर रहा हूं। आने वाले समय में जो संघर्ष या क्रांति होगी वह जल के लिए होगी। आज हम जल को लेकर चिंतित हैं। बढ़ती आबादी को कैसे रोका जाए, बढ़ती आबादी के साथ-साथ प्रत्येक घर को शुद्ध पीने का पानी कैसे मिले।

(1800/SK/SAN)

पहले भारत की अधिकांश नदियां बारहमासी थीं और छोटी नदियों में पूरे साल कुछ न कुछ प्रवाह अवश्य होता था। अब नदी क्षेत्रों पर अतिक्रमण भू-माफियाओं ने कर लिया है। बांध के भराव क्षेत्रों पर भी अतिक्रमण हावी हो गया है। राजधानी जयपुर के रामगढ़ बांध पर बहुत लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अतिक्रमण नहीं हट रहा है। गरीब के झोपड़े के लिए अगर हाई कोर्ट आदेश कर दे तो कलैक्टर भी कन्टेम्प्ट की आड़ में रातोंरात झोपड़ा हटा देता है।

माननीय अध्यक्ष: बेनीवाल जी, आपका भाषण अगली बार जारी रहेगा।

सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 2 दिसंबर, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1801 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा, सोमवार, 2 दिसंबर, 2019 / 11 अग्रहायण 1941 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।